हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

18 मार्च, 2015 (द्वितीय बैठक)

खण्ड-1, अंक-9

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 18 मार्च, 2015

पृष्ठ संख्या

विधान सभा समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना - (9)1

(i) लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 61वीं रिपोर्ट

(ii) प्राक्कलन समिति की 43वीं रिपोर्ट

(iii) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की समिति की 38वीं रिपोर्ट

(iv) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की 5वीं रिपोर्ट

(v) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की 6वीं रिपोर्ट

(vi) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की 7वीं रिपोर्ट

(vii) याचिका समिति की 5वीं रिपोर्ट

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण) (9)3

मूल्य :

199

Vidhan Sabha Secretariat * Haryana * Chandigarh
LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 18 मार्च, 2015

(द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में मध्याह्न-पश्चात् 2.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवरपाल) ने अध्यक्षता की।

विधान सभा की समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 61वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती संतोष यादव, लोक उपक्रमों सम्बंधी समिति की चेयरपर्सन, वर्ष 2010-2011 के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2014-2015 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 61वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगीं।

Chairperson, Committee on Public Undertakings (Smt. Santosh Yadav) : Sir, I beg to present the Sixty First Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2014-15 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 2010-2011 (Commercial)

(ii) प्राक्कलन समिति की 43वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री कृष्ण लाल पंवार, प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन, वर्ष 2013-2014 के लिए पर्यटन विभाग के बजट अनुमानों पर वर्ष 2014-2015 के लिए प्राक्कलन समिति की 43वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें।

Chairperson, Committee on Estimates (Shri Krishan Lal Panwar) : Sir, I beg to present the Forty Third Report of the Committee on Estimates for the year 2014-15 on the Budget Estimates for the year 2013-14 Tourism Department.

(iii) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की समिति की 38वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री बलवंत सिंह, अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्थाण के लिए समिति के चेयरपर्सन, वर्ष 2014-2015 के लिए अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्थाण के लिए समिति की 38वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें।

Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes(Shri Balwant Singh) : Sir, I beg to present the Thirty Eighth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2014-15.

(iv) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की 5वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री ज्ञानचंद गुप्ता स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति के चेयरपर्सन, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2005 से मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए पंचायत समिति, मोरनी (जिला पंचकूला) के लेखों पर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2014-2015 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति की पांचवी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें।

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति के चेयरपर्सन (श्री ज्ञानचंद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं निदेशक, स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परिक्षित अप्रैल, 2005 से मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए पंचायत समिति, मोरनी (जिला पंचकूला) के लेखों पर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2014-15 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति की पांचवी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(v) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की 6वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री ज्ञानचंद गुप्ता स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति के चेयरपर्सन निदेशक, स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए नगर निगम, फरीदाबाद के लिए अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए नगर निगम, यमुनानगर के लिए तथा अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए नगर निगम,अम्बाला के लेखों पर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2014-2015 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं समिति की छठी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें।

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति के चेयरपर्सन (श्री ज्ञानचंद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं निदेशक, स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए नगर निगम, फरीदाबाद के लिए अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए नगर निगम, यमुनानगर के लिए तथा अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए नगर निगम,अम्बाला के लेखों पर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2014-2015 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं समिति की छठी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(vi) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की 7वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री ज्ञान चंद गुप्ता स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति के चेयरपर्सन निदेशक, स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तथा अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए जिला परिषद्, कुरूक्षेत्र, अप्रैल, 2011 से मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए, सोनीपत, अप्रैल, 2011 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए जींद तथा अप्रैल, 2010 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए, अम्बाला के लेखों पर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2014-15 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति की सातवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति के चेयरपर्सन (श्री ज्ञानचन्द गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं निदेशक, स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तथा अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए जिला परिषद्, कुरूक्षेत्र, अप्रैल, 2011 से मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए, सोनीपत, अप्रैल, 2011 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए जींद तथा अप्रैल, 2010 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए, अम्बाला के लेखों पर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2014-15 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति की सातवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(vii) याचिका समिति की 5वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास अरोड़ा चेयरपर्सन याचिका समिति वर्ष 2014-15 के लिए याचिका समिति की पांचवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

याचिका समिति के चेयरपर्सन (श्री घनश्याम दास अरोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2014-15 के लिए याचिका समिति की पांचवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब बजट पर चर्चा का पुनरारम्भण होगा।

डॉ. अभय सिंह यादव(नांगल चौधरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं बजट का समर्थन करता हूं। हमारे माननीय वित्तमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 का कल सदन में बजट प्रस्तुत किया। अगर हम माननीय वित्तमंत्री जी के बजट को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से जोड़कर देखें तो महामहिम का जो अभिभाषण है वह सरकार की आधारभूत नीतियों का विवरण होता है कि आगामी वर्ष में सरकार क्या-क्या काम करना चाहती है और बजट उन नीतियों को मूल रूप देने के लिए पैसे की व्यवस्था करता है। बजट में खर्च और आमदनी का विस्तार ब्यौरा होता है। वर्तमान बजट पर कई तरह के विचार सुबह से सुनने को मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि बजट अपने आप में तब तक सार्थक नहीं होता जब तक सरकार की नीयत और नीति स्पोर्ट न करे। वर्तमान बजट में हमारे माननीय वित्तमंत्री महोदय द्वारा हर बात का ध्यान रखा गया है कि राज्य के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का किस तरह से निदान किया जाए। बजट में प्रावधान किया गया है कि हमारे प्रदेश को विकास की राह पर किस तरह से आगे ले जाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक-एक करके कुछ बिंदूओं/पहलूओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। सिंचाई के लिए बजट में पैसे का प्रावधान किया गया है। बजट में जवाहर लाल नेहरू उठान प्रणाली की ओवर हालिंग की बात भी की गई है। इसके लिए बजट में व्यवस्था भी की गई है। अध्यक्ष महोदय, अगर हरियाणा में वर्तमान समय में पानी की उपलब्धता पर दृष्टिपात किया जाये तो आपको एक तरफ तो राज्य के कुछ इलाके में सेम की समस्या नज़र आ रही है वहीं दूसरी तरफ सूखे से न केवल लोग पीड़ित हैं बल्कि पीने के पानी के लिए भी लोग मोहताज़ हैं। मैं समझता हूं कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह पानी का असमान बंटवारा है। मैं उन

[डॉ० अभय सिंह यादव]

कारणों में नहीं जाना चाहता कि जिन कारणों से यह असमानता फैली है लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि हम सभी को पार्टी लाईन से ऊपर उठकर यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि हरियाणा में जो जल का बंटवारा है वह बिलकुल पूर्ण रूप से असमान है और न्यायोचित नहीं है। पिछले काफी लम्बे समय से यहां पर हर बार जब पानी के बंटवारे का जिक्र होता है तो बीच में पहले एस.वाई.एल. का जिक्र आता था लेकिन पिछले 4-5 सालों से अब बीच में हांसी-बुटाना नहर का जिक्र भी आता है। सरकार द्वारा हांसी-बुटाना नहर का निर्माण करके उसमें पानी लाकर प्रदेश में पानी के समान बंटवारे के लिए जो प्रयास किये गये हैं मैं उनके ऊपर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूं मेरे कहने का सीधा सा मतलब यह है कि कई बार हम कुछ बातों का जिक्र केवल मात्र खानापूर्ति के लिए ही करते हैं लेकिन उनके पीछे जो प्रयास होते हैं उन प्रयासों की कमी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. का जहां तक प्रश्न है मैंने पिछली बार भी आपके समक्ष निवेदन किया था कि एस.वाई.एल. के बारे में विभिन्न समय में भिन्न-भिन्न सरकारें इस प्रदेश में रही उन सरकारों की नियत में हमेशा फर्क रहा है। इस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। जब पंजाब सरकार ने रीवर वॉटर एग्रीमैंट को निरस्त किया तो हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ थी। महज़ खानापूर्ति के लिए केन्द्र सरकार को कहकर under article 143 उसका रैफरैंस सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिया गया। जहां तक मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट में रैफरैंस भिजवाने की तब आवश्यकता होती है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई भ्रम की स्थिति होती। इस बारे में दिये गये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई भ्रम नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के बड़े स्पष्ट आदेश थे कि अगर पंजाब सरकार इस नहर को एक निश्चित अवधि में नहीं बनवा सकती तो केन्द्र सरकार अपने स्तर पर इस नहर का निर्माण करवायेगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ और यह मामला साल-दर-साल से वहां पर लटक रहा है। इसके अलावा जहां तक हांसी-बुटाना की बात है यह ठीक है कि यह एक अच्छा प्रयास था। यह भी मैं कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में पानी के समान वितरण की तरफ एक कारगर स्टैप था। मैं समझता हूं कि भाखड़ा-रावी-ब्यास के पानी के सिस्टम को जब जवाहर लाल नेहरू कैनाल के सिस्टम से जोड़ दिया जायेगा तो सम्भवत : हमारे इलाके के हिस्से में और दक्षिणी हरियाणा के जो दूसरे इलाके हैं उनके हिस्से में भी कुछ पानी आयेगा। पीछे नेता प्रतिपक्ष भी और सी.एल.पी. लीडर भी दोनों कह रहे थे कि नहरों के आखिरी छोर तक और हर खेत में यह सरकार पानी कैसे पहुंचायेगी। इस बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी, हमारे कृषि मंत्री महोदय ने भी और हमारे वित्त मंत्री महोदय ने भी बार-बार यह स्पष्ट किया है कि एस.वाई.एल. और हांसी-बुटाना नहर के मुद्दे हम प्रत्येक स्तर पर बड़ी गम्भीरता से उठायेंगे। इसके साथ-साथ इस संबंध में एक और विकल्प भी हमारे सामने मौजूद है। यमुना नदी में जो बरसात के समय में पानी आता है बरसात के समय का जो यमुना नदी में हाईयेस्ट डिस्चार्ज होता है उसमें जो मुझे एक ताज़ा आंकड़ा मिला है उसके मुताबिक 17 जून, 2014 को यमुना में 8 लाख 6 हज़ार क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज रिकार्ड किया गया था। इसका असर यह हुआ कि हरियाणा और यू.पी. के यमुना के साथ लगते सभी इलाकों में अलार्म बज गया था कि यमुना में बाढ़ आने का खतरा है और इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा और यू.पी. के यमुना के आस-पास के सभी इलाकों को खाली करवा लिया गया था। दूसरी तरफ जब लीन सीजन होता है तो वही डिस्चार्ज 2-3 लाख क्यूसिक पर रह जाता है। इसी तरह से पोल्यूशन की समस्या भी है। जो दूसरे दिल्ली

और आसपास के शहर यमुना नदी के किनारे बसे हैं उनका गंदा पानी यमुना में प्रदूषण फैलाता है। लीन सीजन में यमुना की सफाई नहीं होती क्योंकि उस समय यमुना में पानी का फ्लो कम होता है उस सफाई को नियमित करने की जरूरत है। यमुना की हमारी 3 परियोजनाएं यमुना और इसकी सहायक ट्रिब्यूट्रीज पर प्रस्तावित हैं। रेणुका बांध और किशाऊ बांध दोनों यमुना की ट्रिब्यूट्रीज पर प्रस्तावित हैं। रेणुका बांध यमुना की एक गिरी रीवर ट्रिब्यूट्रीज है, उस पर बनना है और इसकी ऐस्टीमेटिड कैपेसिटी 1.46 एम.ए.एफ. है। इसमें कुछ काम भी हो चुका है। काम होने का मतलब यह है कि इसकी इन्वॉयर्नमैंट क्लीयरैंस हो चुकी है और अब वह शायद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चैलेंज हुआ है। कुछ हद तक इसकी लैंड एक्विजीशन की कार्यवाही भी हो चुकी है। इसी तरह से जो किशाऊ बांध है यह टोन्स रीवर पर बनना है और इसकी ऐस्टीमेटिड कैपेसिटी 1.073 एम.ए.एफ. है। इसी तरह से लखवार और व्यासी बांध यमुना मेन नदी पर बनने हैं। अगर ये तीनों-चारों बांध निर्मित हो जायें, जिसके लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है जिसके लिए हम प्रयास करेंगे तो हमे यमुना नदी में कुछ फालतू पानी मिल जायेगा उससे पूरे मेवात और अहीरवाल क्षेत्र के सूखे इलाके हैं उनमें और ज्यादा पानी दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं लैंड एक्विजीशन का भी जिक्र करना चाहूँगा। हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत सीनियर लीडर डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी किसानों का जिक्र कर रहे थे। एक कवि हृदय बड़े भावुक तरीके से किसानों की दशा का वर्णन कर रहे थे। मुझे भी उनकी बात सुन कर बहुत अच्छा लगा और मैं समझ रहा था कि उनके दिल में किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा दर्द है। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक विपत्ति जैसे ओले पड़ना, बारिश होना किसानों के लिए बहुत ही पीड़ा दायक होता है। जब पकी हुई फसल पर ओले पड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके सामने रखी हुई खाने की थाली उठा ली हो। वह जो नुकसान होता है वह सीजन का नुकसान होता है। अध्यक्ष महोदय, सभी सभासद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जमीन किसान की धरोहर होती है जो पीढी-दर-पीढ़ी और सदियों से बुजुर्गों से एक से दूसरे तथा दूसरे से तीसरे को दी जाती है। जब किसी उद्योगपति की मौत होती है तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनमें फैक्ट्रियों का और मिलों का बंटवारा होता है लेकिन जब किसी किसान का निधन होता है तो उसके वारिसों को जमीन का टुकड़ा मिलता है जो वह अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संजोकर रखता है। जब उस जमीन का हक उससे जबरदस्ती ही छीन लिया जाये जो उसकी 7 पीढ़ियों की धरोहर हो, तो मैं नहीं समझता कि किसान के साथ इससे बड़ा और कोई अन्याय हो सकता है। डॉ. रघुवीर सिंह कादियान लैंड एक्विजीशन एक्ट के बारे में भी काफी कुछ कह रहे थे। आज सुबह जब सदन शुरू हुआ तो अलग-अलग जिलों से जिस तरह के मामले सदन के समक्ष लाये गये तो ऐसा लग रहा था जैसे इस प्रदेश में जमीनों की लूट मची हुई हो, कि किसानों से जमीनें छीन लो और छीन कर और कहीं दे दो। लैंड एक्विजिशन एक्ट का जिस तरह से, जिस बेदर्दी से दुरूपयोग हुआ मैं उसको दर्दनाक कहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गुड़गांव में मेरी पोस्टिंग थी उस समय मैं वहां ए.डी.सी. था उस समय मेरे दोस्त का रिश्तेदार मेरे पास आए उनका गुड़गांव के पास गांव है। उसने मुझे आकर कहा कि हरियाणा एक बहुत बड़ा बिल्डर उसकी जमीन को लेने के लिए आया है और वह 5 करोड़ रुपये पर एकड़ दे रहा है लेकिन मैंने उससे 6 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मांगे हैं। मैंने उस दिन उसको मजाक में कह दिया कि भाई दे दे फिर कभी ऐसा न हो जबरदस्ती देनी पड़ जाए। आप विश्वास करना फिर दो-तीन महीने बाद वही आदमी मेरे पास

आया और कहने लगा कि भाई धर्म संकट में फंस गया मैंने कहा कि क्या बात हुई वह कहने लगा कि मैंने पहले तो उसको मना कर दिया और अब मेरी जमीन को ग्रीन बैल्ट में डाल दिया। वह कहता है अब उस जमीन को कोई किसी भी कीमत में नहीं पूछता। मैंने कहा अगर दोबारा कोई आए तो उसको दे देना वह अपने आप ग्रीन बैल्ट से रैजीडैंसियल जोन में करवा लेगा। उस आदमी को ओने-पोने दाम पर अपनी वह जमीन बेचनी पड़ी। लैंड एक्विजिशन ऐक्ट में कभी यह नहीं होता कि सैक्शन 4 कर दिया। हम भी कलैक्टर रहे हैं हमनें भी कई बार लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जमीनों को अधिग्रहण किया है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा कि सैक्शन-4 कर दिया वह जमीन किसी ने खरीद ली उसको रिलीज कर दी , उसको लाईसैंस भी दे दिया। सर, अगर सैक्शन-4 के बाद में सैक्शन-6 तक वह जमीन उसके पास रह गई और सैक्शन-6 के बाद उसने जमीन छोड़ दी। आज जब सुबह जब बहस हो रही थी तो उस समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि पहले जिन किसानो की जमीन छोड़ी गई हैं उनसे यह तो पता कर लो कि जिस वक्त वह जमीन छोड़ी गई थी उस समय वह जमीन उन किसानों की थी भी या नहीं। अध्यक्ष महोदय, जमीनें तो तब छोड़ी गई थी जब किसान के हाथ से निकल गई थी। मैं प्रार्थना करूंगा और यह उम्मीद करूंगा कि किसानों के लिए जो दर्द हो तो वह वास्तविक हो। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब ओलावृष्टि होती है तो ओलावृष्टि के समय में हम कहते हैं कि हम जमींदारों की बहुत मदद कर रहे हैं हमने एक महीने में मुआवजा दे दिया हमने दो महीने में मुआवजा दे दिया लेकिन जो मुआवजा दिया जाता है उसमें जो खराबे की प्रसन्टेज होती है वह जब पटवारी स्पैशल गिरदावरी करने के लिए जाता है तो वह जितना खराबा लिखता है उसी के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। अब किसान को तो पता है जिस जमीन में 50 मण गेहूं होना था उसमें अब 20-22 मण भी गेहूं नहीं होगा। लेकिन पटवारी का जो अंक गणित है उसमें किसी का 25 प्रतिशत खराबा दिखाता है और किसी में 30 प्रतिशत खराबा दिखाता है। एक मार तो किसान को वहां पड़ जाती है। दूसरी हमारी जो मुआवजा राशि देने की कम्पनसेशन की लिमिट है वह 10 हजार रुपये पर एकड़ की है। 10 हजार रुपये में आजकल जो भाव है और जो पैसे की कीमत है वह 10 हजार रुपये जिसका 100 प्रतिशत नुकसान पूरे एकड़ में हो, तब मिलते हैं। किसान की फसल खराबे की परसैन्टेज के हिसाब से कैल्कुलेट करते है तो वहीं पर एकड़ के हिसाब से उसको ढ़ाई-तीन हजार रुपये प्रति एकड के मिलते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है वित मंत्री जी यहां बैठे हैं इसके लिए चाहे किसी बीमा कम्पनी से कोई अरेंजमैंट किया जाए। अगर किसान किसी कारणवश बीमे की किस्त नहीं दे पाता तो सरकार यह फैसला कर ले कि सरकारी खजाने से उसकी बीमे की किस्त की अदायगी कर दी जाए। अगर किसान का दुर्भाग्यवश ऐसा नुकसान होता है तो ऐसा इन्तजाम किया जाए कि किसान का जो नुकसान होता है खराबा होता है उसका पूरा मुआवजा मिल जाए। जब आसमान में बिजली कड़कती है तो किसान के दिलों की धड़कन पता नहीं कितने गुना तेज हो जाती है क्योंकि मैं बचपन से ही न केवल किसान का बेटा हूं बल्कि मैंने खुद अपने हाथों से हल भी चला रखा है। इसलिए मुझे पता है कि किसान को कितना दर्द होता है। जहां तक विकास की बात है जब से सैशन शुरू हुआ है तब से विकास में असन्तुलन की बात बहुत हो गई और यह सच्चाई भी है। इसलिए मेरा सरकार से सुझाव भी है और एक निवेदन भी है कि किसी भी राज्य की जो भौगोलिक स्थिति होती है वह उस राज्य का एक संसाधन होता है। हमारे राज्य में बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ या दूसरे जो सोयल वैल्थ हैं वह हमारे राज्य में चाहे ना हो लेकिन हमारे को एक बहुत बड़ा फायदा है कि

अगर हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को केन्द्र मानकर एक चाप लगाओ तो 150 किलोमीटर के रेडियस में तो हमारा दो तिहाई से ज्यादा हरियाणा उसमें कवर हो जाता है और राष्ट्रीय राजधानी के इतने नजदीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जितने नेशनल हाईवे बने हुए हैं। नारनौल के पास से 2 नेशनल हाईवे राजस्थान की ओर से दो महीने पहले ही निकाले गये हैं। इसके साथ ही हम अध्यक्ष महोदय, यदि इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर भी बना लें जैसाकि माननीय वित्त मंत्री जी एक इंडस्ट्रीयल पॉलिसी बना रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि अगर औद्योगिक नीति बनाते समय एक इन्डस्ट्रीयल कोरीडोर साउथ में दे दिया जाये, एक नॉर्थ में दे दिया जाये, एक वैस्ट में दे दिया जाये और ईस्ट में तो पहले से ही इन्डस्ट्रीज इस्टैब्लिश हैं। इस राज्य में समेकित विकास के लिए हमें हर क्षेत्र का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से फीलिंग है कि जो राष्ट्रीय राजधानी के अति नजदीक क्षेत्र है। जिसका पिछले कुछ वर्षों से बहुत दोहन हुआ है। अंग्रेजी के प्ले में एक लाईन थी जो इस प्रकार है "There is a tide in the affairs of men."

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप दो मिनट में वाईड-अप कीजिए।

डॉ० अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जब प्रॉपर्टी का एक बूम हमारे राज्य में आया था, उस समय हमारे राज्य के फेवर में एक ज्वार आया था और उस समय राजकोष में कितना ही धन जमा किया जा सकता था। जिस तरीके से सी.एल.यू. दी गई तो उसे व्यवस्थित ढंग से डिवैल्पमैंट भी किया जाता या उसे व्यवस्थित ढंग से राजकोष के लिए उपयोग किया जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि हरियाणा का हजारों करोड़ रुपये का कर्ज और उसका ब्याज चुकाने के लिए चाहे वह कोई भी सरकार आती है उसको बजट का प्रावधान करना पड़ता है। जैसे सुबह ही सी.एल.पी. लीडर मैडम जी कह रही थी कि सरकार ने बजट की व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक की है। मैडम जी, बजट में प्रावधान इसलिए अधिक करना पड़ता है क्योंकि ब्याज भी अधिक देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, उस समय सी.एल.यू. का पैसा सही तरीके से राजकीय खजाने मे आ जाता। आज देश और राज्य की बहुत अच्छी भौगोलिक स्थिति है उसके मुताबिक इस स्थिति का पूरा आकलन अवश्य किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हम सभी माननीय सदस्य मिलकर पार्टी लाईन से हट कर सोचें कि हरियाणा प्रदेश का मिलकर विकास करें। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शैक्सपीयर की लाईन को कोट किया है "There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood, leads on to success." Please, now there is a tide. Please, take flood on and leads on to success.

Dr. Abhey Singh Yadav : That's I am indicating.

श्री कृष्ण लाल पंवार (इसराना) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं। वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2015-2016 का जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट प्रस्तुत करते समय सभी समुदाय के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या कर्मचारी हो लेकिन बजट में काफी सदस्यों ने पावर के बारे में चिन्ता जताई है और वास्तव में पावर एक नेसेस्टी है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों ने पावर के मामले में जिस प्रकार की अनियिमिताएँ बरती हैं, वह में

[श्री कृष्ण लाल पंवार]

आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आज वित्त मंत्री जी ने अनुमान बजट में 2015-16 में 6546.91 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। जिसमें 917.50 करोड़ रुपये की राशि योजनागत आबंटन में शामिल है जो पिछली योजना के अनुमानों में 45.25 प्रतिशत से अधिक है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ।

15-00 बजे अध्यक्ष महोदय, मेरे इसराना विधान सभा क्षेत्र में पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट आता है जिसमें 800 मैगावाट का सुपर क्रीटिकल थर्मल पॉवर प्लांट लगाने की योजना सरकार ने बनाई है। यह योजना इसलिए बनाई है क्योंकि पूर्व सरकारों ने इसकी तरफ कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया था। अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकारें बिजली के प्लांट बंद रखने में विश्वास रखती थी लेकिन वर्तमान सरकार बिजली के नये प्रोजैक्ट लगाने में विश्वास रखती है। फरीदाबाद के अन्दर 62.4 मैगावाट के 4 संयंत्र पिछली सरकार ने बंद कर दिये और उसके स्थान पर नये संयंत्र लगाने की कोई योजना नहीं बनाई। अध्यक्ष महोदय, पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट के अन्दर 8 यूनिट हैं। उनमें से 110-110 मैगावाट क्षमता की पुरानी और अक्षम इकाई नं. 1 से 4 वर्ष 1979 में लगी थी, वह इकाई पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण उनका पी.एल.एफ. बहुत कम है। एक यूनिट बिजली प्राप्त करने के लिये 700 से 800 ग्राम कोयला कंज्यूम होता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो नया 800 मैगावाट का सुपर क्रीटिकल थर्मल पॉवर प्लांट 4 हजार करोड़ रुपये की लागत से लगाने की योजना बनाई है, उसमें एक यूनिट बिजली प्राप्त करने के लिये 400 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक कोयले की खपत होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पूर्व सरकार ने यमुनानगर के अन्दर जहां आपका भी विधानसभा का क्षेत्र लगता है, उसमें 300-300 मैगावाट के दो यूनिट दीन बन्धु सर छोटू राम के नाम से लगायें और उसके अन्दर चाइनीज मशीनरी का प्रयोग किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं आपके माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइनीज मशीनरी लगाने के बाद भी वे प्लांट चलते नहीं थे। जब मैं विपक्ष में था, मैंने बार-बार यह मुद्दा उठाया था। आज यमुनानगर दीन बन्धु सर छोटू राम पॉवर प्लांट का जनरेटर का इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिपिटेटर टूट कर नीचे गिरने से रोटर खराब हो गया है। जो चाईना से लगभग डेढ़ साल बाद आया था। 300 मैगावाट का जो एक संयंत्र चलाता था, वह डेढ़ साल तक बंद रहा। इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिपिटेटर का रोटर टूटने से एक साल फिर बंद रहा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से खेदड़ के अन्दर भी 600-600 मैगावाट के दो प्लांटों में चाईनीज मशीनरी लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, चालू करने के बाद टर्बाइन की फाउण्डेशन वाईब्रेशन होने के कारण कई सालों से बंद पड़ा रहा और रोटर खराब हो गया फिर चाइना से लाया गया उसके बाद फिर खराब हो गया। अध्यक्ष महोदय, अगर इन यूनिटों में कोई भी तकनीकी खराबी आती है तो चाइना से ही इंजीनियर बुलाये जाते हैं क्योंकि इंडियन इंजीनियर तो इन प्लांटों को ठीक ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देता हूँ कि जिस प्रकार से 4 हजार करोड़ रुपये की लागत से 800 मैगावाट सुपर क्रीटिकल थर्मल पॉवर प्लांट लगाने की सरकार की योजना है वह किसी और कम्पनी से लगवाने की बजाए हिन्दुस्तान की सबसे अच्छी बी.एच.ई.एल. कम्पनी से ही लगवाया जाये क्योंकि इस कम्पनी ने जितने भी प्लांट लगाए हैं उनका पी.एल.एफ. शत प्रतिशत रहा है। अध्यक्ष महोदय, पानीपत के अन्दर 250-250 मैगावाट के दो प्लांट बी.एच.ई.एल. कम्पनी ने लगाये थे, जिनका पी.एल.एफ. शत प्रतिशत रहा है। अध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि पहले वाली कम्पनी जिन्होंने प्लांट लगाये हैं उनको टैंडर में ही शामिल न किया जाये। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार बहुत बड़ी-बड़ी एडवरटाईज़मैंट करती थी कि हमने झांड़ली के अन्दर 1320 मैगावाट का सुपर थर्मल पॉवर प्लांट लगाया है, जबकि हरियाणा का उस प्लांट में एक प्रतिशत भी हिस्सा नहीं है क्योंकि वह चाईनीज कम्पनी है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने इसी प्रकार से इस कम्पनी से 660 मैगावाट के दो यूनिट इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल प्लांट और 500-500 मैगावाट के 3 यूनिट लगाये हैं। सरकार ने बहुत ढिंढोरा पीटा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस सरकार ने की है लेकिन अध्यक्ष महोदय, असलियत यह है कि इसमें 50 प्रतिशत हिस्सा एन.टी.पी.सी. का है, 25 प्रतिशत हिस्सा दिल्ली का है और 25 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा का है। उसके बाद यदि सरकार कोशिश करे तो 750 मैगावाट बिजली में से 15 प्रतिशत हरियाणा सरकार को मिलेगी।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सदन में बार-बार थर्मल पावर प्लांट की चर्चा कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि क्या इन्हें इस बात का दुख है कि प्रदेश में इतने बड़े-बड़े थर्मल पॉवर प्लांट क्यों लगे हुए हैं ? मेरे विधानसभा क्षेत्र में झाड़ली पॉवर प्लांट लगा था। (शोर एवं व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने दीजिए। माननीय सदस्य श्री कृष्ण लाल पंवार जी ने इस बात को बार-बार उठाया है। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो पॉवर प्लांट लगे हैं - एक है झाड़ली पॉवर प्लांट और दूसरा है खानपुर थर्मल पावर प्लांट। मेरा क्षेत्र पहले बिल्कुल रेतीला होता था और आज वहां पर पूरी तरह से जंगल में मंगल हो रहा है। आज वहां पर टाऊनशिप डिवैल्प हो चुकी है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सिक्योरिटी बेहतर हो गई है, अच्छी दुकानें बन गई हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है और लोगों को बेहतर बिजली भी मिल रही है। मैं कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्य सदन में गलत आंकड़ें पेश कर रहे हैं। मेरा विधानसभा क्षेत्र झज्जर एन.सी.आर में होने के बावजूद पिछड़ा हुआ इलाका हुआ करता था। हमारी सरकार के समय में इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। अगर किसी क्षेत्र में इतने बड़े-बड़े प्लांट आते हैं तो इनके साथ तरक्की और खुशहाली भी आती है। माननीय सदस्य को इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या गीता भुक्कल जी हमारी बहन हैं और हम इनका सम्मान करते हैं कि इन्होंने रेतीले इलाके में पॉवर प्लांट लगाए हैं लेकिन इन प्लांटों में हरियाणा का एक भी कर्मचारी नहीं है। इन प्लांटों पर चाइनीज कम्पनी का कंट्रोल है और क्षेत्र को बिजली भी यही कम्पनी दे रही है। इन प्लांटों में सारे कर्मचारी एन.टी.पी.सी. और चाइनीज कम्पनी के ही हैं। अगर ये इसे सही नहीं मानती तो साबित कर दें कि इन प्लांटों में हरियाणा का एक भी कर्मचारी काम कर रहा है। हमें चाईनीज कम्पनी से कंट्रोल्ड बिजली मिल रही है। बात जहां तक नौकरियों की है तो इनमें चाइना के ही कर्मचारी लगे हुए हैं। (विघ्न)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा को तो सिर्फ राख मिलती है, बिजली तो दिल्ली को मिल रही है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं मौजूदा सरकार की सराहना करता हूं। भारत सरकार ने डायरेक्शन दी है कि कंडम हो चुके पानीपत थर्मल प्लांट की 1 से 4 यूनिट का कोयला आप किसी और जगह यूज कर सकते हैं। इसलिए हरियाणा गवर्नमैंट ने योजना बनाई है कि 800 मैगावाट थर्मल प्लांट के अंदर इस कोयले को ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी प्रकार से

[श्री कृष्ण लाल पंवार]

झारखण्ड के अन्दर कल्याणपुर बादरा यू.पी. में हरियाणा की एक कोल माइन है। पूर्व सरकार ने इसे शुरू करने की कोई कोशिश नहीं की लेकिन यू.पी. सरकार ने हरियाणा सरकार को लीडिंग दी कि आप इस माइन को चालू करें। इस माइन से हमें 102 मिलियन टन कोयला प्राप्त होगा। जब यह माइन चालू हो जाएगी तो इससे एक नया 8 सौ मेगावॉट का प्लांट हम स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार से एम.पी. में महारामान जगह पर हरियाणा सरकार की एक माइन थी। वह बहुत अच्छी माइन थी। उसका कोयला बहुत अच्छा था। लेकिन पूर्व हरियाणा सरकार ने उसको चालू नहीं किया तब केंद्र सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। अब वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रधानमंत्री जी से इसे चालू करने की बात की है। इस पर प्रधानमंत्री अब राजी हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम महामारन एम.पी. की कम्पनी को दोबारा अलॉट करेंगे और इसे दोबारा शुरू करने के प्रयास करेंगे। इससे हमें 9 सौ मिलियन टन कोयले का आऊटपुट प्राप्त होगा। इससे हम 8 सौ मेगावॉट के दो यूनिट लगा सकते हैं। इसी प्रकार से पूर्व की सरकार ने एक बनी हुई कोल इंडिया कम्पनी को शुरू नहीं किया। इनके समय में नदी कोल कम्पनी थी जिसका कोयला बहुत घटिया दर्जे का था और वह कोयला हिसार को दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार के द्वारा केवल पैसा कमाने के लिए इंडोनेशिया से कोल मंगाया गया था। अच्छे कोयले की कैलोरिफिक वॅल्यू 7 हजार से ज्यादा होती है परंतु जो कोयला हमें दिया गया उसकी कैलोरिफिक वैल्यू 4805 थी और सरकार ने उसका पूरा पैसा दिया था। इसके अलावा (110x4= 440 MW)चार यूनिट का जो कोल माइन से कोयला आता है जिनकी कैलोरिफिक वैल्यू 4800 होनी चाहिए लेकिन 3200 से 3000 तक कैलोरिफिक वैल्यू मिल रही थी और इसके लिए भी पैसा पूरा दिया गया था। इसी प्रकार से यूनिट नं0 5,6,7 और 8 में भी कैलोरिफिक वैल्यू 4000 थी उसमें 3000 से 3500 तक कैलोरिफिक वल्यू आई है। इसके लिए भी हमने पैसा पूरा दिया था। इसी प्रकार से हमारे पानीपत के प्लांट में और खेदड़, हिसार में काफी स्पेस है और वहां पर सरकार द्वारा 70-70 मैगावाट के सौलर ऊर्जा प्लॉट लगाने की योजना बनाई जा रही है जिसके बारे में एक्सरसाईज चल रही हैं। वहां पर सोलर के नये प्लॉट लगायेंगे। इसी प्रकार से बिजली निगम के पास जो सब स्टेशन्ज है उनमें से 70 से 75 प्रतिशत सब स्टेशन ट्रांसफारमर्ज ओवरलोडिड हैं उनकी इम्प्रूवमैंट करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। इसके लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत जहां पर सब स्टेशंज नहीं हैं वहां पर सब स्टेशंज लगायेंगे और जहां पर ट्रांसफारमर्ज इम्प्रूव करने हैं तो उनका इम्प्रूवमैंट करेंगे। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की मन्शा है कि जहां पर 250 इम्पॉयर से ज्यादा ट्रांसफारमर्ज ओवर लोडिड हैं उन सभी को अपग्रेड किया जायेगा। सभी सदस्य कहते हैं कि सब जगह पर बिजली की शॉर्टेज है। सर्दियों में हरियाणा प्रदेश को लगभग 6500 मैगावॉट बिजली की आवश्यकता होती है और गर्मियों के अन्दर हरियाणा प्रदेश को 9000 मैगावॉट बिजली की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने 1000 मैगावॉट अतिरिक्त बिजली का पहले ही प्रबन्ध कर लिया है और आने वाले दिनों में प्रदेश वासियों को बिजली के बारे में कोई कठिनाई नहीं आयेगी। पिछली सरकार के समय में सैल्फ फाईनैंस स्कीम के द्वारा 16 के.वी. के ट्रांसफारमर्ज किसानों को दिए थे और उन ट्रांसफारमर्ज की तीन साल की गारन्टी थी लेकिन वे ट्रांसफारमर्ज तीन साल से पहले ही जल गये थे और किसानों को उसके बाद कोई ट्रांसफारमर्ज नहीं मिले क्योंकि जिनसे वे ट्रांसफार्मर खरीदे थे वे काम छोड़ कर चले गये थे। अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पर विचार करके उन किसानों को 16 के.वी. की बजाए 25 के.वी. के ट्रांसफारमर्ज दे, जिससे उन किसानों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। इसके साथ ही अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की मांगों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। बुटाना कैनाल से न्यू उरलाना माईनर निकलती है जिसकी टेल कुराना गाँव के पास पड़ती है उसे बने हुए 15 साल हो गये हैं लेकिन आज तक उस माईनर का पानी टेल तक नहीं पहुंचा है क्योंकि उस माईनर का लेवल ठीक नहीं है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस माईनर का लेवल ठीक करके टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जाए। इस लुहारी माईनर की टेल अहर गांव तक पड़ती है उसको जिला सोनीपत के गाँव छतैहरा तक बढ़ाई जाए और इन सभी गाँवों को पानी दिया जाए। इन 10-15 गाँवों के लोगों ने इस बारे में एक रेजोल्यूशन भी दिया था। मतलौडा ब्लॉक हैडक्वार्टर है वहां पर आई.टी.आई. नहीं है उस गाँव में आई.टी.आई. खोली जाए क्योंकि उसके आसपास 24 गाँव लगते हैं। पानीपत जिले में तीन तहसील हैं और मतलौडा एक सब तहसील है और इस सब तहसील के नीचे 34 गाँव आते हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मतलौडा सब तहसील को तहसील बनाया जाए। इसराना में एक पी.एच.सी. है जोकि पंचायत घर की बिल्डिंग में चल रही है। जबकि पंचायत ने पी.एच.सी. के लिए जमीन भी दे रखी है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसराना में पी.एच.सी. बनाई जाए। इसी प्रकार से पानीपत से रेवाड़ी का रास्ता जो कि एन.एच. 71 पिछली सरकार के समय में बनाया गया था उस समय हमारे इलाके के साथ बहुत भेदभाव किया गया था। रोहतक के किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी, उन किसानों को 39 लाख रुपय प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया। पानीपत जब शुरू होता है तो वहां से मेरा विधान सभा क्षेत्र इसराना शुरू होता है, वहां की जमीनें बड़ी फर्टाइल जमीन है हमारे क्षेत्र के किसानों को केवल 31 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया। मेरा विधान सभा क्षेत्र- इसराना एक ब्लॉक है, कस्बा है तथा छोटे स्तर का एक हैडक्वार्टर है। इसराना से होकर जब रोहतक जाते हैं तो इसराना में बाई-पास न होने की वजह से ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या हो जाती है। रोहतक व सोनीपत जिलों में जितने भी गाँव इस प्रकार से आते हैं, उन सब में बाई-पास बने हुए हैं। इसराना में एक अनाज मण्डी बनी हुई थी लेकिन ओवरब्रिज बनने से अब वह अनाज मण्डी शतप्रतिशत् बंद हो गई है। माननीय कृषि मंत्री जी इस समय सदन में बैठे हुए हैं। इस बारे में मैंने एक आढ़तियों का डैलीगेशन भी इनसे मिलवाया था। मेरी आपके माध्यम से उनसे प्रार्थना है कि इसराना की अनाज मण्डी को वर्तमान स्थान से शिफ्ट किया जाये क्योंकि अभी गेहूं की फसल आने वाली है और किसानों को अपनी गेहूं की फसल डालने में दिक्कत आयेगी। इस परिस्थिति में उस क्षेत्र के किसान अपनी गेहूं हाईवे पर एन.सी.कॉलेज के सामने डालने पर मजबूर हो जायेंगे परिणामस्वरूप मेन रास्ता बंद हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य परिवहन मंत्री श्री कंबोज साहब सदन में इस समय बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि इसराना में बस स्टैंड का रास्ता शतप्रतिशत् बंद पड़ा है। बेशक आप इसका सर्वे करवा लें। मेरी प्रार्थना है कि इस बस स्टैंड को वहां से शिफ्ट किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर बोलना चाहूंगा। इस सदन में मैं 20 वर्ष तक विपक्ष में बैठा रहा हूं। (विघ्न) कादियान साहब, बस स्टैंड तो चला था जिसके बारे में मैंने सदन में आवाज उठाई थी लेकिन ओवरब्रिज बनने से उसका रास्ता बंद हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में जिक्र कर रहा था कि मेरे हल्के के एक बाल जाटान गाँव के सरकारी स्कूल में

[श्री कृष्ण लाल पंवार]

बच्चों की संख्या भी पूरी है, बिल्डिंग भी पूरी बनी हुई है तथा इस स्कूल को सुंदरता के क्षेत्र में स्टेट अवार्ड भी मिले हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस स्कूल को अपग्रेड करके 10+2 स्तर का विद्यालय बनाया जाये। इसी प्रकार से खन्ना गाँव के स्कूल को भी अपग्रेड करके 10+2 स्तर का विद्यालय बनाया जाये। पानीपत जिले के सिठाना गाँव में 90-95 प्रतिशत् गरीब लोग रहते हैं, वहां की लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर किसी दूसरे गाँव में नहीं जा सकती हैं। इस गाँव के सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या भी पूरी है, बिल्डिंग भी पूरी तरह निर्मित है। मेरा अनुरोध है कि इस विद्यालय को अपग्रेड करके 10+2 स्तर का विद्यालय बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, नौल्था गाँव का लड़कियों का स्कूल भी अपग्रेड करके 10+2 स्तर का विद्यालय बनाया जाये। मेरे हल्के में माण्डी गाँव बहुत बड़ा गाँव है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि माण्डी गाँव के लड़कियों के सरकारी स्कूल को अपग्रेड करके 10+2 स्तर का विद्यालय बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री कुलदीप बिश्नोई(आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में प्रस्तुत बजट प्रस्तावों पर सुझाव देने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं न तो बजट के पक्ष में और न ही विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी वर्तमान सरकार को बने हुए केवल 4 महीने ही हुए हैं। इसलिए हमें इस सरकार को benefit of doubt अवश्य देना चाहिए। (विघ्न) किसी सरकार के कार्यकलापों का आकलन करने के लिए 4 महीने का समय बहुत कम होता है। मैं ट्रेजरी बैंचिज़ के चारों तरफ़ बैठे माननीय सदस्यों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि इस बार हमें बजट पर सरकार को केवल जन-हितैषी सुझाव ही देने चाहिए। (थंपिंग) तथा अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम इनसे पूछताछ भी करेंगे व गरमागर्मी भी करेंगें (हंसी) मेरा तो इनके साथ पुराना साथ है। मेरे साथ अच्छी करी भी कौन्या ना इन्होंने। इस संबंध में मुझे एक शेर याद आ गया। मेरी पीठ पर जो जख्म है, वह अपनों की निशानी है, छाती मेरी आज भी दुश्मनों के लिए तैयार खड़ी है। (थंपिंग) सदन में उपस्थित हम सभी माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य बनता है कि बजट प्रस्तावों पर सरकार को अच्छे सुझाव दें क्योंकि बहुत उम्मीदों और अपेक्षाओं से हमारे हल्के की जनता ने हमें विधान सभा में चुनकर भेजा है कि जो अन्याय और भेदभाव पिछली सरकार के समय में उनके साथ हुआ है उससे निजात मिल सके। अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं उनको उनके इस सदन में प्रथम बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह काफी चैलेंजिंग बजट है। सरकार के सामने बहुत चुनौतियाँ हैं कि यह जो बजट पेश किया गया है उसमें जो योजनायें बनाई गई हैं तथा जो आँकड़े पेश किये गये हैं, उनको यह सरकार कैसे पूरा करेगी ? यह तो कैप्टन साहब अपने जवाब में या आने वाला समय ही बता पायेगा लेकिन मैं अपनी पार्टी की ओर से सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी विपक्ष की जिम्मेवारी होने के नाते जिस प्रकार की भी मदद सरकार हमसे चाहेगी, वह हम देंगे चाहे मेरा दो बार पार्लियामैंट का तजुर्बा हो, चाहे मेरा तीन बार विधानसभा का तुजर्बा हो, या हरियाणा की जनता के बीच जो मैंने संघर्ष किया उसका तजुर्बा हो, चाहे मेरी रथ यात्रा का तजुर्बा हो, चाहे मेरी ट्रैक्टर यात्रा का तजुर्बा हो या फिर कुलदीप बिश्नोई चले चौपाल की ओर कार्यक्रम का तजुर्बा हो मुझे हर शहर के हर गांव में कई बार जाने का अवसर मिला है इसलिए हरियाणा की जनता के दु:ख दर्द को मैं नजदीक से समझता हूं और मैंने महसूस भी किया है। सरकार जो

भी सेवाएं मुझसे चाहेगी वह मैं देने के लिए तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, हम सभी मैम्बर्ज यहां बैठे हैं हम सबकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, हमारे तौर तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन हम सबका लक्ष्य एक समान विकास एक समान रोजगार होना चाहिए । कुछ वायदे आपने मेरे साथ भी किए थे और मैं समझता हूं कि सारी पार्टियां वायदे करती रहती हैं लेकिन मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो वायदे हम लेकर चले थे और सरकार बनाने में कुछ योगदान तो हमारा भी रहा है इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारे उस सहयोग की लाज जरूर रख लेना।(विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान देश के संविधान की ओर ले जाना चाहूंगा। प्रिएम्बल की तीन पंक्तियां हम हमेशा सुनते रहे हैं, जो हमें शुरू से स्कूल में पढ़ाई जाती रही हैं, कालेज में भी पढ़ाई गई हैं। इन तीन पंक्तियों का जो निचोड़ है मैं यहां जरूर बताना चाहूंगा The Preamble of the Constitution reads that to secure to all his citizens justice, social, economic and political, liberty of thought & expression, belief, faith and worship, the equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार जो भी ऐक्शन ले अगर वह इसी दायरे में आकर ले तो सारे काम सम्भव हो सकते हैं। हरियाणा की जनता बजट के आंकड़ों को नहीं समझती है लेकिन अपने घर के बजट को जरूर समझती है। वित्त मंत्री जी का कल जो बजट आया है उसे हरियाणा की जनता ने टी.वी. पर सुना होगा और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बात समझ आई होगी। हालांकि वित्त मंत्री जी ने बहुत बढ़िया बजट पेश किया लेकिन मूलभूत सुविधाओं के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं अक्सर मुख्यमंत्री महोदय जी का ब्यान पढ़ता हूं तथा और भी मंत्रियों के ब्यान मैं देखता हूं। कोई भी सरकार आती है तो कहती है कि हम इतनी नई यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, इतने नए कालेजिज खोलेंगे, हम विदेशों से टीचर्स लेकर आएंगे। यह सब करना चाहिए अच्छी बात है मैं इसका विरोध नहीं करता हूं इनको पैरलल लेकर चलना चाहिए लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर है उस इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्यों न हम मजबूत करें। जो एग्जिस्टिंग हमारे स्कूल या कालेजिज हैं उनमें कहीं टीचर्स की कमी है, कहीं क्लारिज की कमी है तो कहीं स्कूलों की बिल्डिंग्ज की हालत जर्जर हो गई है और यह पता नहीं है वह किस वक्त गिर जाएं। सरकार को मैक्सीमम बजट या फिर एक्स्ट्रा बजट एग्जिस्टिंग स्कूलों और कालेजिज के लिए देना चाहिए ताकि उनको हम सशक्त और मजबूत बना सकें। जो वैकेंट पोस्ट्स हैं उनको भरा जाए और रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम का इंतजाम किया जाए। क्वालिटी एजूकेशन की ओर ध्यान दिया जाए। जिन स्कूलों की बिल्डिंग की हालत जर्जर है उनको ठीक करवाया जाए, जिन स्कूलों में कमरों की कमी है वहां कमरे बनाए जाएं। आज के बच्चे हमारे देश की नींव है जिनको कल हमारा हरियाणा बनना है और हमारा देश बनना है। अगर वे बच्चे मजबूत नहीं होंगे तो हमारा हरियाणा प्रदेश और देश कहां मजबूत होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि एजूकेशन ढांचे की ओर सरकार विशेष ध्यान दे, नए कालेजिज और स्कूल तो पैरलल आते रहेंगें। क्योंकि प्रदेश में आज सरकारी स्कूल्ज की जो हालत है उसके बारे में सभी जानते हैं और यही हाल प्रदेश में हास्पिटल्ज का है। जिस प्रकार से लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राईवेट स्कूल्ज में पढ़ने के लिए भेजते हैं क्योंकि वहां पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। उसी प्रकार से सरकारी अस्पतालों की भी यही हालत है।

[श्री कुलदीप बिश्नोई]

सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि लोग अपना इलाज कराने के लिए फोर्टीस, मैक्स, मेडीसिटी आदि हास्पिटल्ज में क्यों जाते हैं क्योंकि they provide good facilities, good doctors, good machineries and good infrastructure. हमारी सरकार उन हॉस्पिटल्ज जैसी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल्ज में प्रोवाईड क्यों नहीं करवा सकती है। सरकारी हॉस्पिटल भी अच्छे होने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, हमें सबसे बड़ा जीवन दान परमात्मा देता है उसके बाद सरकार का कर्तव्य बनता है कि लोगों को अच्छी सुविधाएं मुहैया करवायें। हमारे पास साधन हैं इसलिए प्रदेश के भी सरकारी हास्पिटल्ज में बढ़िया मशीनें इम्पोर्ट करके लानी चाहिए तथा अच्छे डाक्टर्ज को भी एप्वायंट करना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी ने पार्लियामैंट में कहा है कि स्टेट्स को आत्मनिर्भर कर रहे हैं और जहां तक मेरी याददाश्त है उन्होंने यह भी कहा है कि 78 प्रतिशत पैसा स्टेट्स को देंगे ताकि स्टेट्स आत्मनिर्भर हो सकें। माननीय प्रधान मंत्री जी की यह बहुत अच्छी सोच है। उसको हमें यूटीलाईज करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश को तो खासतौर पर केन्द्र सरकार से पैसे की मांग करनी चाहिए क्योंकि हरियाणा की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में भारी मैंडेट देकर सरकार बनाई है। पिछली सरकार ने प्रदेश का भट्ठा गोल कर दिया और प्रदेश को भारी कर्जे में छोड़ दिया। पिछली सरकार जो कर्जा प्रदेश पर छोड़ गई कम से कम उसको तो सरकार सैंटर गवर्नमैंट से माफ करवा ले। स्पेशल पैकेज प्रदेश के लिए लेकर आना चाहिए ताकि प्रदेश को वाकई में नम्बर-1 बनाया जा सके। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश चौधरी भजन लाल जी के समय में, चौधरी देवी लाल जी के समय में और चौधरी बंसी लाल जी के समय में नम्बर-1 पर था। हमें वही हरियाणा चाहिए। हमें टी.वी., समाचार पत्रों और एडवर्टाइजमैंट वाला हरियाणा नम्बर-1 नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि वास्तविकता में हरियाणा नम्बर-1 पर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता में हरियाणा नम्बर-1 पर तभी होगा जब हम सब मिलकर सम्पूर्ण रूप से यह धारणा across party line पार्टी पौलिटिक्स को छोड़कर एक सशक्त और मजबूत हरियाणा बनाने की होनी चाहिए। जब तक हम इस तरह का निर्णय नहीं लेंगे तब तक हरियाणा तरक्की नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया है। कोई उसके पक्ष में है और कोई विरोध कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि श्वेत पत्र जारी करें या न करें इसका कोई फायदा नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दे दिया है और उन बातों में कुछ नहीं रखा है। अब हमें कंस्ट्रक्टिव बात करनी पड़ेगी और विकास की बात करनी पड़ेगी कि हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या करना चाहिए। किन एरियाज में क्या-क्या कमियां रह गई हैं और कौन से इलाके पिछड़े रह गये हैं इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। श्वेत पत्र में जिक्र किया गया है कि रोहतक, सोनीपत और झज्जर इन 3 जिलों में पिछली सरकार के समय में विकास किया गया है।

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने श्वेत पत्र इसलिए जारी किया है ताकि प्रदेश की जनता को मालूम हो कि पिछली सरकार के समय में किस तरह से क्षेत्रवाद का भेदभाव किया गया है। यदि श्वेत पत्र जारी नहीं किया जाता है तो प्रदेश की जनता को किस प्रकार से समझ आयेगा कि पिछली सरकार के समय में किस प्रकार से भेदभाव हुआ है। * * * इस पर भी चर्चा होनी चाहिए ताकि भविष्य में सरकारें इस तरह का भेदभाव न कर पायें।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो अनपार्लियामैंटरी शब्द कह रहे हैं वे सदन की कार्यवाही में रिकार्ड न किए जायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो अनपार्लियामैंटरी शब्द कहे हैं वे रिकार्ड न किए जायें। कुलदीप जी, आप वाईंड अप करें। आपके पास अपनी बात कहने के लिए दो मिनट का समय बचा है।

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है और आप कह रहे हैं कि वाइंड अप करूं। अध्यक्ष महोदय, महीपाल जी की बात तो सही है लेकिन अब लोगों ने सरकार को मैंडेट दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने एजूकेशन की बात की है और हैल्थ की बात की है और पावर के बारे में सबसे अहम बात कहना चाहता हूं कि फतेहाबाद जिले के गोरखपुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्क्रैप करना चाहिए। वहां के लोगों की भी यह मांग है और लोगों ने इसको स्क्रैप करवाने के लिए धरने भी दिए थे। उस धरने में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता भी मेरे साथ गये थे। श्री गणेशी लाल जी उस समय काआर्डिनेशन कमेटी के को-चेयरमैन थे वे भी हमारे साथ वहां गये थे और शायद सुभाष बराला जी भी साथ थे। हमने उस समय वहां के लोगों से वायदा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम उस फतेहाबाद न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्क्रैप करवा देंगे। अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस प्लांट को स्क्रैप करवाया जाये क्योंकि इस प्लांट की अब कोई जरूरत भी नहीं है। We should go for solar power plant और बायो गैस पर भी जा सकते हैं तथा दूसरी चीजें भी हैं जिनसे पावर जनरेट कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे एक माननीय सदस्य ने बजट पर बोलते हुए एस.वाई.एल. का मुद्दा भी उठाया। इस समय वे सदन में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों ने एस.वाई.एल. को बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मैं समझता हूं इस तरह के शब्द सदन की कार्यवाही से ऐक्सपंज करने चाहिएं क्योंकि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। पंजाब के कपूरी गांव में इंदिरा जी को ले जाकर स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी ने नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। मैं यह याददाश्त के लिए बता रहा हूं। सारी की सारी एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के समय में हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अगर पंजाब सरकार इस नहर का निर्माण नहीं करवाती है तो केन्द्र सरकार को अपने स्तर पर इस नहर का निर्माण करवाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको इस बारे में जिक्र करना चाहिए था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और चौधरी भजन लाल जी ने तब प्रधानमंत्री निवास का घेराव किया था। इसके साथ-साथ मैं यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अच्छे इंसान थे और वे भी इस मामले में प्रयासरत थे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल बिज) : स्पीकर सर, यहां पर जो बात चल रही है मैं उसी के संदर्भ में to put the record straight क्योंकि यहां पर बात की जा रही है कि कांग्रेस ने एस.वाई.एल. का निर्माण करवाया। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तो सदा ही उल्टे काम किये हैं। नहर को हमेशा ही अप साईड से डाऊन साईड खोदा जाता है लेकिन इन्होंने इस नहर को नीचे से ऊपर खुदवाया। इसलिए अगर इन्होंने ऊपर से नीचे यह नहर खुदवाई होती तो आज जो यह पानी रुका हुआ है यह पानी न रुकता और हरियाणा प्रदेश को बहुत पहले इस

नहर का पानी मिल चुका होता, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने यह उल्टा काम किया है जिसका आज तक रगड़ा पड़ा हुआ है।

श्री कुलदीप बिश्नोई : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के शब्दों को सदन की कार्यवाही से एक्सपंज करवाना चाहिए।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बारे में बात की है। मैंने श्री कुलदीप बिश्नोई जी को नहीं कहा है।

श्री कुलदीप बिश्नोई : स्पीकर सर, अगर विज साहब ने कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई बात कही है तो उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ही देगी। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो चौधरी भजन लाल जी के व्यक्तिगत प्रयासों की बात कर रहा हूं। अगर कांग्रेस पार्टी इस बारे में प्रयास करती तो जब श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस समय केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जी पंजाब में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री थे उस समय इस नहर का निर्माण करवाया जा सकता था। यही स्थिति आज है इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस नहर का निर्माण हर हाल में करवाना चाहिए क्योंकि हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसी प्रकार से पंजाब प्रदेश की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी भागीदार है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हमें एक टाईम बाऊंड डेट दे दे कि इस तारीख को हम बादल साहब से एस.वाई.एल. कैनाल में हरियाणा के हिस्से का पानी लेकर आयेंगे तो कुलदीप बिश्नोई सारा कुछ दांव पर लगाने के लिए और आपके नाम करने के लिए तैयार बैठा है। जहां तक चण्डीगढ़ का मुद्दा है मैं समझता हूं कि अगर पंजाब हमें एस.वाई.एल. कैनाल का पानी देता है तो हमें उसे इसके बदले में चण्डीगढ़ देने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि हमें चण्डीगढ़ की बिल्डिंगों से अपने सिर थोड़े ही फोड़ने हैं। हमें अपने किसानों के लिए पानी चाहिए इसलिए अगर हमें अपने किसानों के लिए पानी मिलता हो और पंजाब के हिन्दी भाषी इलाके हमें मिलते हों तो हमें चण्डीगढ़ को पंजाब को देने में कोई हर्ज़ नहीं होना चाहिए। स्टेट की कैपिटल बनाने के लिए हमारा हिसार बहुत बढ़िया जिला है। चौधरी भजन लाल जी ऐसा चाहते भी थे और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर है। यूनिवर्सिटी भी वहां पर है इसलिए वहां पर स्टेट कैपिटल बनाई जा सकती है इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से हम समान रोजगार और समान विकास की बात किया करते थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सभी सदस्यगण कृपया करके बैठ जायें। श्री कुलदीप जी अपनी बात कह रहे हैं जब आपको मौका मिलेगा तब आप अपनी बात कह लेना। (विघ्न)

श्री कुलदीप बिश्नोई : स्पीकर सर, अगर हम भी यही करते जो कादियान साहब कह रहे हैं यह इनकी बहुत अच्छी सोच है ये मुझसे सीनियर भी हैं और मुझसे उम्र में बड़े भी हैं लेकिन अगर हमारी यही सोच रही कि चण्डीगढ़ भी हमारा है इसलिए हम चण्डीगढ़ भी लेंगे, पानी भी हम लेंगे और हिन्दी भाषी क्षेत्र भी हम लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है फिर तो हम ऐसे ही सिर फोड़ते रहेंगे। इसलिए मैंने यह चाहता हूं कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें कोई न कोई लॉजीकल कंक्लूज़न निकालना चाहिए। यह मैं अपनी सोच के हिसाब से बात कर रहा हूं। दूसरा समान विकास के बारे में सरकार को मैं एक बहुत अच्छा सिस्टम बताना चाहता हूं जो कि चौधरी भजन लाल जी की सोच थी और इस मुद्दे को जब हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस था उस समय श्री अनिल विज जी ने इस सदन में बहुत ही बढ़िया ढंग से उठाया भी था

कि एम.पी. लैड (लोकल एरिया डिवैलपमैंट) की तर्ज़ पर हरियाणा में भी एम.एल.ए. लैड की शुरूआत होनी चाहिए। मैं एक बार से फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब 1996 में चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी तो उस समय यह चौधरी भजन लाल जी की व्यक्तिगत सोच थी लेकिन उसके बाद जितनी भी सरकारें हरियाणा में आई उनमें से किसी ने भी इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया। एम.पी. लैड की तर्ज़ पर हरियाणा में भी एम.एल.ए. लैड स्कीम की शुरूआत होनी चाहिए जिसके तहत एम.एल.ए. चाहे वह किसी भी पार्टी का हो उसे भी एम.पी. की तरह पॉवर होनी चाहिए कि वह उस धन को अपने हल्के में अपने हिसाब से और अपनी सहूलियत के हिसाब से खर्च कर सके। मैं इस सरकार को यह एक कंफर्ट लैवल दे रहा हूं ताकि आने वाले समय में कोई भी एम.एल.ए. या जनता सरकार को बुरा-भला न कहे कि इस सरकार ने भी पूरे हरियाणा प्रदेश का समान विकास नहीं करवाया। एक हमारी बात थी यूथ के ऊपर कि हरियाणा प्रदेश में जो स्टूडैंट यूनियंस के इलैक्शन हैं उनको जल्दी से जल्दी करवाया जाये क्योंकि वर्ष 1996 के बाद हरियाणा प्रदेश में बहुत लम्बे समय से स्टूडैंट यूनियंस के इलैक्शन नहीं हुए। दिल्ली के अंदर जब स्टूडैंट यूनियंस के इलैक्शन होते हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों उसमें पार्टीसिपेट करती हैं। अगर हम दिल्ली के स्टूडैंट यूनियंस के इलैक्शन में पार्टीसिपेट कर सकते हैं तो फिर हरियाणा में स्टूडैंट यूनियंस के इलैक्शन क्यों नहीं करवाये जा सकते। जब लोअर लैवल से बच्चे उठकर आते हैं और अपना लीडर चुनने में सक्षम होते हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छी शुरूआत हो सकती है। इसलिए मैं एक बार फिर से सरकार से पुरज़ोर मांग करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जल्दी से जल्दी स्टूडैंट यूनियंस के इलैक्शन करवाये जायें। (विघ्न) स्पीकर सर, बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता था इसके लिए मैंने बी.ए.सी. की मीटिंग में भी यह कहा था कि लोकदल के सदस्यों के समय में से थोड़ा सा समय मुझे दे दें और उस समय श्री अभय चौटाला जी मान भी गये थे। मैं अपने हिसार लोक सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि हिसार लोक सभा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं को लेकर पिछले 19 साल से लगातार घोर उपेक्षा का शिकार हो रहा है। आदमपुर हल्के की समस्याओं को लेकर मैंने 50 पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं और इसी प्रकार से हांसी हल्के की समस्याओं को लेकर 50 पत्र रेणुका जी ने माननीय मुख्यमंत्री को लिखे हैं। हिसार पार्लियामैंट के मुद्दों को लेकर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखें हैं चाहे वह सीवरेज़ की बात हो या फिर किसी अन्य समस्या के बारे में हो। अभी कल यहां पर बात हुई थी कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमने सीवरेज़ की व्यवस्था के लिए हरियाणा प्रदेश के 28 शहर चुने हैं। मैं यह चाहता हूं कि हिसार लोक सभा क्षेत्र के इस मामले में जो पिछले 19 साल से पिछड़े हुए इलाके रह गये हैं उनको नम्बर एक पर रखना चाहिए। इनमें मेरा आदमपुर है, हिसार शहर है, हांसी शहर है और बरवाला शहर है। इन सबके लिए सीवरेज़ व्यवस्था की शुरूआत की जाये। इसी प्रकार से समान विकास और समान रोज़गार का कानून सरकार यहां पर पारित कर दे तो आपकी और सरकार की बड़ी कृपा होगी। स्पीकर सर, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन वे मुद्दे रह गये हैं। उनके लिए अगर आप इज़ाजत दें तो मैं उनको आपको लिखकर दे दूंगा आप कृपा करके उनको हाऊस में पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, अभी आप बैठ जाईये। आपके जो मुद्दे रह गये हैं उनके बारे में आप हमें लिखकर दे दें हम उनको हाऊस की प्रोसीडिंग में शामिल कर लेंगे।

श्री भगवान दास कबीरपंथी (नीलोखेड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सदन में बैठे सभी सम्मानित सदस्यों का नमन करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है यह बजट पूरे प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रख कर लाया गया है और इस बजट से निसन्देह चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर वर्ग को लाभ मिलेगा और पूरा प्रदेश बहुमुखी विकास करेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र नीलोखेड़ी की कुछ समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वैसे तो नीलोखेड़ी शहर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बसाया था लेकिन जब से यह शहर बसा है तब से आज तक किसी भी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली है। बासमती चावल के नाम से मशहूर इस नगरी से बहुत बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात किया जाता रहा है। इस क्षेत्र में चार बड़ी मंडियाँ हैं और भारी भरकम राजस्व सरकार को इस क्षेत्र से जाता है लेकिन विकास किसी भी सरकार ने नहीं किया। चाहे सड़क की बात हो चाहे विकास की कोई योजना बनाने की बात हो, किसी सरकार ने इस क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं किया। मैं एक सड़क के बारे में बताना चाहता हूँ वह सड़क रायपुर से यूनुसपुर जो कल्ची से बरसालू हो कर जाती है उस सड़क की हालत ऐसी हो चुकी है कि उस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लगभग 2-3 साल पहले हरियाणा रोडवेज की बसें इस सड़क पर जाती थी अब वे भी जानी बंद हो गई हैं। इसलिए इस सड़क पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी प्रकार से एक पब्लिक हैल्थ का सब डिवीजन जो कि नीलोखेड़ी में था उसको पिछली सरकार ने असन्ध भेज दिया और अब असन्ध से वह करनाल चला गया है। इसलिए अब हमें छोटे-छोटे कार्यों के लिए करनाल जाना पड़ता है जबकि वहाँ पर बिल्डिंग भी थी और स्टाफ भी था। इसी तरह से तरावड़ी में लगभग 16-17 साल पहले चौधरी भजन लाल जी ने एक कॉलेज का शिलान्यास किया था लेकिन आज वहाँ पर सिर्फ पत्थर लगा हुआ है। किसी भी सरकार ने वहाँ पर कॉलेज बनवाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से आपको भी पता है कि नीलोखेड़ी और तरावड़ी हाईवे पर हैं। यात्रियों को बस पकड़ने के लिए सड़क पर खड़ा होना पड़ता है। इस वजह से कई बार बहुत हादसे हो चुके हैं लेकिन दोनों ही जगहों पर बस-अड्डे नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि नीलोखेड़ी और तरावड़ी में बस-अड्डों का निर्माण किया जाये ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। नीलोखेड़ी में एक बहुत पुराना पोलिटैक्निक कॉलेज है। वहाँ पर बिल्डिंग भी पर्याप्त है और स्टाफ भी मौजूद है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस पोलिटैक्निक कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया जाये। इसी प्रकार से तरावड़ी में एक विद्यालय है जहाँ जगह कम होने की वजह से दो-दो शिफ्ट लगाई जाती हैं। सर्दियों में तो बच्चों को बाहर टाट पर बैठना पड़ता है क्योंकि बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहाँ पर और जगह उपलब्ध करवाई जाये ताकि बच्चे आराम से बैठ कर अपनी पढ़ाई कर सकें। इसी प्रकार से हरियाणा में नीलोखेड़ी विधान सभा क्षेत्र में 4 बड़े कस्बे हैं नीलोखेड़ी, तरावड़ी, निसिंग और निग्दू, इसलिए कृपया इसको उप-मण्डल का दर्जा दिया जाये। हरियाणा में चावल पर मार्किट फीस 4 परसेंट है जबकि मध्यप्रदेश और पंजाब में चावल पर कोई टैक्स नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि या तो इस मार्केट फीस को कम किया जाये या बिल्कुल ही समाप्त किया जाये ताकि किसान और व्यापारी लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी प्रकार से निसिंग जो कि बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत गांव लगते हैं तथा वहाँ

पर कन्याओं के लिए कोई कॉलेज नहीं है इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि वहाँ पर एक कन्या महाविद्यालय खोला जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक ऐसी समस्या उठाना चाहता हूँ जिससे पूरा प्रदेश दुखी है और वह है जन्म-मृत्यु पंजीकरण की। इसमें अगर किसी का जन्म पंजीकरण नहीं हुआ है या पंजीकरण में नाम गलत हो गया है तो जन्म पंजीकरण वाले इतने चक्कर कटवाते हैं कि चक्कर काटते-काटते उसकी जूतियाँ टूट जाती हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस समस्या का सरलीकरण किया जाये और जिन बच्चों का पंजीकरण नहीं हो पाया है उनके लिए कोई स्कीम फ्लोट की जाये कि इतने समय में आप अपने बच्चे का पंजीकरण करवा सकते हैं या नाम ठीक करवा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका पुन: धन्यवाद करता हूँ।

श्री रविन्द्र माच्छरौली (समालखा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे से पहले बहुत से साथियों ने बड़ी बारीकी से बजट के आंकड़ों पर अपने-अपने विचार रखे। यह बजट सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बजट में सरकार ने कोई भी नया कर नहीं लगाया है। बल्कि जैविक उर्वरकों पर वैट खत्म किया है तथा एल.ई.डी. लाईट तथा किसानों के लिए प्रयोग होने वाले पी.वी.सी. पर भी वैट कम किया है। स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पानीपत में लगभग चार हजार करोड़ रुपये की लागत से थर्मल पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सरकार को अपने हल्के की कुछ समस्याओं से अवगत कराने चाहता हूं। मेरे समालखा के अन्दर फौजियों के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां वे महीने-दो महीने में मिल बैठकर अपने दु:ख-सुख व देश की चर्चाएं कर सकें। वे बेचारे सारा जीवन फौज के अंदर सेवा करके आते हैं। दूसरी समस्या मेरे समालखा हल्के के अन्दर शहर के अन्दर बहुत ज्यादा भीड़ है और वहां पर कोई भी बाईपास नहीं है जिसकी वजह से आने-जाने वाले ट्रकों का जाम लगा रहता है। तीसरी समस्या यह है कि मेरा समालखा हल्का बहुत गरीब हल्का है। यमुना के आस-पास काफी गांव हैं जहां यू.पी. और हरियाणा के लोगों का आपस में झगड़ा रहता है। सर, ऐसा होता है कि जमीन बोते तो हैं हमारे हरियाणा वाले लेकिन फसल को काट ले जाते हैं यू.पी.वाले। यह भी काफी झगड़ा है। एक मेरे हल्के में आटा गांव है जो मेरे हल्के की सबसे ज्यादा आबादी वाला गांव है जिसके अन्दर लड़कियों के लिए कोई सीनियर सैकेंडरी स्कूल नहीं है। लड़कियों को पढ़ने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। सर, मेरे पीछे जो सदस्य बैठे हुए हैं वह पीछे से बात कर रहे थे कि भाई जो सदस्य अंग्रेजी में बोलते हैं वह तो एस.वाई.एल. केनाल की समस्या से भी बड़ी समस्या लग रही है। मैं तो स्पीकर साहब के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि एस.वाई.एल. की समस्या को हटाकर इसको जोड़ लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जब कोई बात यहां आने वाले 70 प्रतिशत लोगों की समझ में नहीं आएगी तो उसका कहने का क्या फायदा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कुछ ऐसा करो जिससे सभी हिन्दी में ही बोलें क्योंकि हिन्दी हमारी मातृ भाषा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं माननीय विधायक जी को कहना चाहूंगी कि आपको हम समझा दिया करेंगे।

श्रीमती लतिका शर्मा (कालका) : अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामय सदन में इस बार के बजट में महिलाओं एवं बाल विकास के लिए इस वर्ष 1193.29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि वर्ष 2014-15 के रिवाईज्ड एस्टीमेट प्लान आऊट ले से 1.83 प्रतिशत अधिक है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं। हमारी सरकार महिला एवं बाल विकास के लिए अग्रणी प्रयास कर रही है जैसा कि हम सबको पता है केवल हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे देश में बेटियों की संख्या वर्ष 2011 के अनुसार 1000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ तथा हरियाणा में रजिस्टर्ड बर्थ्स एण्ड डैथ्स दिसम्बर, 2014 के आंकड़ों के अनुसार ए हजार लड़कों पर 871 लड़कियां हैं। कन्या भ्रूण हत्या तथा अन्य कारणों से यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। मैं इस सदन में उपस्थित मैम्बर साहेबानों को बताना चाहती हूं कि बच्चियों के संरक्षण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लाल किले से जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया था उसे पूर्ण रूप देते हुए 22 जनवरी, 2015 को पानीपत से एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में हरियाणा के 12 जिलों में इस अभियान को शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज की मानसिकता को बदलना है। बालिकाओं के जन्म, शिक्षा एवं पोषाहार के प्रति एक सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करना है जिससे लड़कियां सशक्त व सबल बन सकें। इस वर्ष इस बजट में इस कार्यक्रम के लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी सदस्यगण ने हरियाणा के सभी जिलों में जन प्रचार यात्रा दिनांक 17-18 जनवरी, 2015 को शुरू करते हुए समाज के सभी वर्गों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लिए प्रेरित किया। इस वर्ष हमारी सरकार ने बेटी की लोहड़ी मनाते हुए पूरे समाज को ये सन्देश दिया कि बेटी के जन्म पर भी हमें प्रसन्नता होनी चाहिए और गर्व महसूस होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 20 और 21 जनवरी, 2015 को पानीपत में एक राष्ट्र स्तरीय चिन्तन शिविर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राज्यों एवं यूनियन टैरीटरी के महिला एवं बाल विकास मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस दो दिवसीय चिन्तन शिविर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की जागरुकता के लिए 12 मोबाईल वैन दृश्य श्रव्य उपकरणों द्वारा लैस है तथा ये सभी 12 जिलों में कार्यरत हैं। अध्यक्ष महोदय, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, कुपोषण रोकना, महिलाओं को शिक्षित तथा महिलाओं को सशक्त करना सरकार की प्राथमिकताएँ हैं जिसके लिए सरकार बहु आयामी प्रयास कर रही है। जिनमें बहुत सी सरकारी योजनाएँ लागू करने के साथ-साथ सामाजिक गतिशीलता व सहभागिता के लिए प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के लिए इस बजट में 568.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और आंगनबाड़ियों के निर्माण में 210 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा 8 मार्च, 2015 को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य यह है कि हम अपनी बेटियों का इस दुनिया में स्वागत करें और कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध पर अंकुश लगाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं बीपीएल परिवारों में पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि आधार लिंक के खाते से जमा करवाई जायेगी और सभी परिवारों की दूसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि जमा करवाई जायेगी। जब बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जायेगी तब यह राशि लगभग 1,00,000 रुपये हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, व्यस्क लड़किया अपनी उच्च शिक्षा के लिए या अपनी शादी के लिए यह

राशि निकलवा सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन पहले राज्यों में से एक है जिसमें बेटियों के विकास के लिए हरियाणा कन्या कोष का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2015 को गठन किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कमजोर, कुपोषित बेटियों को उचित पोषाहार देकर उनके स्तर को ऊँचा उठाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस बारे में एक मल्टी सैक्टोरल प्रोग्राम 8 मार्च, 2015 को चार जिलों में जैसे कि मेवात, फतेहाबाद, नारनौल तथा कैथल के लिए अतिरिक्त पोषाहार देते हुए 919 लाख रुपये ` वार्षिक बजट का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ हमारी सरकार बच्चों, किशोर बालिकाओं तथा महिलाओं में कुपोषण तथा एनीमिया को खत्म करने के लिए पोषण मिशन को शीघ्र लागू करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा अभिभावकों को उनकी बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए बचत करने हेतु सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत से शुरू किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 10 वर्ष तक की बेटी के नाम पर 1,00,000 रुपये से लेकर 1 लाख 50 हजार रुपये तक पैसा जमा करवाने पर अधिक से अधिक ब्याज दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कालका विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो कि हिमाचल की तलहटी में बसा है और अत्यंत पिछड़ी अवस्था में है और विकास की राह देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा नैतिक कर्त्तव्य बनता है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जी जान से काम करूँ। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के इस एक मात्र पहाड़ी क्षेत्र की अलग तरह की समस्याएँ हैं। मेरा क्षेत्र बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के चहुँमुखी विकास के लिए हरियाणा सरकार को विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज का प्रावधान किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कालका विधान सभा क्षेत्र अत्यन्त दयनीय अवस्था में है यदि इसको औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया जाये तो हमें कुछ राहत मिल सकती है क्योंकि यह एरिया बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के साथ लगता है। अध्यक्ष महोदय, रायपुर रानी में एक बड़ा ब्लॉक और उप तहसील विकसित की जाये और इसी तरह इसे उप प्रभाग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रायपुर रानी के कुछ गाँवों को प्रशासनिक दृष्टि से उपायुक्त पंचकूला द्वारा देखा जाता है। जबकि पुलिस ज्यूरिसडिक्शन अंबाला मुख्यालय के साथ है। अध्यक्ष महोदय, इस विसंगति को हटा दिया जाना चाहिए और रायपुर रानी को स्वतंत्र उप प्रभाग के रूप में उन्नत किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मोरनी में हर्बल पौधारोपण करवाया जाना चाहिए और वहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाना चाहिए। किसानों को 5-5 या इससे ज्यादा या कम भूमि लीज पर देकर हर्बल प्लांटस लगाये जाने चाहिए जैसे हरड़, बहेड़ा, आंवला, धृतकुमारी, हल्दी और अदरक आदि की खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर पहले से ही खेती की जाती है जिससे इन किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी को मोरनी में हर्बल पौधारोपण करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मोरनी को पर्यटक स्थल घोषित किया जाना चाहिए। हमारे टूरिज्म मिनिस्टर, श्री रामबिलास शर्मा जी और केन्द्रीय मन्त्री डॉक्टर महेश कुमार शर्मा जी भी इसके लिए प्रयासरत हैं। मेरी यह भी मांग है कि मोरनी के किसान जो पुश्तों से जमीन को जोतते आ रहे हैं उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया जाये। कालका के अन्दर एक यूनिवर्सिटी खोली जाये, जिससे वहां के बच्चों को पढ़ने के लिये दूर दराज

[श्रीमती लतिका शर्मा]

के क्षेत्रों में न जाना पड़े। अध्यक्ष महोदय, एच.एम.टी. कम्पनी पिंजोर और कालका की रीड की हड्डी है जो बंद होने के कगार पर खड़ी है। एच.एम.टी. कम्पनी को विशेष पैकेज दिलवाने तथा दोबारा से कम्पनी को उसी स्थिति में लाने के लिये केन्द्रीय सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं, वह बहुत सराहनीय हैं उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। माईनिंग बंद होने के कारण, पंचकूला क्षेत्र में माईनिंग अवैध तरीके से हो रही है और बिल्डिंग मैटीरियल भी महँगा होता जा रहा है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, माईनिंग को खुलवाया जाये, जिससे क्षेत्र के 50 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल सके। आम, चीकू, लीची आदि फलों की पैदावार हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए माननीय कृषि मंत्री जी भी सदन में बैठे हुए हैं, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक होर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी पिंजौर या कालका क्षेत्र में खोली जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात कहना चाहती हूँ कि जनसंख्या तथा भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र हरियाणा से अलग है, जो सुविधाएं मेवात क्षेत्र को दी गई है वही सुविधाएं इस मैदानी क्षेत्र को भी देनी चाहिएं ताकि इस क्षेत्र में विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, इस पहाड़ी क्षेत्र में स्कूल खोलने तथा जमीनी उपलब्धता के नियमों में ढील देकर नियमावली बनानी चाहिए जिससे पिछड़े क्षेत्रों में विकास हो सके। इस क्षेत्र के लोग अति गरीब हैं, मोरनी क्षेत्र में तो यह हालत है कि बच्चों को पढ़ने के लिये 10-10 किलोमीटर दूर तक स्कूल जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में तो स्कूल बंद ही हो जाते हैं, साथ ही जंगली जानवरों का खतरा भी मंडराता रहता है। हमारी सरकार जन कल्याणकारी है, अत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि कालका को विशेष जोन घोषित करके नियमावली में ढील देकर स्कूलों का अपग्रेड किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है कि आपने पार्टीवाईज़ बोलने के लिये समय सारणी बनाई हुई है लेकिन प्रतिपक्ष नेता और कांग्रेस विधायक दल की नेता ने 40-40 मिनट का समय लिया, इस समय को छोड़ दीजिए ताकि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का समय मिले।

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, सभी को बोलने का समय मिलेगा, यह तो आपके लीडर को देखना चाहिए था। बाकी सभी माननीय सदस्य 5-6 मिनट ही बोल रहे हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, सदस्यों के पास बोलने के लिये ज्यादा मैटर भी नहीं है और ना ही इनके बोलने के समय किसी प्रकार का विघ्न आता है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, जिस माननीय सदस्य के पास बोलने के लिये कुछ होगा तभी तो बोलगा। हमारे प्रतिपक्ष के नेता 40 मिनट नहीं बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता 28 मिनट व कांग्रेस विधायक दल की नेता 37 मिनट बोली है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को चाहिए कि बजट पर बोलें, इधर-उधर की बातों मे न जाये।

श्री अध्यक्ष : नये माननीय सदस्य 5-5 मिनट ही बोल रहे हैं, आप को वैसे ही लग रहा है कि ज्यादा समय लिया है। माननीय सदस्या के बाद आपका ही नाम है।

श्रीमती संतोष चौहान सारवान (मुलाना) (अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2015-16 के बजट पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हरियाणा प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने हर क्षेत्र तथा हर वर्ग के समग्र विकास के लिये जो पहला बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों ने अपने शासन काल के दौरान सम्पूर्ण हरियाणा के साथ भेदभाव करते हुए केवल कुछ ही हिस्सों में विकास का कार्य करवाना मुनासिब समझा था परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में समान विकास तथा प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। कृषि के मसले में प्रदेश के किसानों को परम्परागत खेती की जगह नकदी फसलों की ओर प्रेरित करने की सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा फ्रेश' के नाम से अपना खुद का ब्रांड लघु कृषक व्यापार संघ से पंजीकृत करवाया है। देसी गाय के दूध से घी व इससे बने हुये उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना है। कृषि से संबंधित बजट में पिछले वर्षों की तुलना में 10.10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अकेले कृषि और बागवानी के लिए बजट में 20.88 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त मछली-पालन विभाग के बजट में रिकॉर्ड 132.71 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी की गई है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के बजट में भी 27.87 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इस प्रकार से समाज कल्याण की सभी योजनाओं में सरकार ने उदारता दिखाते हुए 16.93 प्रतिशत की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन विवाह योजना के तहत अनुसूचित जातियों, जनजातियों, टपरीवास जातियों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवाओं की लड़कियों की शादी में 41 हजार रुपये का कन्यादान देने का फैसला किया गया है। इस फैसले से सरकार की गरीब लड़कियों के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। पिछली सरकार में यह राशि 31 हजार रुपये थी और इसे देने की कोई समय-सीमा भी नहीं थी। पिछली सरकार के समय में गरीब विधवाओं को एक-एक साल तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और उनको निश्चित समयावधि में अनुदान नहीं दिया जाता था लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने 26 फरवरी, 2015 से इस राशि को एक महीने के अंदर देने का फैसला किया है। शादी के सिर्फ एक महीने के बाद ही लड़की को पैसा प्राप्त हो जाएगा। इससे लाभार्थी को एक फायदा यह होगा कि अगर उसने किसी से पैसा लिया है तो उसका ब्याज नहीं देना पड़ेगा। पिछली सरकार ने हरियाणा के कुछ चुनिन्दा हल्कों में ही विकास करवाया था। इस वजह से मेरा विधानसभा क्षेत्र विकास से अछूता रहा है। यहां पर जनसमस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा से कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का दस साल राज रहा है और मेरे हल्के से जो कांग्रेस का विधायक था उसने कोई विकास नहीं कराया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं उस समय विधायक नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो ऐश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आदरणीय सदस्य इस शब्द को क्लीयर करें और यह शब्द एक्सपंज किया जाए क्योंकि मैं उन दस सालों में विधायक नहीं

[श्रीमती संतोष चौहान सारवान]

थी। (विघ्न) नहीं भाईसाहब, मेरे हाथ खड़े हैं। इनके साथ कुश्ती का मेरा जुगाड़ नहीं है। जो शब्द ये प्रयोग कर सकते हैं उन्हें मैं प्रयोग नहीं कर सकती। ये मेरे वश की बात नहीं है। (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को कई पार्टियों का तजुर्बा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती संतोष चौहान सारवान : अध्यक्ष महोदय, मैं कई पार्टियों की सदस्य रह चुकी हूं इसलिए मैं बिल्कुल सही ढंग से बात करूंगी। मैं आपके माध्यम से विपक्ष से केवल एक बात कहना चाहती हूं कि पिछले दस साल तक मेरे हल्के का जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता रहा वह दाहिनी तरफ के बैंचों पर बैठता था और उसकी कांग्रेस सरकार में अच्छी पैठ थी तथा वह कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का आपके पड़ोस में है। आप वहां जाकर देखें कि मेरे क्षेत्र की कैसी हालत है ? उसे देखकर लगता ही नहीं कि यह उस सदस्य का इलाका रहा है जिसकी पार्टी ने सरकार बनाई थी। मेरे क्षेत्र को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यू.पी. के किसी ईंटीरियर एरिया या रिमोट एरिया में प्रवेश कर लिया हो। इतनी खराब हालत मेरे हल्के की है। अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र का थाना नाहन के राजा की धर्मशाला में स्थित है। उसमें बारिश का पानी गिरता रहता है। बारिश के समय पुलिस वाले अपने टीन-टप्पर उठाकर कभी किसी के घर में तो कभी किसी की दुकान में जाकर पनाह लेते हैं। इतनी खराब स्थिति मेरे क्षेत्र के थाने की है। 16.00 बजे अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का 100 प्रतिशत ग्रामीण है। इसमें तीन ब्लॉक हैं साहा, बराड़ा और अम्बाला-1, टोटल 167 पंचायतें हैं और 172 ग्राम हैं। मेरे ख्याल से हरियाणा विधान सभा का इससे बड़ा कोई ग्रामीण हल्का नहीं होगा। मेरे हल्के के गांवों के विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि पिछली सरकार के समय में यह हल्का बहुत उपेक्षित रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा के बराड़ा कस्बे की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकड़ों के अनुसार 22780 थी जोकि अब बढ़कर 30 हजार के करीब हो गई है क्योंकि लोगों का गाँवों से शहर की तरफ पलायन हो रहा है और पिछले चार सालों में इस कस्बे की तरफ ज्यादा लोग आये हैं। बराड़ा नगर पालिका के गठन के लिए प्रस्ताव बनाकर उपायुक्त, अम्बाला के माध्यम से हरियाणा सरकार को भेजा हुआ है जोकि सरकार के विचाराधीन है। पिछली सरकार के समय में भी बराड़ा नगर पालिका के गठन का प्रस्ताव आया था परन्तु हल्के की नुमांइदगी कर चुके कांग्रेसी नेता जो उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद पर विराजमान थे, उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के कारण इसके गठन का प्रस्ताव रूकवा दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि बराड़ा में नगरपालिका के गठन की स्वीकृति शीघ्र प्रदान कर दी जाये ताकि आने वाले पंचायत के चुनावों के दायरे से इस कस्बे को बाहर रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के निवासियों की बहुत समय से यह मांग रही है कि मारकण्डा रीवर पर गांव हरयोली से तन्दवाल तक एक हाई लैवल पुल का निर्माण करवाया जाये। इस पुल के बनने से बराड़ा से साहा जिसकी दूरी अब 20 किलोमीटर के लगभग है, पुल के बनने से यह दूरी मात्र 8 से 9 किलोमीटर तक रह जायेगी तथा इस पुल के बनने से गांव सबगा, पसियाला, पंजैल, वजीदपुर, दिनारपुर, खानपुर, डुबली, चुड़ियाला, घसीटपुर, शेरगढ़, बीहटा, नगला जाटान, हरयोली, हलधरी, लंगरछन्नी, लण्डा, घुराला समालखा, राउमाजरा, सोहाता, खानपुर, उगाला,

बराड़ा, अमबड़, तन्दवाल दाउमाजरा इत्यादि 30 गाँवों को फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस बजट में ही इस पुल के निर्माण हेतु पैसे का प्रावधान करने की कृपा करें ताकि वहां के लोगों की मांग को पूरा किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए की गई चुनावी घोषणाओं के कारण सभी विभागों में विकास कार्य रोक दिये गये थे। मेरे विधानसभा क्षेत्र मुलाना की कुछ नई सड़कें जिनमें लिंक रोड मुलाना से उपलाना, लिंक रोड गुरद से काकरकुण्डा, लिंक रोड सोहाना से राजोली, लिंक रोड तलहेडी से अकालगढ़ तथा लिंक रोड तमनौली से साहा की कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनकी लम्बाई 2 से 4 किलोमीटर के लगभग हैं तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा इनकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी भी कर दी गई थी परन्तु पिछली सरकार द्वारा विकास कार्यों पर खर्च किये जाने वाला सारा पैसा चुनावी घोषणाओं पर खर्च कर देने से इन सड़कों के लिए पैसा मुहैया नहीं करवाया गया। इसके अतिरिक्त कुछ और लिंक रोड जैसे दादुपुर से राजोखड़ी, मलिकपुर से अलावलपुर, मुलाना बाईपास, धन्योड़ी से ठरवा, दुखेड़ी से फडौली, लंगरछन्नी से घुराला, सांबापुर से मलिकपुर, ठाकुरपुरा से मुलाना तथा ठाकुरपुरा से बाघोली तक मेरे हल्के की कुछ नई सड़कें हैं जिनकी लम्बाई डेढ़ से ढ़ाई किलोमीटर है, इन सड़कों के निर्माण हेतु भी बजट का प्रावधान किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांव खण्डा में 1 से 1.50 लाख की कैपेसिटी के एक पानी के टैंक का निर्माण अति आवश्यक है ताकि जिन घरों में पानी की पूरी सप्लाई नहीं हो पाती, वहां पानी पहुंच सके। मेरे हल्के के कस्बा बराड़ा, मुलाना, साहा तथा दोसड़का में सीवरेज व्यवस्था नहीं है, मैं जब स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इन कस्बों में सीवरेज की व्यवस्था करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त गाँवों के तालाब पानी से भरे पड़े हैं, जिससे गाँवों की गलियों में गन्दा पानी इकट्ठा हो जाता है तथा इस कारण बीमारी फैलने का अंदेशा बना रहता है। गाँवों के तालाबों से पानी की निकासी का भी सरकार कोई न कोई समाधान अवश्य करे। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा बराड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का कर दिया गया है परंतु उसके लिए न तो भवन का निर्माण किया गया है और न ही सी.एच.सी. नॉर्म के अनुसार वहां पर सुविधायें ही मुहैया करवाई गई हैं। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वहां सी.एच.सी. स्तर के भवन का निर्माण करवाया जाये तथा और अन्य सुविधायें भी दी जायें। इसके अतिरिक्त कस्बा मुलाना में चल रही सी.एच.सी. को इण्डियन हैल्थ स्टैण्डर्ड के अनुसार अपग्रेड किये जाने संबंधी प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के पास विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगी कि इसकी स्वीकृति जल्दी प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : सारवान जी, कृपया वाइंड-अप करें।

श्रीमती संतोष चौहान सारवान : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात केवल एक मिनट में ही पूरी कर लूंगी। मैं कहना चाहूंगी कि गाँव धीन में एक सब सैंटर चल रहा है, उसकी चारदीवारी तथा एक डिलीवरी रूम बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा उगाला जो शाहबाद-बराड़ा रोड पर बसा हुआ है तथा मुलाना जो अम्बाला छावनी-जगाधरी रोड़ पर स्थित है, इन कस्बों में बस अड्डे बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है जिनके संबंध में जनता की मांग लंबे समय से चली आ रही है। उस समय के विधायक ने अपने हल्के के आगे अपना नाम तो लिखवा लिया था लेकिन उस गाँव में आज तक बस स्टैंड नहीं है। मैं पूछना चाहती

[श्रीमती सन्तोष चौहान सारवान]

हूं कि इन्होंने ये विकास किया है क्या ? अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गाँव मलिकपुर में एक 66 के.वी. सब स्टेशन बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है जो कि मेरे हल्के के निवासियों की मांग है। ग्राम पंचायत मलिकपुर इसके लिए भूमि देने के लिए तैयार है। इस सब स्टेशन के बनने से बराड़ा, अधोया तथा अन्य 20 गाँवों को फायदा होगा। इस सब-स्टेशन के निर्माण हेतु उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि इस सब स्टेशन को बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। इसके अलावा मेरे हल्के के गांव सरकपुर तथा आस-पास की पंचायतों ने माँग की है कि गाँव सरकपुर में एक डिग्री कॉलेज बनाया जाये जिसके लिए ग्राम पंचायत 10 एकड़ भूमि देने के लिए तैयार है। इससे छात्रों विशेषकर हमारी बेटियों को यमुनानगर, अम्बाला या शाहबाद इत्यादि कॉलेजों में नहीं जाना पड़ेगा तथा **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना** को भी बल मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि बराड़ा के थाने की बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। मेरी प्रार्थना है कि इस थाने के पुराने भवन को गिराकर नये भवन का निर्माण किया जाये। (विघ्न) जब पुलिस के जवान हमारी सुरक्षा की चिंता करते हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी उनकी चिंता करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बज़ट में कुछ नया देखने को मिलेगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जैसे पूर्व में बज़ट आते रहे हैं वैसा ही यह बज़ट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। सदन में बज़ट प्रस्तुत करने से पहले ही हरियाणा में वैट लगा दिया गया है तथा यह सरकार अब टैक्स-फ्री बज़ट लेकर सदन में आई है। मैं सरकार से यह आश्वासन व जवाब चाहता हूं कि क्या आने वाले एक वर्ष के समय में सरकार कोई नया टैक्स तो नहीं लगाएगी ? इसके साथ ही साथ हमें आपके इस बज़ट का अवलोकन करने से एक गंभीर बात का पता चला है जिस पर मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने श्वेत-पत्र तैयार किया। कर्ज की बात हम भी करते थे कि राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ा है जो 81836 करोड़ रुपये था लेकिन अब 26,000 करोड़ रुपये के ऋण का और बोझ राज्य सरकार पर डाला गया है। आपने 17 हजार करोड़ रुपये का बाजार से लोन लिया और करीब करीब 8 हजार करोड़ रुपये एस.बी.आई. से लेकर 26 हजार करोड़ रुपये का ऋण का बोझ प्रदेश पर डाला। 2008-09 में प्रदेश के ऊपर ब्याज की अदायगी का बोझ 2339 करोड़ रुपये था जो आज बढ़कर 8563.75 करोड़ रुपये हो गया है जोकि बहुत चिंता का विषय है। हरियाणा के ऊपर वर्ष 2004-05 में आकस्मिक देनदारियां 4209 करोड़ रुपये थी जो आज 27306 करोड़ रुपये हो गई हैं यानि 650 परसैंट हमारी देनदारियां बढ़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कर्जा भी ले लिया और ब्याज की अदायगी पर खर्चा बजट में बहुत कम कर देने से जो 5 या साढे 5 हजार करोड़ रुपये का गैप है इसको किस तरह से सरकार पूरा करेगी। क्या इसको टैक्सिस लगाकर पूरा करेंगें ? प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि आने वाले समय में सरकार बहुत बढ़िया बजट देगी। अध्यक्ष महोदय, बजट से यह पता चलता है कि आप कौन से काम करना चाहते हैं और कौन से असैट्स का निर्माण आप करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम कैपिटल एक्सपैंडीचर देखें तो केवल 1.44 परसैंट कैपिटल एक्सपैंडीचर आ रहा है।

सरकार के घोषणा पत्र में विकास के जो सब्जबाग दिखाए गए हैं मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार उसका अंशमात्र भी पूरा हो पाएगा। कैपिटल एक्सपैंडीचर वर्ष 2006-07 में 2.3 परसैंट, 2007-08 में 2.45 परसैंट और 2008-09 में 2.65 परसैंट था जोकि आज घटकर 1.44 परसैंट रह गया है। मैं समझता हूं कि जब वित्त मंत्री जी जवाब देंगें तो वे सारी बातें क्लीयर कर देंगें। कैपिटल एक्सपैंडीचर में असैट्स निर्माण नहीं होंगें तो किस तरीके से अपने घोषणा पत्र में सरकार ने जो वायदे किए हैं उनको पूरा कर पाएंगें । अध्यक्ष महोदय, यदि पूरे बजट का अवलोकन करें तो मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि मैं बजट में एक्सपर्ट नहीं हूं, लगभग 68 परसैंट के करीब जो पैसा है वह पैंशन में, सेलरीज में और इंट्रस्ट की पेमैंट में जा रहा है। (विघ्न) आप किस प्रकार से विकास कर पाएंगे इस बात की मुझे चिंता हो रही है। अध्यक्ष महोदय, कृषि के बारे में मेरे कई साथियों ने यहां चर्चा की। हमारा हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। खुद सरकारें मानती हैं, हम सब मानते हैं कि पूरे प्रदेश में लगभग 70 परसैंट लोग कृषि और खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि है और सैकेंड्री सैक्टर इंडस्ट्रीज है, दोनों को निवेश की दृष्टि से और प्राथमिकता के आधार पर नजरअंदाज कर दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद 15.3 परसैंट था जो अब 14.2 परसैंट रहने का अनुमान है और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में 27.71 परसैंट था जो अब 26.9 परसैंट रह जाएगा तो किस प्रकार से आज हम हरियाणा को आगे लेकर जाएंगें। आज कृषि के ऊपर हरियाणा वासी बहुत निर्भर करते हैं। सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का सब्जबाग दिखाया और पूरे देश में और प्रदेश में स्वामीनाथन रिपोर्ट का प्रचार कराया और लोगों को मानसिक रूप से तैयार कराया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी जिससे किसान का भला होगा और वह सोचेगा कि कोई किसान के आंसू पोछने आया है। आपने उस पर भी यू टर्न ले लिया। आपके समय में आज जीरी का रेट पिटा, किसान बेहाल हुआ और वह बेघर होने को है। आज आपके समय में आलू की फसल और दूसरी सब्जियों का रेट पिटा। जब हम 9 तारीख को यहां आए थे तब बारिश हुई और जब दोबारा 13 और 14 तारीख को आंए तो और भी ज्यादा बारिश हुई है। पूरे हरियाणा में किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। आज ठेके का हिसाब लगाएं तो 40-40 या 50-50 हजार रुपये सालाना ठेका है और आप 10 हजार रुपये मुआवजे की राशि दे रहे हैं जोकि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऐसा करके आप किस प्रकार किसानों के हमदर्द बनते हैं ? मैं समझता हूं कि इस पर हमारे सदन के नेता को पुनर्विचार करना चाहिए। चाहे इसके लिए सैंटर गवर्नमैंट से पैसे मांगे जायें क्योंकि प्रदेश के किसान को बचाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक भूमि अधिग्रहण बिल की बात है इस बारे में मैंने पहले भी कहा था कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव सदन को लाना चाहिए कि जो इस बिल में किसान विरोधी क्लाजिज हैं उनको हम निकालना चाहते हैं और हरियाणा की ये भावनाएं हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पास तो केन्द्र सरकार करती है लेकिन केन्द्र को हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाकर अपनी भावनाओं से अवगत तो करवा सकते हैं। इसी तरह से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके भेजा जा सकता है। हमें इस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि प्रदेश के किसानों को फायदा पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन जी ने थानों का जिक्र किया और मैं भी जिक्र करना चाहूंगा कि आज प्रदेश में माताओं और बहनों को थानों में जाकर खाद लेना पड़ रहा है। एक मेरे जैसा आदमी जुलाना शहर में घूम रहा था। मैं वहां नम्बरदार की दुकान पर हुक्का पीने जाता हूं। मुझे माफ करना मैं इस तरह की बात सदन में कर रहा हूं लेकिन पूरा सदन यह जानकर

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

हैरान होगा कि वहां एक औरत मेरे पास आई और मुझे राम-राम करने लगी। इतने में एक आदमी वहां आया और कहने लगा कि बहन जी 100 रुपये ले लो और खाद की लाईन में मेरी जगह लग जाओ ताकि मुझे खाद मिल जाये। इस तरह की हालत खाद को लेकर मेरे हल्के जुलाना में थी। अध्यक्ष महोदय, खाद को लेकर किसान इतना मारा-मारा फिरा कि मैं समझता हूं कि सरकार की एलोकेशन पूरी नहीं हुई। आज किसान के प्रति सरकार को विश्वास जताने की जरूरत है। बजट बना उससे पहले बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल को बहुत नुक्सान हुआ है। उसके लिए बजट में पैसे का विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए था और किसान पर भरोसा जताना चाहिए था लेकिन नहीं जताया गया यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात गवर्नर एड्रैस पर भी कही थी और आज भी कह रहा हूं कि सरकार ने कहा है कि कपास का मुआवजा बंट चुका है। मेरे क्षेत्र में तो बंटा नहीं है और पता नहीं कहा बंट गया। इस तरफ ध्यान दिया जाये। बजट में सिंचाई की भी बात की गई है। सिंचाई हमारे प्रदेश के लोगों की प्राथमिकता है। सिंचाई मंत्री जी अभी सदन में बैठे नहीं हैं इसलिए मैं वित्तमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि सरकार स्वयं मानती है कि हमें सिंचाई के लिए 36 एम.ए.एफ. पानी चाहिए और केवल 14 एम.ए.एफ. पानी उपलब्ध है। इतने कम पानी में किस प्रकार से सिंचाई होगी। कहा गया है कि एस.वाई.एल. कैनाल का निर्माण किया जायेगा, डैम का निर्माण किया जायेगा परंतु बजट में पैसे की कोई एलोकेशन नहीं की गई है। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा ? आज केन्द्र में, पंजाब में और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं फिर एस.वाई.एल. के निर्माण पर देरी किस बात की है। एस.वाई.एल. का पानी आना चाहिए। यह हमारा नैचुरल अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा की नहरी व्यवस्था करीबन 35-40 साल पुरानी है जिसके कारण पानी वेस्ट होता है और पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है। मैंने इस बारे में पिछले कार्यकाल में प्रश्न भी लगाया था और मेरे प्रश्न पर सिंचाई मंत्री जी ने चिंता जाहिर की थी कि हमारी नहरी व्यवस्था करीबन 35-40 साल पुरानी है। इसको एक प्रोजैक्ट बनाकर जिस प्रकार से पंजाब ने टेक ओवर किया है उसी प्रकार करने की आवश्यकता है। इसमें सभी रजवाहों, नहरों को दोबारा बनाना पड़ेगा। मेरे हल्के के बुआना और लुदाना माईनर्ज में पिछले दस साल से टेल तक पानी नहीं आ रहा क्योंकि उनका निर्माण ठीक से नहीं हुआ है। इसी तरह से मेरे हल्के के किला जफरपुर माईनर की बढ़ोत्तरी की बात थी। पिछली सरकार ने बढ़ोत्तरी करवाने का आश्वासन दिया था और काम भी शुरू हो गया था लेकिन अब रोक दिया गया है। इसी तरह से मेरे हल्के के बिरोली, न्यूकरेला, बिजवाना कलां नये माईनर बनाने की मेरी मांग मानी गई और सरकार ने घोषणा भी कर दी थी। मेरी आज भी मांग है कि इन तीनों माईनर्ज को बनाया जाये। यह बहुत जरूरी हैं इसलिए कैप्टन साहब मेरी बात ध्यान से सुन लें। अध्यक्ष महोदय, जिस समय नहरी डिवीजन बनाये गये थे उस समय ये क्या सोचकर बनाये गये यह बात मेरी समझ नहीं आ रही है ? उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि हमारे जींद डिवीजन में सुंदर सब ब्रांच और हांसी सब ब्रांच का 2.32 लाख एकड़ का एक डिवीजन बना दिया गया। वहां पर 1 एक्सीयन की, 3 एस.डी.ओ. की, 11 जे.ई.ज. की और 65 बेलदार की पोस्ट्स हैं। ये पोस्ट्स पिछले कई सालों से पूरी नहीं भरी गई हैं। कभी एक एस.डी.ओ. रहता है, कभी दो रहते हैं और कभी एक भी नहीं रहता। मैंने जींद डिवीजन के लिए पहले भी प्रपोजल दी थी कि इस डिवीजन को रिआर्गनाईज किया जाए और प्रदेश में दूसरे डिवीजन भी हैं जिनको रिआर्गनाईज

करने की जरूरत है। सुंदर सब ब्रांच में 1.18 लाख एकड़ जमीन और जींद ब्रांच में 1.14 लाख एकड़ जमीन करके दो डिवीजन बना दिए जाएं। हरियाणा में बहुत से ऐसे डिवीजन हैं जिनमें 1 लाख एकड़ से कम जमीन आती है। जींद डिवीजन में नया सिस्टम इस तरह का बनाया जाये ताकि उसकी देखभाल हो सके और लोगों को पानी मिल सके। आज हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। सुन्दर ब्रांच और हांसी ब्रांच हमारी जीवन रेखा है। इन दोनों के अंदर भी इनकी पूरी कैपेसिटी का पानी नहीं आ रहा है। पिछली सरकार जाते-जाते हमारी जींद ब्रांच का पानी भी 1600 क्यूसिक कर गई जब कि इससे पहले जींद ब्रांच का पानी 2400 और 2200 क्यूसिक था। आज हमारा जुलाना इलाका पानी की कमी की गम्भीर परेशानी से जूझ रहा है क्योंकि मेरे हल्के में नहरी पानी से ही लोगों की सभी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसका कारण यह है कि हमारे इलाके का अण्डरग्राउंड पानी अच्छा नहीं है। इन्हीं नहरों के पानी से हमारे यहां की सभी पेयजल योजनायें चलती हैं लेकिन इन नहरों के फेल हो जाने से, इन नहरों में पानी न आने से हमारी सभी पेयजल योजनायें भी ठप्प पड़ी हैं। आज यहां पर जिस प्रकार से पी.एच. लैवल की बात चल रही थी वहां पर भी इतना गंदा पानी है कि आप उसे पी नहीं सकते इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको रि-ऑर्गेनाईज किया जाये। इस पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए वित्तमंत्री द्वारा बजट में कोई एलोकेशन नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हरियाणा के सभी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की घोषणा की गई थी। पुलिस कर्मचारियों को भी पंजाब के समान वेतनमान देने की बात उस घोषणा पत्र में की गई थी लेकिन इस बारे में भी सरकार ने अब यू टर्न ले लिया है। मैं जिस विधान सभा में खड़ा हूं इस विधान सभा के कर्मचारी भी साथ लगती पड़ौसी पंजाब की विधान सभा के कर्मचारियों से कम से कम 10 हज़ार रुपये तक कम तनख्वाह ले रहे हैं। यह भी अन्याय किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से अपने प्रदेश के कर्मचारियों की अनदेखी करके हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे ? इसी प्रकार से आपने बेरोजगारों के बारे में कहा कि आप उनको 6000 रुपये और 9000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में भी बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा गैस्ट टीचरों और कम्प्यूटर ऑपरेटर्ज से वोट लेने के लिए उनके साथ बहुत से बड़े-बड़े फोटो खिंचवाये गये लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बन गई है तो उन्हें दुत्कार कर बाहर निकाल दिया गया है। इसी प्रकार से कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 1413 कर्मचारी हैं मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि वे गलत तरीके से लगे हैं या सही तरीके से लगे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला हैं। इनमें से कोई 4 साल से और कोई 6 साल से वहां पर काम कर रहा है। उनको अपना पेट पालने के लाले पड़े हुए हैं। वे इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे उसके बाद उनकी समस्या का कोई समाधान तो क्या निकालना था उनको नौकरी से ही निकालने का नोटिस जारी कर दिया गया। अगर सरकार द्वारा इस प्रकार के कार्य किये जायेंगे तो कैसे काम चलेगा ? मैं यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार इन्हीं वर्गों के समर्थन से और इन्हीं वर्गों का भला करने के लिए सत्ता में आई है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर पुनर्विचार किया जाये और पुनर्विचार करके इनकी समस्या का सही समाधान निकाला जाये। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था के मामले में माननीय वित्तमंत्री द्वारा केवल मात्र 3 करोड़ रुपये की ही वृद्धि की गई है। इसके साथ साथ यह दिया गया कि हम बेहतर तरीके से प्रदेश की रक्षा करेंगे

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

और महिला सिपाहियों की भर्ती करेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि 3 करोड़ रुपये की राशि में आज के समय में एक थाना भी नहीं बनता। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के लिए नई गाड़ियों की व्यवस्था कहां से की जायेगी ? आज हरियाणा के सिपाहियों को 303 राईफल्ज़ दे रखी हैं अगर वे कहीं सलामी देने जाते हैं तो उस समय वे नहीं चलती। इसका दोष भी उनके ऊपर ही लगा दिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे पुलिस के जवानों को नई राईफल्ज़ की आवश्यकता है और नई गाड़ियों की भी आवश्यकता है लेकिन इसके लिए एलोकेशन केवल 3 करोड़ रुपये ही की गई है। जवान जो 24-24 घंटे हमारी रक्षा करते हैं और पूरे प्रदेश की रक्षा करते हैं उनको आपको पंजाब के समान वेतनमान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, डिमाण्डज़ मेरी बहुत सी हैं। मैं यह समझता था कि सरकार अपने घोषणा पत्र पर 100 प्रतिशत अमल करते हुए पूरे प्रदेश को चहुंमुखी विकास के मामले में आगे लेकर जायेगी लेकिन आपने तो एक ऐसा अनोखा काम कर दिया जो कांग्रेस भी नहीं कर पाई। वह यह कि VAT की धारा 59 में संशोधन कर दिया। VAT की धारा 59 में यह प्रावधान था कि अगर VAT के ऊपर कुछ चेंज करना हो तो जनता 10 दिन तक एप्लाई कर सकती है लेकिन वर्तमान सरकार ने यह भी चेंज कर दिया। सरकार द्वारा धारा 60 को भी संशोधित कर दिया गया और जनता का नैसर्गिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार द्वारा श्वेत पत्र दिया गया है मैं इस श्वेत पत्र से सहमत हूं या नहीं हूं मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं यह मानता हूं कि सरकार द्वारा जो यह श्वेत पत्र जारी किया गया है यह बहुत अच्छी बात है। इसमें मुद्दे भी बहुत सही उठाये गये हैं। इसमें आपने यह भी माना है कि विकास और रोजगार सहित सभी मामलों में मेरे इलाके के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है। इसलिए मैं अपने इलाके से भेदभाव के लिए ही नहीं अपितु पूरे जींद जिले के साथ हुए भेदभाव को दूर करने के लिए मैं पूरे जींद जिले के लिए चाहे वह सफीदों हल्का हो, चाहे उचाना हल्का हो, चाहे नरवाना हल्का हो, चाहे जुलाना हल्का हो और चाहे जींद हल्का हो सभी के समग्र विकास के लिए सरकार से 5000 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करता हूं। मैं माननीय वित्तमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि क्या वे यह धनराशि हमें जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवायेंगे इस बारे में वे अपने जवाब में बतायें ताकि हमारे समस्त जींद जिले का समग्र विकास हो सके क्योंकि हमारे जिले की सारी की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं यहां तक कि हमारे जिले से गुजरने वाले जो नैशनल हाईवेज़ हैं वे भी पूरी तरह से टूटे पड़े हैं और पीने के पानी की भी किसी भी प्रकार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के हालात में हमारा पूरा क्षेत्र कैसे आगे बढ़ पायेगा? कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे जिले की हरेक मामले में बहुत ज्यादा बुरी हालत है। अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ डिमाण्ड्ज़ हैं। इनमें कुछेक तो पुरानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी हुई सड़कों की रिपेयर की हैं और कुछेक ऐसी हैं जो नई बनाई जानी हैं।

श्री अध्यक्ष : ढुल जी, इसके अलावा आपकी जो भी डिमाण्ड्ज़ रह गई हैं उन्हें आप हमें लिखित में दे दें हम उनको हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ में शामिल कर लेंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : ठीक है स्पीकर सर, मेरी जो डिमाण्ड्ज रह गई हैं मैं उनको आपके पास लिखित रूप में भिजवा देता हूं आप उन्हें हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ में शामिल करवा देना। धन्यवाद

श्रीमती प्रेमलता (उचाना कलां) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री और सरकार से एक प्रार्थना है कि हम जीन्द जिले से 5 विधायक हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की विधायक हूँ, 3 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल से हैं तथा एक निर्दलीय विधायक है। इसलिए हम सामूहिक तौर पर सरकार से माँग करते हैं कि हमारे जीन्द जिले के विकास के लिए उचित ग्रांट दी जाये जिससे कि जीन्द जिले का समुचित विकास हो सके।

Shri Kuldeep Sharma : Speaker Sir, this amount of Rs. 5,000 crores demanded by the five Legislators, I do not think it is a big demand. So, I would like to give a suggestion that out of this, Capt. Abhimanyu may contribute Rs. 2,000 crores and the rest of Rs.3,000 crores, Mrs. Prem Lata may demand from the Ministry of Rural Development, Government of India. तो 3000 करोड़ रुपये चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से दिलवाओ।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, उस पैसे को तो मैं नहीं मांग सकती लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री डिमांड करेंगे तो हरियाणा के लिए तो कुछ ज्यादा पैसा दिया ही जा सकता है।

श्री नसीम अहमद (फिरोजपुर झिरका) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले 5 साल से इस सदन का सदस्य रहा हूँ और पहले भी बजट पेश होते हुये मैंने देखे हैं। जब हमारी टेबल पर बजट की कॉपी पहुंचती है तो हम देखते हैं कि लगभग एक ही तरह का बजट यहाँ पर पेश किया जाता रहा है। इस बार भी सरकार ने कोई बहुत ज्यादा तबदीली नहीं की है। उसी तरह का बजट सरकार ने पेश किया है जिस तरह का बजट पिछली सरकार पेश करती थी। इस बार भी वही बात कही गई है कि कोई वैट नहीं बढ़ाया गया और न ही कोई नया टैक्स लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार यह आश्वासन दे कि हम इस बजट सत्र के बाद भी कोई नया टैक्स या वैट नहीं लगायेंगे तो हम इस बजट का तहेदिल से सराहना करेंगे और मान-सम्मान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए 3028.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि बहुत कम है क्योंकि आज पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप फैल रहा है। इसी प्रकार से कैंसर से मरने वालों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। एक जो अहम मुद्दा है वह है शिशु और मातृत्व मृत्यु दर के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। सरकार को स्वास्थ्य के बारे में खास तौर से सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम एक आम आदमी की जिन्दगी को बचा सकें क्योंकि दुनिया में जीवन से बहुमूल्य कोई चीज नहीं हो सकती। अगर जीवन को बचाना ही सरकार की प्राथमिकता नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग का बजट पर्याप्त नहीं है। अगर मैं मेवात जिले की बात करूँ तो मेवात जिले में एक मेडिकल कॉलेज जो कि पिछली सरकार ने बनवाया था, एक जनरल हॉस्पीटल, 3 सी.एच.सीज. और 10 पी.एच.सीज. हैं। मेवात में स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 जून, 2011 को माननीय श्रीमती सोनिया गाँधी जी ने जननी-शिशु सुरक्षा योजना का मांडीखेड़ा जनरल हॉस्पीटल में शुभारम्भ किया था लेकिन पूरे मेवात जिले में उस वक्त एक भी लेडी डॉक्टर नहीं थी। इससे स्वास्थ्य विभाग के प्रति सरकार की गम्भीरता का पता चलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेवात में स्वास्थ्य सेवाओं

[श्री नसीम अहमद]

में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया जाये क्योंकि मेवात में हमारा जो परिवेश है वह इस प्रकार का है कि हम बच्चों की शादी जल्दी कर देते हैं और अगर शादी जल्दी की जायेगी तो पहला बच्चा भी जल्दी हो जायेगा। उस स्थिति में अगर शिशु और मां को उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी तो मृत्यु दर बढ़ती चली जाती है। इसी तरीके से जो मेडिकल कॉलेज मेवात में बना तो वाकई में बड़ी खुशी हुई और गर्व भी हुआ कि चलो मेवात की भी किसी ने सुध तो ली। लेकिन स्पीकर सर, आज उस मेडिकल कॉलेज की हालत ये है कि वह केवल नाम का मैडिकल कालेज दिखाई देता है केवल उसकी बिल्डिंग ही दिखाई देती है लेकिन उसमें उपचार के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेवात के लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज वहां पर डॉक्टरों की पूरी टीम उपलब्ध नहीं है। वहां मेडिसंज उपलब्ध नहीं हैं। वहां की सारी मशीनरी को एक कमरे में बन्द कर रखा हुआ है क्योंकि उस अस्पताल में उचित ऑप्रेटर नहीं हैं। अध्यक्ष जी, वहां के मैडिकल कॉलेज की जो बुनियादी चीजें हैं जैसे वहां का ए.सी. और हीटिंग का प्लांट फेल हुआ पड़ा है। पानी की वहां पर इतनी बड़ी किल्लत है कि अगर कोई मरीज अपने साथ पानी की बोतल ना लेकर जाए तो हॉस्पीटल और मैडिकल कॉलेज के अन्दर पीने के पानी की कोई सहूलियत नहीं है। सर, वहां पर बिजली की इतनी समस्या है कि बार-बार वहां पर फॉल्ट हो जाने की वजह से बिजली चली जाती है कई-कई दिनों तक अंधेरे में रहना पड़ता है। इसी के साथ डॉक्टरों की जो समस्याएं है वह दूर होनी चाहिए, डॉक्टर तो वहां पर टिकना नहीं चाहते हैं। डॉक्टरों के लिए मेवात जैसे क्षेत्र में सरकार को स्पैशल स्कीम बनानी चाहिए। मेवात को देखकर पता नहीं क्यों यहां चण्डीगढ़ में बैठे अधिकारी या डॉक्टर ऐसे समझता है कि जैसे वह हरियाणा प्रदेश का हिस्सा ही नहीं है। वह तो कोई काला पानी या अण्डेमान व निकोबार का क्षेत्र है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर डॉक्टरों की एप्वाइंटमैंट की जाए और वहां पर डॉक्टरों की सैलरी के साथ उनको कुछ एक्सट्रा बेनीफिट भी दिए जाएं ताकि वह अपनी नौकरी अच्छे तरीके से कर सकें। गुड़गांव हमारे से बहुत नजदीक है तो हर कोई यह चाहता है कि हमें गुड़गांव में रहने का मौका मिले। लेकिन मेरे विचार में मेवात जैसे क्षेत्र में काम करके चाहे आपको दुनिया की सहूलियत न मिले लेकिन वहां काम करने के बाद दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए और उनको अतिरिक्त सैलरी भी दी जाए। इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश का ट्रांस्पोर्ट का जो सिस्टम है वह भी आपके सामने है। सर, पूरे हरियाणा में ढाई करोड़ की आबादी है उसमें केवल मात्र तीन हजार बसें सारे हरियाणा बेड़े की हैं जिससे ढाई करोड़ लोगों को इधर-उधर करने में बड़ी कठिनाई होती है। पिछली सरकार को ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट को अतिरिक्त बजट देने के लिए भी सोचना चाहिए था। इस बजट में सरकार ने ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट के लिए 5 हजार 541 करोड़ 14 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त हमारा क्षेत्र रेलवे लाईन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन बाकी पूरा हरियाणा जुड़ा हुआ है इसलिए वहां पर बसों की सुविधा और अच्छी हो इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिएं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि मेवात को जोकि दिल्ली वहां से इतनी नजदीक है। आगरा वहां से 150 किलोमीटर दूर है। जयपुर वहां से 150 किलोमीटर दूर है। आज मेवात में इण्डस्ट्रियल हब बनाने की सख्त जरूरत है। आज आई.एम.टी. जो रोजका- मेव में है। उसका जब से उद्घाटन किया है तब से वह ऐसे की ऐसे पड़ी है उसके बाद एक भी प्लॉट में इण्डस्ट्री नहीं आई है।

स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर जल्द से जल्द इण्डस्ट्री को विकसित किया जाए ताकि मेवात के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके और वहां पर मेवात के साथ-साथ गुड़गांव जिला है, पलवल जिला है, वहां के लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। स्पीकर सर, जब यहां बैठकर मेवात का नाम लिया जाता है तो पिछली सरकार भी यह कह देती थी और अब पता नहीं यह सरकार हमारे मेवात के बारे में कुछ करेगी या नहीं लेकिन हमें तो इस सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि पिछली सरकार ने तो हमें केवल आश्वासन ही दिए थे और मेवात को पिछड़ा हुआ क्षेत्र कह कर हमें बदनाम करने की कोशिश की गई थी। सरकार मेवात को पिछड़ा हुआ न कहे बल्कि यह कहना चाहिए कि सरकार की कमियों की वजह से मेवात पिछड़ा हुआ है। मेवात हर चीज में नम्बर-1 है पिछले दिनों मैं देख रहा था एक सवाल का जवाब था उसमें स्कूलों की एजुकेशन की बात आई थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे मेवात के अन्दर भी प्राईमरी एजुकेशन की बात की जाए हमारे वहां लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उसका सबूत ये है कि वहां पहली से पांचवी कक्षा तक 1 लाख 60 हजार 57 बच्चों की इन्रोलमैंट है। उसके बाद अगर हम 6 से 8 कक्षा तक की इन्रोलमैंट देखें तो वह एक दम गिर जाती है और वह केवल 42 हजार 605 बच्चों पर आ जाती है। इसकी वजह ये है कि वहां पर स्कूलों की बहुत भारी कमी है। जहां प्राईमरी एजुकेशन में स्कूलों की संख्या 593 है वहीं मिडल स्कूलो की संख्या 270 रह जाती है, हाई स्कूलों की संख्या केवल 45 रह जाती है और सीनियर सैकेंडरी में स्कूलों की संख्या केवल मात्र 30 रह जाती है। अध्यक्ष महोदय, 12वीं तक आते-आते बच्चों की संख्या भी केवल 3291 रह जाती है इसलिए अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से शिक्षा के मामले में मेवात में विशेष ध्यान दिया जाये क्योंकि मेवात हरियाणा प्रदेश और पूरे भारत में विकासशील क्षेत्रों में से एक है। इसके साथ-साथ मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि मेवात की अनदेखी और बेरुखी के कारण वहां के लोग आज पिछड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेवात में 1980 में एम.डी.ए. का गठन किया गया था। 1980 में मेरे वालिद साहब चौधरी शकरुल्ला खां जी जब इस सदन के सदस्य थे तब उनके प्रयासों से उस वक्त एम.डी.ए. (मेवात डवलैपमैंट एजैंसी) का गठन किया गया था। उसका मकसद यह था कि मेवात के अंदर जो पिछड़ापन है, जो कमियाँ हैं उनको दूर किया जाये लेकिन आज सरकार भी यह मानती है कि एम.डी.ए. बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसको दोबारा से जीवन देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, एम.डी.ए. में सुधार करने की बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि मेवात सिर्फ जो संस्था है उनके द्वारा नहीं है एम.डी.ए. के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है एम.डी.ए. का पैसा सिर्फ मेवात के लिए आता है। मेवात क्षेत्र अगर एम.डी.ए. बजट बढ़ाया जाये तो उससे काफी संख्या में लोगों की समस्याओं का हल हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, एम.डी.ए. का बजट 22 करोड़ रुपये का होता है वह बहुत ही कम है। बजट को बढ़ाकर कम से कम 100 करोड़ रुपये किया जाये ताकि मेवात में वहां की जनता का विकास किया जा सके। इसके अलावा एम.डी.ए. में सी.ई.ओ. नियुक्त है। डी.सी. साहब को चार्ज दे दिया जाता है क्योंकि उनके इतने काम होते हैं जैसे कोर्ट में जाना होता है इसके साथ-साथ जिले में भी बहुत सारे काम होते हैं। उनके पास एम.डी.ए. में बैठने के लिए टाइम नहीं होता है अत: मेरी मांग है कि एम.डी.ए. के लिए अलग से सी.ई.ओ. नियुक्त किया जाये ताकि वह एम.डी.ए. की पूरे तरीके से देखभाल कर सके और मेवात के लोग अपनी बात उस बोर्ड के समक्ष रख सकें। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेवात के लोगों के हित के लिए रेनीयैल प्रोजैक्ट वर्ष 2004 में शुरू किया था। उस वक्त हमारे इलाके में पानी की बहुत किल्लत थी उसको देखते हुए यह प्रोजैक्ट शुरू किया था। यमुना के

[श्री नसीम अहमद]

किनारे से पानी को लिफ्ट करवाकर के मेवात जिले में पहुँचाने का काम किया था लेकिन आज वह प्रोजैक्ट पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि ज्यादातर गाँवों में पीने के पानी की समस्या है। लोगों के घरों में टैंक बने हुए हैं। उसमें एक-एक हफ्ते के लिए पानी डलवा लेते हैं और उसी पानी को पीते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी (पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर) बैठे हैं। इस क्षेत्र के बारे में उन्हें अधिक मालूम है। इसके साथ पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के अधिकारी भी बैठे हुए हैं। मैं यह बात उनके भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वहाँ पर पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, इसका तुरन्त हल किया जाये, क्योंकि वहाँ पर लोग 700-800 रुपये में पीने के पानी के टैंकर मंगवाते हैं। पानी की समस्या को दूर करने के प्रयास किए जाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि यह समस्या अब दूर करवा लीजिए।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या जल्दी ही दूर कर देंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग की बात की जा रही है सरकार का इसमें क्या थ्यू है ? सरकार अल्पसंख्यक आयोग को ही खत्म करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में इस आयोग की सख्त जरूरत है क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग ही एक ऐसा आयोग है जो कि अल्पसंख्यकों के बारे में विचारविमर्श करता है। उनके बारे में देखा करते हैं इसलिए इस आयोग को खत्म न किया जाये बल्कि उसे और मजबूत किया जाये ताकि अल्पसंख्यक की आवाज पूरी तरह से उठाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, आज जो वक्फ बोर्ड डिपार्टमैंट है वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है लेकिन वक्फ बोर्ड की इतनी जमीन पड़ी हुई है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर उसको आईडेंटीफाई करें अगर उनसे सही मात्रा में रेवेन्यू कलेक्ट करें तो बजट में सहायता मिल सकती है लेकिन उसमें कई कमियों की वजह से या राजनीतिक संरक्षण की वजह से वक्फ बोर्ड को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जाये वक्फ बोर्ड के सिस्टम को दुरूस्त किया जाये ताकि रेवेन्यू में भी इजाफा हो सके। हरियाणा सरकार के पास जो वक्फ बोर्ड की जमीन पड़ी हुई है जिस पर लोगों के नाजायज कब्जे हैं, उनको भी संरक्षण मिल सके। अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड पर ध्यान दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड के लिए अलग से बजट का प्रावधान करें। वक्फ बोर्ड में मदरसों में जो मदारसी पढ़ाते हैं उनके लिए तनख्वाह की भी विशेष जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैंने पिछली सरकार से मेरे हल्के के लिए 5 साल में एक मांग रखी थी। हर सत्र में मेरी एक ही मांग रहती है कि फिरोजपुर झिरका के अन्दर एक सब-डिपो बनाया जाये। पहले फिरोजपुर झिरका के अन्दर सब-डिपो किन्हीं कारणों से खत्म कर दिया गया था। अत : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि उस सब-डिपो को दोबारा से बनाया जाये क्योंकि फिरोजपुर झिरका राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पर है। फिरोजपुर झिरका के साथ

अलवर और भरतपुर (राजस्थान) तथा मथुरा (उत्तरप्रदेश) के जिले लगते हैं। जन समुदाय का बालाजी देव स्थल (राजस्थान) नजदीक होने के कारण लोगों को वहां जाने के लिये बसें नहीं मिलती, इसलिए सब-डिपो के साथ-साथ बसों का बेड़ा भी बढ़ाया जाये जिससे लोगों को सही ढंग से आने-जाने के लिये सुविधा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, नगीना में ट्रेजरी की सुविधा न होने के कारण लोगों को रजिस्ट्री में स्टाम्प पेपर वगैरह खरीदने के लिये फिरोजपुर झिरका जाना पड़ता है और फिर नगीना आकर रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, इससे लोगो को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अत : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय वित्त मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि नगीना को सब तहसील का दर्जा देने के साथ-साथ वहां पर ट्रेजरी भी खोली जाये ताकि लोगों को अपने कार्य करवाने के लिये इधर-उधर न भटकना पड़े। पिछली सरकार ने नगीना से राजस्थान जाने के लिये तिजारा मार्ग की मंजूरी दी थी लेकिन आज तक उस मार्ग पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस मार्ग को तुरन्त बनवाया जाये अगर यह मार्ग बन जाएगा तो हमारे हल्के के लोगों को अपनी रिश्तेदारी व भाईचारे के कारण राजस्थान में जाने के लिए 45 किलोमीटर दूर तक का जो चक्कर लगाना पड़ता था उससे छुटकारा मिल जायेगा और लोगों को सुविधा हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात पहले भी बता चुका हूँ कि नगीना क्षेत्र में पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि केवल रेनीवैल प्रोजेक्ट के माध्यम से ही पानी की सप्लाई होती है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में सिंचाई विभाग के सिर्फ उमरा माईनर व बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री को छोड़कर कोई नाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अहमद जी, आप जल्दी वाइंड अप कीजिए।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध है कि मेरे हल्के में नहर का निर्माण करवाया जाये जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को भी पीने का पानी मिल सके। (विघ्न) हुड्डा साहब ने तो हमारे क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गुड़गांव से अलवर के लिए फोर लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर हुआ था लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी नूँह में पता नहीं क्या सोच कर फोर लेन की जगह दो लेन राजमार्ग का उद्घाटन करके चले गये। (विघ्न) इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि उस राजमार्ग को चार लेन किया जाये। जिस तरह से सम्पूर्ण हरियाणा में विकास की दौड़ चल रही है मेवात को भी उस दौड़ में शामिल किया जाये क्योंकि मेवात भी हरियाणा का अभिन्न अंग है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

डॉ० हरिचंद मिढ़ढा (जीन्द) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, जीन्द हल्के में 36 गांव व पूरा शहर आता है, इसलिए यदि मैं हर गांव व शहर की समस्या बता दूं तो बहुत ज्यादा समय लग जायेगा, जिससे बाकी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 36 गांवों में और पूरे शहर में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हल्के के लोग बार-बार मुझसे पूछते हैं कि डॉ० मिढ़ढा आपको क्यों एम.एल.ए. बनाएं, मैंने कहा कि मुझे एक बार फिर मौका दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब की बार नई सरकार आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सारी मांगे पूरी होंगी। (शोर एवं

[डॉ० हरिचंद सिद्धा]

व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आशा भी रखता हूँ और कोई गलती हो गई है तो माफी भी चाहता हूँ क्योंकि श्री अभिमन्यु के पास मंत्री और कैप्टन दो पद हैं और मैं भी एक्स सर्विस मैन हूँ, (शोर एवं व्यवधान) इसलिए मेरे ऊपर दया करना और प्यार रखना, मेरे हल्के में जो कमियाँ हैं उन्हें एक ही बार में दूर करना, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : सिद्धा जी, यदि आपको बोलने में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी स्पीच सदन के पटल पर रख दें, आपकी स्पीच को सदन की कार्यवाही में शामिल कर लिया जायेगा।

श्री हरिचंद सिद्धा : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी स्पीच सदन के पटल पर रख देता हूं। (इस समय स्पीच को सदन के पटल पर रखा गया) "अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2015-16 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमान जी, बजट पेश होने से पहले प्रदेश के हर व्यक्ति को एक उम्मीद होती है प्रत्येक व्यक्ति टकटकी लगाए देखता है कि बजट में प्रदेश सरकार कुछ न कुछ अच्छा देने का काम करेगी। लेकिन जैसाकि माननीय मंत्री जी ने जैसा बजट पेश किया है वो प्रदेश की आशाओं के अनुरूप नहीं है। प्रदेश सरकार ने चुनाव में जो चुनावी वादे सत्ता में आने के लिए किए थे यह बजट प्रदेश की जनता की उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।

पेयजल और सीवरेज :- श्रीमान् जी, अगर मैं जीन्द विधान सभा क्षेत्र की बात करूँ तो पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण क्षेत्र अपने इतिहास को भूलता जा रहा है। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी के कारण जन जीवन बहुत आहत और परेशान है। अध्यक्ष महोदय, जीन्द विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है जिसके चलते कैंसर और पीलिया की बीमारियां बड़ी तीव्रता से फैल रही हैं अगर मैं सीवरेज व्यवस्था की बात करूँ तो जीन्द की सीवरेज व्यवस्था ठप्प पड़ी है जिसके चलते आम आदमी का जीना दूभर हो गया है, इसलिए मेरी मांग है कि वित्त वर्ष 2015-2016 में जीन्द की सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

खेती :- अध्यक्ष महोदय, जीन्द विधान सभा क्षेत्र के गांव जाजबान, ढाण्डा खेड़ी, दरियावाला, बरसोला, बड़ोदी आदि गांव में नहरी पानी की कमी के कारण किसान बर्बादी की कगार पर है, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इन अन्नदाताओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक माईनर के निर्माण का प्रावधान सरकार इसी बजट में करे।

सड़क :- अध्यक्ष महोदय, जीन्द विधान सभा क्षेत्र का सड़क तंत्र बिल्कुल जर्जर स्थिति में है और जीन्द का बाईपास जो वर्ष 2008 से निर्माणाधीन है। मेरी सरकार से आशा है कि बाईपास के निर्माण को इसी बजट वर्ष में पूरा करने के साथ ही सड़क तंत्र को भी दुरुस्त करने का काम सरकार करें।

चिकित्सा :- अध्यक्ष महोदय, जहाँ प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, इसलिए जीन्द के सामान्य अस्पताल में आधुनिक मशीनों का लगाना, चिकित्सों की कमी को पूरा करना, सरकार इसी वित्त वर्ष में सुनिश्चित करने का काम करें।

शिक्षा :- अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अनदेखी का शिकार जीन्द क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा है, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि चौ. रणबीर सिंह विश्वविद्यालय को इसी वित्त वर्ष 2015-2016 में पूर्ण रूप से विकसित किया जाना चाहिए और शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए स्कूलों को अपग्रेड किया जाना चाहिए। श्रीमान् जी, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसाकि माननीय मंत्री जी ने बजट में पढ़ा है कि सबका साथ सबका विकास उसी वादे पर सरकार पूरी उतरे और जीन्द के विकास के लिए वित्त वर्ष 2015-2016 में एक विशेष पैकेज का प्रावधान सरकार सुनिश्चित करे। धन्यवाद।"

श्री रणबीर गंगवा (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कल वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सदन में बजट पेश किया है। मुझे इस बजट स्पीच को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ है। भाजपा ने चुनाव में जो वायदे बार-बार किये थे वे इस बजट में कहीं भी नजर नहीं आए। मुझ से पहले माननीय सदस्य ढुल साहब ने सदन में सारी बातें कह दी हैं कि आपने किस-किस तरीके से पहले कर लगाया और बाद में कर रहित बजट पेश किया। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री कृष्ण लाल पंवार चेयर पर पदासीन हुए।)** पिछली सरकार की भांति ही माननीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करने की परम्परा निभाई है। अभी हाल ही में सरकार गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक लेकर आई है। इसे प्रत्येक सदस्य ने मिलकर सर्वसम्मति से पास किया है। आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मूव करते हुए कहा कि गौमाता में 33 करोड़ देवी-देवता निवास करते हैं। हम सभी गाय को अपनी माता मानते हैं और मैं भी मानता हूं कि गाय में 33 करोड़ देवी-देवता निवास करते हैं। परंतु आज गाय की वास्तविक स्थिति कैसी है और गाय को किन हालात में रहना पड़ रहा है? आप देखिये कि गाय की शहरों के अंदर कैसी दुर्दशा हो रही है आज आम आदमी के लिए आवारा पशु संकट का प्रतीक बन चुके हैं। यह एक सच्चाई है और हम इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। आज आवारा पशुओं से अगर सबसे अधिक कोई परेशान है तो वह किसान है। किसान दिन-भर खेत में काम करता है और रात को दोबारा फसलों की रखवाली के लिए खेत में चला जाता है। अगर किसी दिन किसान बीमार हो जाए या उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ जाए तो उसकी फसल को आवारा पशु बर्बाद कर देते हैं। सभापति महोदय, आज हालत यह है कि किसान पहले अपने खेतों के चारों ओर कांटेदार तार लगाते थे लेकिन उन कांटेदार तारों को आवारा पशु अपने सींग से उखाड़ देते थे। इसलिए आजकल किसान अपने खेत के चारों ओर कांटेदार तारों की बजाए मजबूरन ब्लेड वाले तार लगाते हैं जिसके कारण जब अवारा पशु खेत में घुसते हैं तो वे उस ब्लेड वाले तार के साथ कट जाते हैं। जब ब्लेड वाले तारों से उन आवारा पशुओं के शरीर कट जाते हैं तो वे पशु लहूलुहान हो जाते हैं और फिर उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और वे आवारा पशु मर जाते हैं। सरकार गौ संवर्धन का विधेयक इस सदन में लेकर आई है और उस विधेयक में सजा देने का प्रावधान भी किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रकार से ब्लेड वाले तारों से मरने वाले आवारा पशुओं के बारे में भी कोई प्रावधान इस विधेयक में किया है कि जो पशु इस प्रकार मर रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार और दोषी है ? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यह विधेयक लेकर आई है यह अच्छी बात है लेकिन इन आवारा पशुओं पर तुरन्त प्रभाव से बैन किया जाए क्या ऐसा कोई

[श्री रणबीर गंगवा]

प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? सभापति महोदय, हमारे यहां किसानों में पशु मेले के बारे में बड़ा भारी रोष है कि पशु मेले को खोला जाए। आज पशु मेला न खुलने के कारण किसानों की जो 20000 रुपये और 30000 रुपये के बैलों की जोड़ी हैं वे बेकार हो रही है। जब बैल बेकार हो जाता है तो उस पशु को खुला छोड़ देते हैं और वह आवारा पशुओं की तरह घूमता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पशु मेलों को खोला जाए। सभापति महोदय, बजट भाषण में भी कहा गया है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। आज प्रदेश के बहुसंख्यक लोगों की आजीविका का साधन कृषि है। वर्तमान सरकार ने चुनावों के समय उन किसानों से वायदा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी। अब सरकार यह कहकर मजबूरी दिखा रही है कि यह सरकार उस रिपोर्ट को लागू करने में सक्षम नहीं है। आज किसानों की हालत यह है कि वह बिना संसाधनों के अपनी फसल पैदा करता है। जब वह अपनी फसल को बेचने के लिए बाजार में जाता है तो उसको उसकी फसल के वाजिब दाम नहीं मिलते। फसल के उत्पादन के लिए किसान को जो आवश्यक चीजें चाहियें जैसे खाद, बीज और दवाई वे चीजें उसको समय पर नहीं मिलती और इनके लिए उसे लाईनों में खड़ा रहना पड़ता है। पिछले दिनों यूरिया की हालत तो यह थी कि किसान अपने बीवी-बच्चों सहित लाईन में लगा रहता था और उसे तब भी यूरिया नहीं मिलता था। मंगाली गाँव का सुल्तान नामक एक किसान मुझे बता रहा था कि मैं तो बीवी-बच्चों सहित यूरिया लेने के लिए गया था सारा दिन लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें यूरिया खाद तो मिली नहीं और पीछे से तीन एकड़ गेहूं की फसल को आवारा पशुओं ने खराब कर दिया अब वह फसल काटनी नहीं पड़ेगी। आज ऐसी हालत हमारे प्रदेश में है। अगले साल किसानों को ऐसी दिक्कत न आये इसके लिए सरकार को देखना होगा और सरकार को इस तरह की व्यवस्था पहले ही करनी चाहिए। सभापति जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में भी कहा गया है कि सरकार हर खेत को पानी देगी। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। हमारे यहां हिसार जिले में नलवा, आदमपुर के साथ साथ लगते क्षेत्र लोहारू में जो ग्राउंड वाटर है वह खारा है। इसके लिए किसानों ने हिसार और सिवानी के अन्दर धरने दिए। माननीय मंत्री श्री धनखड़ साहब जो इस समय सदन में बैठे नहीं हैं वे वहां पर गये और उन किसानों से मिले थे और किसानों को आश्वासन दिया था। बड़े अजीब किस्म की बात है कि धनखड़ साहब खुद किसान हैं और किसान के बेटे भी हैं। उस समय इन्होंने कहा था कि बाड़सन डिस्ट्रीब्यूट्री का पानी 12 दिन चलेगा लेकिन अब 12 दिन में उस डिस्ट्रीब्यूट्री का पानी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जायेगा ? सभापति महोदय, या तो पानी 8 दिन के लिए दें अथवा 16 दिन के लिए दें। जो 12 दिन पानी देने के लिए कहा गया है वह भी देवसर डिस्ट्रीब्यूटरी का काटकर के बाड़सन डिस्ट्रीब्यूटरी में लगा दिया है। दूसरे किसानों का पानी उधर से काट दिया गया है तथा एक क्षेत्र के किसानों को उनके पानी के हक से वंचित रखना ठीक नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा ? सभापति जी, जब दिल्ली विधान सभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने चुनावी भाषणों में कहा करते थे कि अब हरियाणा में हमारी भाजपा की सरकार बन गई है इसलिए अब दिल्ली प्रदेश को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के हक का पानी हमें देने का काम करें तथा मेरी मांग है कि हमारे यहां का पानी दूसरे प्रदेश को नहीं जाना चाहिए।

श्री सभापति : गंगवा जी, कृपया आप कनक्लूड करें।

श्री रणबीर गंगवा : सभापति जी, अभी तो मैंने अपनी बात कहनी शुरू ही की है। (विघ्न) हिसार, फतेहाबाद और सिरसा इन 3 जिलों के किसान ढाणियों में रहते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ढाणियों में लाईट के प्रबंध के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। किसान को देश व प्रदेश का अन्नदाता माना जाता है। वह अपने खेत में केवल 2 कमरे ही बनाकर अपने बच्चों के साथ खेत में रहता है तथा आज उसको बिजली नहीं मिलती है परिणामस्वरूप किसानों को अंधेरे में ही सोना पड़ता है। आज मोबाईल व इंटरनैट का जमाना है लेकिन हमारे किसान जब बिजली कनैक्शन के लिए फार्म भरते हैं तब 5-7 लाख रुपये के एस्टीमेट बना दिये जाते हैं। सभापति जी, सरकार ने चुनावों के दौरान अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि वे हर ढाणी व हर घर को पानी व बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इस वायदे को पूरा करने का काम करे ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में प्रति माह 2000/- रुपये बुढ़ापा पैंशन करने का वायदा किया था, लेकिन वास्तव में केवल पैंशन के 1200/- रुपये प्रति माह ही किये गये हैं। इसी प्रकार से बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी कही गई थी जिसका इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। सभापति जी, प्रदेश के अंदर सड़कों की बहुत बुरी हालत है, वे जगह-जगह से टूटी हुई हैं। माननीय मंत्री महोदय, श्री नरबीर सिंह जी इस समय सदन में बैठे हुए हैं। मैंने इस बारे में इनसे निवेदन भी किया था।

श्री सभापति : गंगवा जी, कृपया आप वाईंड अप करें।

श्री रणबीर गंगवा : सभापति जी, ठीक है मैं अपनी बात बहुत जल्दी ही पूरी कर लूंगा। माननीय मंत्री जी ने सड़कों की रिपेयर और उन पर पेच-वर्क कराने की बात इस सदन में कही है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में हिसार-मंगाली-सहाड़वा जो सड़क है, उस पर मेरा निवास है। उसको सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो। इस एरिया में श्री अनूप धानक व श्री वेद नारंग माननीय सदस्यगण भी रहते हैं। श्री वेद नारंग जी की वहां पर जमीन है। मेरे घर के आगे सड़क पर पानी भरा हुआ था जिसको मोटर-ईंजन लगाकर निकलवाया गया। इस समस्या के बारे में मैंने माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी तथा माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि आप जब अपने क्षेत्र में जाओगे तो आपको एक्सीयन मिलेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का तो धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक्सीयन को फोन भी कर दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है क्योंकि एक बार फोन करने से एक्सीयन नहीं आता है। मैं तो एक्सीयन को 5-7 बार कह चुका हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। सड़कों पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे हल्के की कुछ सड़कें जिनमें कैमरी से देधा का कच्चा रास्ता, कैमरी से पातन, बूरे से हरेला, देवसर फीडर जो तोड़ी हुई है उसके ऊपर मंगाली रोड से सिंघरान तक तथा बीच का जो रास्ता बगीजोट के ऊपर है, उन सब सड़कों को पक्का करने का निर्माण कार्य करवाने का कष्ट करें ताकि किसानों को कोई दिक्कत न आने पाये। पिछली सरकार के समय में कुछ नगर निगम बने थे। जिसमें अम्बाला, करनाल, पानीपत, रोहतक 17.00 बजे और हिसार आए थे, जिसकी वजह से आउटर की कालोनियां और गांव निगम में शामिल हो गए थे। सभापति महोदय, मेरे हल्के के अंदर आजादनगर, अमरदीप आदि अनेक कालोनियां हैं जिनके अंदर सीवरेज की व्यवस्था नहीं है और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। इन कालोनियों में पानी की समस्या बहुत भारी है।

श्री सभापति : गंगवा जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रणबीर गंगवा : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपने हल्के की समस्याएं कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा।

श्री सभापति : गंगवा जी, आप एक मिनट में अपनी बात कम्पलीट करें।

श्री रणबीर गंगवा : सभापति महोदय, नगर निगम के अंदर अनेक ऐसी कालोनियां हैं जिनकी हालत गांवों से भी ज्यादा खराब है। वहां न तो सड़कें बनी हुई हैं और न ही गलियां बनी हुई हैं। उन कालोनियों में हाउस टैक्स और प्रोपर्टी टैक्स भी लगाए जा रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि उन कालोनियों के लिए कोई स्पैशल पैकेज दिया जाए। मुख्यमंत्री महोदय जी ने हिसार हल्के के लिए तो हां कर दी इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि नलवा क्षेत्र के लिए अलग से व्यवस्था की जाए ताकि वहां के लोगों की दिक्कतें और परेशानियां दूर हो सकें। सभापति महोदय, अंत में मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि बजट के माध्यम से आपने बहुत से वायदे किए थे लेकिन आपने किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू न करके और किसान की फसल की अच्छी कीमत न देकर और कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान न देकर उनकी तनख्वाहें खाने का काम किया है और सरकार बुजुर्गों की पैंशन खा गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : गंगवा जी, आप बैठिए आपका समय समाप्त हो गया है। राजदीप फौगाट जी आप अपनी स्पीच शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति महोदय, बुजुर्गों को पैंशन देने के लिए हमने इनके नेता का ही सुझाव माना था उसके बाद भी ये हमें उलाहना दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदय, आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। मैं सुबह से आपसे समय की मांग कर रही हूं लेकिन आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : गीता भुक्कल जी, राजदीप फौगाट के बाद आपको समय दिया जाएगा।

श्री राजदीप फौगाट(दादरी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, बजट में बहुत सी बातें सुनने को, देखने को और पढ़ने को मिली। अगर हम शिक्षा की बात करें तो मैं दादरी क्षेत्र का छोटा सा जिक्र करना चाहता हूं। दादरी में 4 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट बिल्डिंग्ज में चल रहे हैं और सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सभापति महोदय, आप यकीन नहीं करेंगे कि चारों के चारों स्कूल स्लम बस्ती में हैं और एक भी स्कूल में शौचालय नहीं है, बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है, बिजली का कनैक्शन नहीं है। ये सारे सरकारी स्कूल हैं। इनमें से कोई स्कूल 60 सालों से चल रहा है तो कोई 70 सालों से चल रहा है लेकिन किसी भी स्कूल में शौचालय नाम की चीज नहीं है। जब हमने वहां के टीचर्स से पूछा कि बच्चे शौचालय के लिए कहां जाते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि बच्चे शौचालय के लिए अपने घर जाते हैं और फिर वापिस स्कूल नहीं आते हैं। सभापति महोदय, इस प्रकार का आज का शिक्षा का माहौल है। दादरी के इन 4 स्कूलों के अलावा प्रदेश के 700 स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग्ज में चल रहे हैं और हर स्कूल का यही हाल है, एक भी बिल्डिंग में सफेदी नहीं हुई है और न ही कोई रिपेयर की व्यवस्था है। बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनकी हालत को कैसे सुधारा जाएगा ?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाए क्योंकि इन स्कूलों में शौचालय, सफाई व्यवस्था या बिजली का कनैक्शन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि बच्चे वहां पर अच्छे तरीके से पढ़ सकें। मैं सरकार से एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि दादरी सबसे बड़ा उप मण्डल है। वहां एक भी सरकारी कालेज नहीं है और एक भी खेल स्टेडियम नहीं है। खेल मंत्री जी बैठे हैं मेरा अनुरोध है कि वे इस तरफ विशेष ध्यान दें। वहां पर बच्चे रोड़ पर और खेतों में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। मेरी यह चिंता ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मैं रणजी ट्राफी का खिलाड़ी रहा हूं और मेरा खेल के प्रति विशेष रूझान रहा है। मंत्री जी दादरी में खेल स्टेडियम बनाने की तरफ विशेष ध्यान दें। इस बारे में हर बार यही कहा जाता है कि पिछली सरकारों ने पैसा नहीं छोड़ा और प्रदेश कर्ज में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के हर जिले के मुकाबले भिवानी जिले की अनाज मण्डियों में सबसे ज्यादा जिंस की खरीद होती है और भिवानी जिले में भी दादरी की मण्डी में सबसे ज्यादा जिंस की खरीद होती है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि दादरी की अनाज मण्डी में जिंस की खरीद इतनी अधिक होती है कि वहां से जो मार्केट फीस और सेल्स टैक्स का पैसा आये उससे एक और हल्का गोद लेकर उसका विकास कार्य करवाया जा सकता है। सरकार अगर मेरी इस बात को मान ले तो ऐसा हो सकता है। दादरी की अनाज मण्डी में सरसों की 3-4 हजार बोरियों की अवैध खरीद रोज होती है और यह संख्या सीजन के समय में 20 हजार बोरियों तक पहुंच जाती है। इस तरह से आज के दिन दादरी की अनाज मण्डी में 8-10 लाख रुपये के जिंस की अवैध रूप से खरीद रोज हो रही है। यदि वहां जायज खरीद हो और सेल्स टैक्स तथा मार्केट फीस पूरी मिल जाये तो प्रति दिन 10 लाख रुपये से अधिक की आमदनी हो सकती है। सभापति महोदय, यदि पूरे सीजन की बात की जाये तो रोज 20 लाख रुपये से अधिक के जिंस की अवैध खरीद प्रति दिन होती है। यदि यह सारी रकम जोड़ दी जाये तो सरकार से एक रुपये भी लेने की जरुरत नहीं है। दादरी हल्के के साथ-साथ एक और हल्के का विकास कार्य वहीं के पैसे से हो सकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह अवैध खरीद बंद की जाए। इसके लिए ज्यादा जानकारी लेने की जरुरत नहीं है। वहां 8-10 मिल हैं और हर मिल का हर महीने का 10 लाख रुपये से अधिक का बिजली का बिल आता है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां जिंस की अवैध खरीद किस तरह से हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी बड़ी ईमानदार छवि के इंसान हैं इसलिए ईमानदारी से वहां अवैध खरीददारी बंद की जाए और दादरी हल्के का विकास किया जाये। इस अवैध खरीद से वहां का आढ़ती, किसान और मजदूर बहुत परेशान है। सभापति महोदय, इसी तरह से दादरी में सी.सी.आई. सीमेंट फैक्ट्री है। हमारे माननीय मंत्री धनखड़ साहब का मकान भी उसके पास है और मेरा मकान भी वहीं है। यह सीमेंट फैक्ट्री वर्ष 1930 में बनी थी और पिछले 20 साल से बंद पड़ी है। जिस समय यह फैक्ट्री बनी थी उस समय हरियाणा की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन चरखी दादरी की थी। वहां करीबन 450 ट्रक उस समय थे। मैं सरकार से भरोसा चाहूंगा कि इस सीमेंट फैक्ट्री को दोबारा से शुरु करवाया जाये। इसकी 300 एकड़ जमीन है जो बंजर पड़ी है और जंगल बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना वार्ड पहले फाटक के जरिये शहर से जुड़ा हुआ था। चार साल पहले वह फाटक इसलिए बंद कर दिया गया कि रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जायेगा। रेलवे स्टेशन का विस्तार तो अभी तक नहीं हुआ है लेकिन हम शहर से अलग जरुर हो गये हैं। बहुत से गांव वाले भी शहर को उसी

[श्री राजदीप फौगाट]
फाटक से जाते थे। वहां पर अंडर पास बनाने की लोगों की मांग है। इसके लिए आंदोलन भी किया गया था और करीबन एक महीने पहले जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी को भी लैटर लिखा गया था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। आंदोलन के दौरान यह भी कहा गया था कि वहां अंडर पास बनाया जाए वरना लोग रेल रोको आंदोलन भी करेंगे। मैं माननीय सी.एम. साहब से यह अपील करूंगा कि वे इस अण्डर पास को जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करें और अगर सम्भव हो सके तो इसे इसी महीने के अंदर-अंदर कम्पलीट करवाया जाये। यह हमारी कालोनी और आस-पास की गांवों की एक बहुत महत्वपूर्ण डिमाण्ड है। इसके साथ ही साथ यह मेरी व्यक्तिगत परेशानी भी है और माननीय कृषि मंत्री महोदय भी इसके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इनकी धर्मपत्नी भी जब टीचर थी तब उनका भी यहीं से आना-जाना था। अगर ये अब भी दादरी रहेंगे तो इनका भी वहीं से आना-जाना होगा और इनके लिए भी यह अण्डरपास सबसे ज्यादा काम आयेगा। अब मैं पार्कों के बारे में बात करना चाहता हूं। आज से लगभग 50 साल पहले दादरी में एक पार्क बना था लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी पार्क नहीं बना इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार पार्कों के बारे में विचार करे कि दादरी के सौन्दर्यीकरण के लिए दादरी में अधिक से अधिक पार्क बनाये जायें। एक डिमाण्ड मैं सरकार से और करना चाहता हूं कि बौंद हमारे उपमण्डल का बहुत बड़ा गांव है यहां पर एक कालेज है। उस कालेज में न तो साइंस के विषय पढ़ाये जाते हैं और न ही कॉमर्स के विषय पढ़ाये जाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस कालेज में साइंस और कॉमर्स के विषय जल्दी से जल्दी शुरू किये जायें। इसी प्रकार से बौंद में एक कच्ची अनाज मण्डी है जो कहने भर को ही कच्ची मण्डी है लेकिन जब इसमें अनाज आता है तो उसे बौंद कालेज के ग्राऊण्ड में उतारा जाता है जिससे बच्चे वहां पर खेल भी नहीं सकते और इससे किसानों को भी बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि बौंद में जल्दी से जल्दी एक पक्की मण्डी का निर्माण करवाया जाये ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। किसानों का अनाज सही जगह पर रखा जा सके और इसके साथ-साथ उनके रहने की भी समुचित व्यवस्था की जाये। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)**

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने यहां पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ टैक्स फ्री बजट पेश किया। लोग सोच रहे थे कि अच्छे दिन आयेंगे, अच्छे दिन आयेंगे लेकिन जैसा कि पहले केन्द्र सरकार का बजट आया और अब राज्य सरकार का बजट आया। जब लोगों ने इन दोनों बजट प्रस्तावों को देखा तो उन्हें लगा कि उन बेचारे लोगों को अच्छे दिनों के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक विज़न डाक्यूमैंट के रूप में बात कही गई। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वयं एक बहुत अच्छा विज़न है लेकिन उन्होंने यहां पर जो अपना अभिभाषण पढ़ा उसमें कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र और बजट का कोई मेल नहीं है। इस प्रकार से एक पूरी तरह से बेमेल बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ है। आज चाहे मैं अपने हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की बात करूं, चाहे अन्नदाता किसानों की बात करूं, चाहे गरीबों की बात करूं, चाहे मैं हरियाणा प्रदेश के दलित लोगों की बात करूं, चाहे बुजुर्गों की

बात करूं, चाहे महिलाओं की बात करूं, चाहे युवाओं की बात करूं या फिर हरियाणा प्रदेश के बेरोजगारों की बात करूं ये सभी उम्मीद कर रहे थे कि शायद हरियाणा के वित्त मंत्री महोदय जब बजट प्रस्तुत करेंगे तो वे बहुत सारी चीज़ें जिनका महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र नहीं किया गया है, वे उन चीजों पर ज़रूर ध्यान देंगे। ये लोग आशा की नज़र से माननीय वित्त मंत्री महोदय की तरफ मुंह बाये देख रहे थे लेकिन उन्हें कुछ मिलना तो दूर की बात इसके विपरीत उनके ऊपर लाठीचार्ज़ हो रहा है। प्रदेश का हर वर्ग इस समय धरना देने और जलूस निकालने के लिए तैयार बैठा है। जैसे भाई राजदीप जी फौगाट ने कहा कि हम रेल रोको आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश का प्रत्येक कर्मचारी अपने आपको ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे रेलवेज़ की बात हो और चाहे रोडवेज़ की बात हो हमारी सरकार के समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा का सर्वांगीण विकास किया। जिस टीम इण्डिया में हरियाणा का स्थान होने की बात की जा रही है उस टीम इण्डिया में तो हरियाणा का नाम और स्थान हमेशा-हमेशा अव्वल रहा है। जो यहां पर बजट पेश किया गया है उस पर चर्चा के दौरान बार-बार यह बात उठकर सामने आ रही है कि पुरानी सरकार ने बहुत से कांटे बोये हुए हैं और बहुत से गड्ढे बनाये हुए हैं इसलिए पहले उनको भरने का काम किया जायेगा। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या यह सरकार अभी तक गड्ढों में ही खड़ी है। (शोर एवं व्यवधान) अब तो सरकार को यह चाहिए कि एक सही रोड मैप तैयार करके प्रदेश की चहुंमुखी तरक्की के रास्ते पर तेज़ी के साथ आगे बढ़े। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सत्तापक्ष के साथियों से कहना चाहती हूं कि ये सभी एक साथ क्यों खड़े हो जाते हैं ? मैं इनको यह भी कहना चाहती हूं कि ये पहले मेरी पूरी बात सुन लें और उसके बाद उसके जवाब दे दें। अध्यक्ष महोदय, जो गड्ढों वाली बात है वह तो ठीक है लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि अब ये जो बोयेंगे वही इनको आगे काटना पड़ेगा। इसलिए अब तो इनको उन गड्ढों को भरने और रोड मैप तैयार करने का काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अगर मौजूदा सरकार द्वारा कांटे बोये जायेंगे तो इनको भी कांटे ही मिलेंगे। मैं यह बात भी विश्वास के साथ कह सकती हूं कि प्रदेश की जनता तो अभी से मौजूदा सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। जो कार्य हमारी सरकार ने किये उसी में से आपने अन्त्योदय अन्न योजना की बात कही और बड़ी ही खूबसूरती के साथ उसको डिफाईन भी किया कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी इसका लाभ पहुंचेगा। इस बजट के बारे में मुझे बताया जाये कि इसमें कहां है किसी गरीब के बारे में कोई योजना और कहां है किसी दलित के बारे में कोई विशेष योजना ? इस प्रकार की गरीब और दलित हितैषी योजनाओं का इस बजट में कहीं पर कोई उल्लेख तक भी नहीं किया गया है। अगर आप गरीबों को अनाज देने की बात कर रहे हैं तो वह तो हम शुरू से ही दे रहे थे। हमने तो उसमें दाल-रोटी योजना जोड़ रखी थी। हम उनको चावल दे रहे थे, मोटा अनाज भी दे रहे थे और दालें भी दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय, यह जो 2015-16 का जो बजट है इसकी न तो कोई दशा है और न ही कोई दिशा है केवल अगर है तो इन लोगों की दुर्दशा है। इस बजट को देख कर पता चल रहा है कि किस तरह से अनुभवहीन लोग सत्तासीन हो गये। आज हमारी हरियाणा की जनता वोट देकर बहुत पछता रही है। अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से चुनावी वायदे किये थे। इन्होंने 169 वायदों का घोषणा पत्र जारी किया था। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं।

[श्रीमती गीता भुक्कल]

लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वायदे करके केन्द्र की सत्ता हथिया ली और इसी तरह से झूठे वायदे करके प्रदेश की सत्ता हथिया ली। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, ये झूठे वायदे की बात कहाँ से आ गई है, अभी तो एक-एक वायदे पर काम चल रहा है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, जितने वायदे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किये हैं उनसे ज्यादा काम तो हमारी कांग्रेस की श्री. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार ने किये हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने हाउस से श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी और श्री कुलदीप शर्मा जी की नेम प्लेट तो उतार दी लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि आज प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री जो उद्घाटन कर रहे हैं वे सभी हमारे समय में शिलान्यास किये गये प्रोजेक्टों के ही उद्घाटन कर रहे हैं। हम आपका स्वागत तो तब करेंगे जब आप शिलान्यास करें और जिन परियोजनाओं के हमने शिलान्यास किये हुये हैं उन पर काम शुरू करवायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने पंचकूला में संस्कृत विद्यालय का पत्थर लगाया था, आज वह पत्थर गायब है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। क्या योजना आयोग सही नहीं था जो आपने उसको बदल कर नीति आयोग बना दिया। National Institute for transforming India, वही काम वही योजनाएं वही सब कुछ, बस नाम बदल दिया गया। शायद नाम बदलने का, नामकरण का सरकार को शौक है। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय सदस्या बड़ी विदुषी सदस्या हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है कि हरियाणा के बजट प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और वे केन्द्र की योजना आयोग की और नीति आयोग पर भाषण दे रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : क्या आपके भाषण में केन्द्र के नीति आयोग का जिक्र नहीं किया गया है ? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हालाँकि अभिभाषण में इसका उल्लेख है लेकिन मेरा कहना यह है कि नीति आयोग केन्द्र का विषय है। वित्त आयोग जो भी बनेगा वह केन्द्र से बनेगा उसका उल्लेख करना एक अलग बात है लेकिन उसकी नीतियों का निर्णय केन्द्र का विषय है। हम यह भी बता देते हैं कि वह अच्छा निर्णय हुआ है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि राज्यपाल महोदय का बहुत अच्छा विज़न है लेकिन उनसे यह क्या पढ़वा दिया गया ? वित्त मंत्री जी ने भी वही पढ़ दिया जो उनसे पढ़वा दिया गया है। इनको मालूम होना चाहिए था कि नीति आयोग का इसमें जिक्र किया गया है, इसलिए मैंने यह जिक्र किया है। इसी प्रकार से अगर पंजाब के समान वेतनमान देने की बात की जाये तो जब भी रूल्ज की बात की जाती है तो हम पंजाब रूल्ज को फोलो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान दिये जायेंगे, लेकिन अब क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ? आज कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही

है और वे सड़क पर धक्के खा रहे हैं। इसी प्रकार से सेवानिवृत्ति की उम्र की बात की जाये तो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 58 साल करने की अफवाह फैलाई जा रही है। कहाँ तो हमने 60 साल एज की थी उसको भी कम करके 58 साल कर दिया गया है तथा श्रेणी-IV के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से घटाकर 60 साल कर दी गई है। इस सरकार का एक ही एजेंडा है कि No appointment only retirement. इस सरकार द्वारा अभी तक कोई नौकरी नहीं निकाली गई है बल्कि हमारे समय में जिनके रिजल्ट्स आउट हो गये थे उनको भी ज्वाईन नहीं करवाया जा रहा है। ना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों को सपने दिखाए गये थे। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : कैप्टन साहब, आप तो मंत्री हैं। आपका तो हक ही नहीं बनता बीच में बोलने का।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो समय मिला है मैं उस पर बोलूंगी और मैं एक बात कलियर करना चाहूंगी कि यहां पर जो भी चुनकर आया है वह माननीय विधायक है। चाहे वह महिला हो या पुरुष हो सबको इस सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है और वह बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात विधान सभा में रखेंगे। हमारे प्रदेश का युवा बड़ी आँखें फैलाए देख रहा था। बेरोजगार युवा घूम रहा था। यहां स्कील डवेलपमैंट की बात की गई। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात कही गई। वित मंत्री जी उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज हमारा यंगिस्तान जो हमारा भारत देश है वह एक युवा देश है। हरियाणा में हमारे युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया गया क्योंकि डिमांड किसी चीज की है और सप्लाई पर कोई और काम हो रहा है। बहुत ही मिस मैच है। हमें उसको बड़ी गम्भीरता के साथ देखना चाहिए था। आपने कर्जा बढ़ाने की बात कही है अगर प्रदेश हित में कोई कर्जा लिया जाता है उसमें कोई बुरी बात नहीं है आपने भी कर्जा लिया है। लेकिन आप प्रदेश हित में इस बजट में जो भी आपने घोषणा पत्र में बातें कही हैं उनको पूरा करने का काम करें। हमारे सभी सम्मानित साथियों में जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी शामिल हैं, हमारी पार्टी के साथी भी शामिल हैं और भी सभी पार्टियों के साथी शामिल हैं। उन्होंने अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की बड़ी-बड़ी मांगे रखी गई और कहा गया लेकिन मैं नहीं मानती कि उस चीज का जिक्र कहीं भी इस बजट में हो पाया है। क्योंकि अभी तक विधायकों के लिए नीधि कोष की मांग चाहे आप सत्ता पक्ष मे बैठे हैं या हम विपक्ष में बैठे हैं लेकिन यह बात हमेशा उठती रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मंत्रियों का डिस्क्रीशनरी ग्रांट बढ़ाया है। हम यह मांग करते हैं कि विधायक निधि कोष की भी शुरूआत की जाए ताकि हम अपने-अपने हल्कों में विकास के कार्य कर सकें और आपके बजट में विधायक आदर्श योजना (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं बार-बार कह रही थी कि जब INLD के सदस्य बोलते हैं तो BJP के सदस्य नहीं बोलते, जब BJP के सदस्य बोलते हैं तो INLD के सदस्य भी नहीं बोलते लेकिन जब हम बोलते हैं तो सारे लोग बोलते हैं। पता नहीं क्या बात है। अध्यक्ष जी बजट में जो विधायक आदर्श योजना की बात कही है वह पार्लियामैंट में सांसदों को भी एक-एक आदर्श गांव बनाने की बात कही गई है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी सम्मानित साथी ने कहा कि जब BJP के सदस्य बोलते हैं तो हम नहीं बोलते और जब हम बोलते हैं तो ये भी नहीं बोलते। इनसे कोई पूछने वाला हो हमारे किस साथी ने आपको बोलने से मना किया।

श्रीमती गीता भुक्कल : आपका धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला : जो बात आपने पहले दोहराई थी ****** (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : आप मुझे धमकाने की कोशिश मत करो भाई साहब, आप अध्यक्ष जी से बात करो।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आप इनको यह समझाओ कि ये हमें बेवजह छेड़ने का प्रयास न करें। इनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है इन्होंने अपने पिछले 10 साल में इस प्रदेश की हालत बहुत खराब बनाकर छोड़ दी है। ये मैडम पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थी। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। ये यहां शिक्षा की बात कर रही हैं और शिक्षा की बात करते-करते नई युनिवर्सिटीज बनाने की बात आ गई कि हम दो-तीन नई युनिवर्सिटी बना रहे हैं और इनकी हालत उस समय ये थी कि थोड़ी देर पहले इन्होंने यह बताया कि जो दसवीं कक्षा के रिजल्ट आए हैं उसमें 50-50% बच्चे स्कूलों में फेल हो गये। उनमें से 50 ऐसे स्कूल थे जिनमें से एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। इनकी ये हालत थी। इनके पास कहने को तो कोई बात है नहीं, फिजूल में आपका समय भी खराब करते हैं और हमारा भी करते हैं। इससे अच्छा आप हमारे सदस्यों को बोलने का समय दो जो अच्छी बात करेगा और प्रदेश के हित की बात करेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि विधायक आदर्श गांव परियोजना की बात कही है कि कोई बजट का प्रोविजन नहीं है। हमारे सांसद भाई दीपेन्द्र हुड्डा जी ने मेरे हल्के के छुछकवास गांव को गोद लिया है। अब लोग यह कहते हैं कि आप क्या-क्या करेंगे बजट का तो कोई प्रावधान नहीं है। अधिकारियों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि बजट का कोई प्रावधान नहीं है। वहां बाईपास भी चाहिए, उसकी स्किल डिवल्पमैंट के लिए सैंटर भी चाहिए। जोहड़ों की बात मैंने कही तो इसी प्रकार से कहीं ऐसा न हो जैसाकि मुख्यमंत्री जी अपनी रिप्लाई में कहा था कि हम सारे के सारे गांवों को आदर्श गांव बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सरकार इस बजट में पूरी तरह से प्रावधान करने की बात कहे। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं समझती हूँ कि इस पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह एक सामाजिक मुद्दा है इस बारे में सरकार ने हरियाणा प्रदेश की बेटियों की चिन्ता की है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पानीपत जिले में इस योजना की शुरूआत की। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार के समय में जो समेकित योजनाएँ थी जैसे प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना, लाडली योजना और लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादि उनके नाम बदलकर नई-नई योजनाएँ बना दी लेकिन योजनाएँ तो वही हैं, इसमें थोड़ा बहुत पैसा जरूर बढ़ाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने का काम किया। हम शिक्षा के अधिकार कानून, सैंट्रल एक्ट हरियाणा प्रदेश में लेकर आये अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शिक्षा को बहुत अच्छे ढंग से हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया। हमारी सरकार ने 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और कम्पलसरी अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, आरोही मॉडल स्कूल बनाये कस्तूरबा गांधी स्कूल बनाये मॉडल संस्कृति स्कूल बनाये और 2025 स्कूलों को भी अपग्रेड करने का काम किया जिससे हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात क्लीयर कर देना चाहती हूँ कि शिक्षा के अधिकार कानून को लेकर बहुत सारे सदस्यों ने

कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षा प्रणाली का भट्ठा बिठा दिया। (शोर एवं व्यवधान) मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि इतने सारे स्कूल, 58 आई.टी.आई., 48 कॉलेजिज, एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी, एक नैशनल डिफैंस यूनिवर्सिटी, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई, एक मीरपुर में यूनिवर्सिटी बनाई, जींद जिले में चौधरी बंसीलाल जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई और इसके साथ-साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई। अध्यक्ष महोदय, क्या इसको शिक्षा का भट्ठा बिठाना कहते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा इन्टरवेशन है। आपकी अनुमति से मैं आदरणीय माननीय सदस्या पिछली सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री भी थी और बड़े जिम्मेदारी वाले विभाग इनके पास थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जिस क्षेत्र से आती हैं उस क्षेत्र में सितम्बर 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने भातनहेल गाँव में मिलिट्री स्कूल का शिलान्यास किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूं कि शायद कहीं न कहीं आपका भी संबंध गाँव भातनहेल से है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहती कि मैं उस गाँव की बेटी हूं और जो बात इन्होंने कही है, मैं उसका भी जवाब दूँगी।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने शिक्षा के नाते जो डिफैंस यूनिवर्सिटी की बात की। सितम्बर 2003 में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में दाल रोटी और अन्न योजना की घोषणा हुई थी। पिछले 10 साल तक आपकी सरकार ने उन घोषणाओं का श्रेय लिया। माननीय सदस्या उस पर पर्दा डालना चाहती हैं। जो कुछ करना चाहिए था वह नहीं किया और अभी मात्र चार महीने पहले ही हमारी सरकार बनी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार जो गड्ढे, खाई और कुएँ खोद कर गई है, उनको भरने के लिए समय नहीं देना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहता हूँ कि वे हाउस में भाषण न दें सिर्फ बजट पर ही चर्चा करें। (शोर एवं व्यवधान) कांग्रेस सरकार के समय में जो कुएँ सूख चुके हैं उनमें पानी डालने का काम तो हमारी सरकार को ही करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही कहना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, कुएँ और गड्ढों की बात न की जाये। हरियाणा प्रदेश का विकास करके दिखायें। आपने भातनहेल गाँव में मिलिट्री स्कूल की बात कही। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, स्कूल बनाने के लिए गाँव की 273 एकड़ जमीन दी थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलिट्री स्कूल बनाने के लिए वर्ष 2003 में जिस पत्थर की नींव रखी गई थी आज वह पत्थर ही गायब है। वहाँ पर स्कूल भी नहीं बनाया गया (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, श्री दलवीर सिंह सुहाग जी 14 मार्च को झज्जर में आये। झज्जर वासियों और गाँव वालों ने उनसे बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो पिछली सरकार ने किया कोई बात नहीं हम आपके गाँव में सैनिक स्कूल बनाने का काम करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री दलबीर सिंह सुहाग जी सैनिक स्कूल में रैली में भाग लेने के लिए आये थे। उनको यहाँ आने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निमंत्रण दिया था। वे इनके कहने पर नहीं आये थे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि गाँव मातनहेल का सैनिक स्कूल रेवाड़ी जिले में शिफ्ट कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूँ कि इनकी सरकार के समय में क्या किया था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री धनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय,मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है। मैं माननीय सदस्या से कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष : धनश्याम सर्राफ हाउस में बोलने के लिए पहली बार खड़े हुए हैं उन्हें भी बोलने का मौका देना चाहिए।

श्री धनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007 में हुड्डा साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान भिवानी के अन्दर 12वीं कक्षा तक की लड़कियों के लिये स्कूल बनाने की घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2009 से 2014 तक विधानसभा के हर सत्र में लगातार आवाज उठाता रहा था परंतु वर्ष 2014 में माननीय सदस्या ने जो उस कार्यकाल के दौरान शिक्षा मंत्री थी, स्कूल बनाने से साफ मना कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की घोषणाएं पिछली सरकार में होती थी।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन पर स्कूल बनना था वह जमीन गांव के जोहड़ की थी, इसके अलावा कहीं और जमीन उपलब्ध न होने के कारण भिवानी बोर्ड में ही वह स्कूल शुरू कर दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी बार-बार खड़े होकर मुझे यह कह रहे थे कि क्या किया है? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक 260 पेज की रिपोर्ट है। मैं आपके माध्यम से सदन में इस रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूँगी कि शिक्षा के अधिकार को लेकर सैन्ट्रल एडवाईजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो हॉयर एजुकेशन की बॉडी है उसमें शिक्षा के अधिकार को लेकर चिन्ता व्यक्त की गई कि बच्चों को फेल नहीं कर रहे हैं, जिससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र स्तर पर जब नॉन डिटेंशन पॉलिसी आई मुझे खुशी हुई कि मुझे उस सब-कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। देश के ज्यादातर राज्यों में स्वयं विज़िट करके, उनकी रिपोर्ट लेने के बाद इस रिपोर्ट को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी को सौंपी है। अध्यक्ष महोदय, यह सैन्ट्रल एक्ट है। यहाँ पर इन्होंने खड़े होकर कह दिया कि हमने पेपर शुरू कर दिये हैं, हम पेपर शुरू नहीं कर सकते। सी.सी.ई. में पहले भी प्रोविजन था। कंटीनुअस एण्ड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूशन स्तर पर मूल्यांकन तो कर ही सकते थे क्योंकि यह सैन्ट्रल एक्ट है जब उसमें अमैंडमैंट होगी तभी लागू होगी। जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो उस समय के केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि यह बिल्कुल गलत परम्परा है कि हम किसी बच्चे को फेल या पास नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कि तीसरी कक्षा में भी स्क्रीनिंग टैस्ट होना चाहिए, पांचवीं कक्षा का भी टैस्ट होना चाहिए और आठवीं कक्षा में पुनः बोर्ड टैस्ट होना चाहिए ताकि दसवीं कक्षा के बोर्ड के नतीजे जो खराब आ रहे हैं, वे अच्छे आएं। उसकी हम सबको चिन्ता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, उस समय तो केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ज्ञान चंद जी, प्लीज बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जब भी हमारी महिला सदस्या बोलती है तो माननीय सदस्य महिला की तरफ न देखकर चेयर की तरफ देखकर बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैडम, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ-साथ समय भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जल्दी वाइंड अप कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, जब कमेटी गठित हुई चाहे वह पंजाब की बात हो, चाहे वह हिमाचल प्रदेश की बात हो और चाहे किसी भी प्रदेश की बात हो सभी ने इस बात का खण्डन किया। मंत्रियों के समूह के साथ मीटिंग करके रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, इसलिए इसको शिक्षा के अधिकार के कानून के साथ करवाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्किल्ड हरियाणा की बात की गई उसके लिए हमने नेशनल एजुकेशन फ्रेम वर्क शुरु किया। जो नेशनल बोकेशनल एजुकेशन फ्रेम वर्क है इसमें Haryana is a piloting State in the country जिसे हमने 40 स्कूलों के साथ शुरू किया था। उसके बाद उसे 200 स्कूलों में लेकर गये लेकिन सरकार ने 250 स्कूलों में बढ़ाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि जो हमारी कांग्रेस सरकार में ऑल इण्डिया इंस्ट्रीयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पार्ट-टू झज्जर में शुरू हो चुका है, उसको आगे बढ़ाने का काम शुरू करें, जो केन्द्र से आई.आई.टी. एक्सटैंशन सैन्टर लेकर आये थे, उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए, जो आई.एम.टी. सैन्टर लेकर आये हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए और जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अध्यक्ष महोदय, चार-चार मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं यदि उनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बजट में प्रावधान करके समस्या को दूर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सोशल सैक्टर सबसे महत्वपूर्ण सैक्टर है। हमारे प्रदेश का अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग और मायनोरिटी के बारे में भाई नसीम अहमद जी ने जिक्र किया था। प्रदेश सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में एक एफीडेविट दे दिया कि We don't require any minority commission in the State. अध्यक्ष महोदय, फिर मायनोरिटी की रक्षा कौन करेगा? सरकार मायनोरिटी कमीशन भंग कर देगी, इसी तरह से सरकार एस.सी. और बी.सी. स्टेट कमीशन भंग कर देगी और सरकार ने मायनोरिटी कमीशन को भंग कर दिया है। सरकार फिर भी मॉयनोरिटी कमीशन को भंग करने की जरूरत को नहीं बता रही है। सरकार इस कमीशन को कायम रखने का काम करे। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्या बजट के ऊपर चर्चा न करते हुए एस.सी., बी.सी. और मायनोरिटी कमीशन की बात कर रही है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मेवात डिवैलपमैंट एजेंसी की पिछले दो साल में कोई एक मीटिंग भी नहीं हुई हैं, यह बात नसीम अहमद जी अच्छी तरह से बता सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यह एक संवैधानिक रिक्वायरमेंट है। एक कमेटी ऑन शिड्यूल्ड कास्ट और उसके ऊपर ही (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, ये मॉयनोरिटी वैलफेयर की बात करते हैं। उसके बाद एक कमेटी शिड्यूल्ड कास्ट के ऊपर एट्रोसिटीज के ऊपर मानीटरिंग करने का काम किया है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित होकर उसकी मॉनिटरिंग करते थे, इनको 2 साल से मीटिंग करने का समय ही नहीं मिला है। यह काम हमें करना पड़ा है। आप जो ये माइनोरिटिज और एस.सी. वेलफेयर की बातें कह रही हैं ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये करने की नहीं हैं। आप सिर्फ भाषण दे रही हैं लेकिन हम आपको रिकॉर्ड की बातें बता रहे हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने विजिलेंस कमेटी मानीटरिंग ऑन एस.सीज. की बात कही है। जब देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी तो उसी समय यह मीटिंग शुरू हो गई थी। ये मीटिंग्स लगातार होती रहती हैं। आप अपने पड़ोसी राज्य से पूछिये जहां ये चीजें होती रहती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या गलत बयानबाजी कर रही हैं। ये मीटिंग नहीं हुई थी। हम रिकॉर्ड की बात कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात के बारे में अपने रिप्लाई में बता दें। मैं महिलाओं के हित की बात करती हूं। (शोर एवं व्यवधान) आज हमारी बहन को महिलाओं की बड़ी चिंता हो रही है। हमने आंगनबाड़ी वर्कर्ज और हैल्पर्स को उच्चतम मानदेय देने का काम किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अगर आप मंत्री हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष जी, महिलाएं तो दोनों ही तरफ की बराबर और सम्माननीय हैं फिर चाहे इधर की हों या उधर की हों। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय कविता जी हमारी तरफ देखकर फिर बोलना शुरू कर देती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : आप अपनी ****** में रहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल ने अभी जो टिप्पणी की है उसे रिकॉर्ड न किया जाए।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने माननीय मंत्री पर अभद्र टिप्पणी की है इसलिए आप उनसे माफी

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

मंगवाइये। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वे माननीय मंत्री जी से माफी मांगे और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न करें। माननीय सदस्य को माफी मांगनी पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, आप एक सीनियर मेम्बर हैं और आपको इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, इनको अपनी टिप्पणी के लिए माननीय मंत्री से सदन में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, आपने बहुत गलत बात कही है इसलिए आपको माननीय मंत्री से माफी मांगनी चाहिए। हमने आप जैसे सीनियर मैम्बर्स को ऑरियनटेशन प्रोग्राम में इसलिए बुलाया था कि आप नये सदस्यों को बताएं कि सदन में उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष जी, अगर हमारे द्वारा इनके सदस्यों की तरफ देखने से इन्हें इतनी ही दिक्कत है तो ये सदन से बाहर चले जाएं। फिर इनकी तरफ कोई नहीं देखेगा। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह बात धमकाने के लहजे में कही है और इस प्रकार इन्होंने सदन में एक माननीय सदस्या का अपमान किया है। उनको अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष जी, आप इनसे माफी मंगवाइये। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, इनको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये महिलाओं के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आपने सैशन शुरू होने से कुछ दिन पहले सभी विधायकों को विशेष रूप से सीनियर सदस्यों को एक वर्कशॉप लगाकर बुलाया था और उस वर्कशॉप में आपने सीनियर मैम्बर्स को यह जिम्मेदारी दी थी कि वे नये सदस्यों को नैतिकता का पाठ पढ़ायें और उन्हें बताएं कि सदन में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उस प्रोग्राम में वहां पर इन सब बातों पर खुलकर चर्चा की गई थी। चूंकि माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल स्वयं संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं और ऑरियनटेशन प्रोग्राम में इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सारी बातों पर चर्चा की थी और कहा था कि नये साथियों को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। माननीय सदस्य ने बताया था कि सदन में किस तरह से सदस्यों को इज्जत और तमीज के साथ और बिना किसी टीका-टिप्पणी के अपनी बात रखनी चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है कि जो व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा था आज वह एक महिला सदस्य पर इस तरह की भद्दी टिप्पणी कर रहा है। इस टिप्पणी के लिए कर्ण सिंह दलाल को हाउस में खड़े होकर माननीय मंत्री से माफी मांगनी चाहिए। मैं सदन के नेता से कहना चाहूंगा कि वे इस मामले में एक्शन लें। अगर वह सदस्य माफी नहीं मांगता है तो फिर उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आज ही इस सदन में लेकर आयें। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में एक बात कहना चाहूंगी कि क्या सम्मानित सदस्य ने चेयर को सीधा एड्रेस करके कहा कि महिला मंत्री हमारी विधायक को देख रही हैं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट एड्रेस करके कहा कि आप उधर देखकर बात कीजिए। पहले तो माननीय सदस्य यह बतायें कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। अध्यक्ष महोदय, आप यह बताईये कि इधर की महिला और उधर की महिला में क्या फर्क है। उसके बाद माननीय सदस्य ने मुझ पर अभद्र टिप्पणी की है। इसलिए माननीय सदस्य या तो सदन में माफी मांगे या इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो यह माहौल बना है इस को आप भी देख रहे हैं। मैं हमेशा प्रत्येक माननीय सदस्य को यह कहता हूं कि आप चेयर को एड्रेस करके अपनी बात कहें बजाए उसके कि जो मैम्बर बोल रहा है उसको आप सीधे तौर पर कुछ बात कहें । ऐसा करने से एक प्रकार से तनाव का माहौल बनता है। माननीय मंत्री महोदया ने बैठे बैठे ऐसा कहा है और मैंने किसी बदभावना से यह बात नहीं कही। मैंने यह बात केवल माननीय मंत्री महोदया के लिए नहीं कही बल्कि मैंने तो यह बात सभी माननीय सदस्यों के लिए कही थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया उनका मतलब लिमिटेशन होता है। अंग्रेजी में इसे लिमिटेशन कहते हैं और यह उर्दू का शब्द है इसमें क्या गलत है ? सर, इसके लिए मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। आप इस शब्द को डिक्शनरी मंगा कर देख सकते हैं कि इसमें क्या गलत है। हमारा मतलब तो यह होता है कि सदन ठीक चले। न रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य सदन में कोई गलत बात करें और न ही हम कोई गलत बात करें। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में पर्दा डाल दिया जाए ताकि माननीय सदस्य की तरफ देखा ही न जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन की नौंवी बैठक चल रही है। सदन 9.3.2015 को शुरू हुआ था। मुझे यह लग रहा था कि इस बार के सत्र में सदन बहुत अच्छे माहौल में चल रहा है। इसमें अच्छा विनोद भी है और इसमें सभी सदस्यों का और सभी पार्टियों का सहयोग है। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि सीमा का उल्लंघन शायद ज्यादा होने लग जाता है। मुझे लग रहा था कि एक अच्छा आनन्दमय वातावरण है। आपस में सदस्यों में वाद-विवाद भी होते हैं, एक दूसरे सदस्य के साथ मजाक भी होता है। लेकिन कभी कोई ऐसा शब्द आ जाए जिससे किसी माननीय सदस्य की भावना को ठेस पहुंचे। इसके बारे में मैंने पिछले सत्र में भी कहा था और यह बात मैंने माननीय सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के कहने पर कही की। हुड्डा जी ने कहा था कि सदन में थोड़ा व्यंग्य होना चाहिए इससे एक हंसी मजाक का वातावरण होता है ताकि माननीय सदस्यों में कोई तनाव न आये। मैंने उनकी उस बात को ऐप्रीसिएट किया था। इसके साथ ही मैंने यह भी कहा था कि जहां कहीं उपहास की बात शुरू होती है तो वहां सीमा टूट जाती है। इसलिए कभी भी किसी माननीय सदस्य का उपहास उड़ाने के नाते कोई शब्द सदन में प्रयोग होता है तो वह सीमा टूट जाती है। इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल से आग्रह करूंगा कि कम से कम जिस शब्द का उपयोग उन्होंने किया है अगर वह शब्द आनन्दमयी होता, विनोदमय होता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन गुस्से की भावना में ऐसा शब्द प्रयोग होता है और जिस तरीके से वह शब्द कहा गया है वह ठीक नहीं था। इसलिए मैं दलाल साहब से कहूंगा कि वे इस शब्द के लिए खेद प्रकट करेंगे तो उनका बड़प्पन

होगा और अगर खेद प्रकट नहीं करते हैं तो कम से कम उस शब्द को वे वापिस ले लें अगर वापिस ले लेंगे तो मैं उनकी बात को मानूंगा कि इन्होंने ठीक किया है। अगर ये इस शब्द को वापिस नहीं लेते हैं तो फिर सदन की अगली कार्रवाई की जायेगी।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बात कहें तो सदन का कोई सदस्य बुरा नहीं मानता। लेकिन अभय चौटाला जी जैसे नेता हमें पाठ पढ़ाने की बात करें जो इस सदन में बैठकर मां बहन की गालियां दिया करते थे। क्या अब ये हमें सबक सिखायेंगे (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप इस बात को ठीक करने की बजाए और बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। आप बैठिये, वित्त मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन में सदन के नेता ने इतनी बड़ी बात कही है। इस सदन में 90 विधायक चुनकर आये हैं और सभी 90 के 90 विधायक सम्मानित सदस्य हैं और उनके लिए माननीय सदस्य "इनके जैसा, उनके जैसा" इस प्रकार के शब्द व्यक्त करके संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य उन शब्दों को वापिस लें।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को सदन में माफी मांगनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, दलाल साहब ने वह शब्द वापिस ले लिया है।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वांयट ऑफ ऑर्डर पर बोलने के लिए उस वक्त खड़ी हुई थी जब माननीय सदस्या बार-बार यह कह रही थीं कि उनके समय में रेगुलर बैठक होती रही। मैंने कहा था कि एस.सी. एक्ट के तहत जो बैठक होनी थी, वह अप्रैल, 2013 के बाद अभी कुछ दिन पहले हमने की है तथा उसके बीच में कोई भी बैठक नहीं हुई। मैं केवल यही बात कहने के लिए खड़ी हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को जरूर कहना चाहूंगी कि वे बहुत अच्छे ढंग से कार्य करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन मेरे जिला झज्जर की सभी आंगनवाड़ी वर्कर्ज़ ने अपनी समस्याओं के समाधान हेतु धरने, जलूस व प्रदर्शन आदि किये तथा ज्ञापन भी दिये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गीता भुक्कल जी, कृपया आप अपनी बात 2 मिनट में वाइंड अप करें।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात 2 मिनट में ही समाप्त कर लूंगी लेकिन कृपया आप सामने वालों को रोक लेना। मैं कह रही थी कि झज्जर में आंगनवाड़ी वर्कर्ज़ ने धरने, जलूस, प्रदर्शन आदि किए तथा ज्ञापन दिये। माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के निवास के बाहर भी धरना, प्रदर्शन किया और उनको ज्ञापन भी दिया क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। (विघ्न) मैंने बार-बार इस बारे में माननीय मंत्री महोदय से भी प्रार्थना की है कि मेरे झज्जर हल्के की आंगनवाड़ी वर्कर्ज़ को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी उनको तनख्वाह नहीं मिली है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है ? (शोर एवं व्यवधान)मैंने कई बार माननीय मंत्री महोदया को इस बारे में कहा और इनके पास ज्ञापन भी आये। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाहती हूं। माननीय सदस्या गलत ध्यान दे रही हैं कि इस बारे में इन्होंने मुझे बार बार कहा है। इन्होंने मुझे कई बार नहीं कहा है। आज दोपहर के भोजन पर माननीय सदस्या मुझे मिली थीं उस समय इन्होंने मुझे इस बारे में बताया। मैंने उसी वक्त डायरैक्टर को टेलीफोन कर दिया था तथा आदेश दिये थे कि जब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्ज़ को तनख्वाह दी जा रही है तो झज्जर में आंगनवाड़ी वर्कर्ज़ को तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है। (विघ्न) आज ही माननीय सदस्या ने मुझे इस बात की जानकारी दी जिस पर मैंने तुरंत कार्रवाई कर दी है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, यह ब्यानबाजी की बात नहीं है। मैं सोशल सैक्टर पर अपनी बात सदन में रख रही थी। उसमें माइनौरिटीज व अनुसूचित जाति के वर्गों का जिक्र हुआ। हमारी सरकार के समय में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के 19,72,011 विद्यार्थियों को स्कालरशिप मिल रही थी। हमारे समय में भी यह दिक्कत आई थी क्योंकि गरीब किसान का बच्चा स्कूल में पढ़ता है। ये गरीब लोगों के बच्चे हैं इसलिए उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, इनके लिए बज़ट में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि वे इन गरीब वर्गों के बच्चों को स्टाईफंड व स्कॉलरशिप देने का काम जरूर करें। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी या तो उन्होंने या माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उन्होंने गरीब वर्ग के लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट देने का कार्य किया था तथा इस स्कीम के तहत करीब 3,84,000 लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट हरियाणा राज्य में दिये गये हैं जिनमें से लाखों लोगों की रजिस्ट्री होना अभी शेष है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे इस बात का संज्ञान अवश्य लें तथा गरीब लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट रैगुलर बेसिज़ पर मिलने चाहिएं। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए प्रियदर्शनी आवास योजना शुरू की थी जिसके तहत 2 लाख लोगों के लिए मकान बनवाये जाने थे। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा आवास योजना के तहत मकानों की किश्त दी जानी थी। पहली किश्त हमारी सरकार ने दी थी जिसकी दूसरी किश्त उनको अभी तक नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई भूमि अधिग्रहण की बात करता है तथा कोई सी.एल.यू. की बात करता है लेकिन मैं बी.पी.एल. परिवारों की बात कर रही हूं। उनके कल्याण के लिए बज़ट में प्रावधान अवश्य होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार का अनुसूचित जाति वित्त एंवम् विकास निगम है जिससे गरीब लोग लोन लेते हैं। गरीब लोगों ने इस वित्त निगम से लोन लिया है तथा जब गरीबी की वजह से वे लोन की अदायगी नहीं कर पाये तो उस समय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी एक कलम से उनके 154 करोड़ रुपये के ब्याज समेत कर्जे माफ करने का काम किया था जिससे हमारे प्रदेश के 1,64,000 परिवारों को लाभ हुआ है। अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ देश की बात की जा रही है, यह बहुत अच्छी बात है। स्वच्छ हरियाणा की बात की जा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। स्वच्छता देश की प्राथमिकता है। यहां सदन में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, उनका हम आदर करते हैं। हमारी सरकार ने 11,000 सफाई कर्मचारी हरियाणा में लगाये थे जिनको 8100/- रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता था लेकिन वर्तमान सरकार सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं दे पा रही है। मेरे हल्के झज्जर में सफाई कर्मचारियों को हटा दिया गया है। आज प्रदेश में क्या सफाई व्यवस्था है ? वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। एम.एल.ए. फ्लैट्स का भी यही हाल है

इनमें तो हमारे विधायक रहते हैं। सफाई कर्मचारी एक तरफ झाड़ू लगाकर अपना काम पूरा किया समझता है। उसको लगता है कि कोई बड़ा अधिकारी अथवा नेता आयेगा और खुद सफाई कर लेगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि हरियाणा प्रदेश में सफाई व्यवस्था प्रॉयोरिटी पर अच्छे ढंग से होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भुक्कल जी, आपको बोलने के लिए जो समय दिया गया था, आप उससे 25 प्रतिशत समय ज्यादा ले चुकी हैं। आपका 17 मिनट से भी ज्यादा समय हो गया है। बाद में आप कहेंगी कि आपको बोलने ही नहीं दिया गया। कृपया आप वाइंड अप करें।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। पैंशन की यहां बार बार बात आई इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों को जिस समय 2005 में सत्ता मिली थी उस समय पैंशन 250 रुपये थी। उसके बाद 300 रुपये की घोषणा हुई और हमने 300 रुपये पैंशन की, फिर 300 से 500 रुपये और फिर 500 से 750 रुपये, 750 रुपये से 1000 और फिर 1500 रुपये पैंशन हमने की। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 2000 रुपये पैंशन देने का वायदा करके हरियाणा की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया है। सरकार ने केवल 1200 रुपये पैंशन देने का काम किया है तथा जीरो से 18 साल तक के निशक्त बच्चों को जो हम 700 रुपये पैंशन देते हैं उसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि उन बच्चों को भी 1200 रुपये पैंशन देने का काम करें।(शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री(कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह सी.एल.पी. की लीडर साहिबा जी अपने बगल में बैठे सदस्य को स्मरण करा रही थी कि पांचवे साल में पैंशन मत बढ़ाना। अध्यक्ष महोदय, इनका 10वां साल था और उस समय पैंशन 750 रुपये थी। लोक सभा के चुनाव नजदीक थे इसलिए इन्होंने पैंशन 1000 रुपये कर दी। उस समय सभी को मालूम था, दीवारों पर लिखा था और आसमान में साफ लिखा था कि हमारी सरकार नहीं आ रही और लोक सभा के चुनावों में इनको समझ आ गया था कि हारी हुई फौजें जाते हुए जोहड़ में जहर मिलाया करती हैं। उस सोच के साथ इन्होंने कभी एक पैसा दिया ही नहीं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने घोषणा पत्र के वायदे को लागू करते हुए बुजुर्गों की पैंशन को 1200 रुपये भी किया और 2000 रुपये तक का रोड मैप हमारी सरकार ने स्पष्ट किया। अध्यक्ष महोदय, क्या ये रोड मैप देकर गए थे। हम तो यह कहते हैं कि ये लोग जनता से झूठे वायदे करके गए थे। मुख्यमंत्री होते हुए झूठी घोषणाएं करते रहे उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है और ये हमें कहते हैं कि हमारे वायदे झूठे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास अभी 5 साल का समय है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री.भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारे मैनीफैस्टो को देखें तो उसमें हमने कहीं कोई ऐसा वायदा नहीं किया, जो वायदे हमने किए थे हमने उनको पूरा किया है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो बुजुर्गों को 2000 रुपये पैंशन देने का वायदा किया था और उस वायदे को करके आपने जनता से वोट लिए हैं। हम वायदे नहीं करते बल्कि हमने तो काम करके दिखाया है इसलिए आपने जो वायदा किया है आप उसको पूरा करें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी जैसे बहुत वरिष्ठ सदस्य और बहुत से अनुभवी लोग यहां बैठें हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम इनसे बहुत सी अच्छी चीजें भी सीखते हैं लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी सीखतें हैं जो नहीं होनी चाहिए। 5 सालों का कार्यकाल हमारे पास है और हम 5 सालों में एक एक वायदे को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं, आप भी यहां होंगे और हम भी यहां होंगे।

श्री अनिल विज : कैप्टन साहब, आप किनकी बात कर रहे हो, हुड्डा साहब ने तो झूठ बोलने के लिए पी.एच.डी. कर रखी है। इन्होंने वायदा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है वह 24 घंटे बिजली, इन्होंने वायदा किया था कि हम हाउस टैक्स माफ करेंगे, कहां किया है माफ ? इन्होंने प्रोपर्टी टैक्स लगा दिया इसलिए जितना इन्होंने प्रदेश को गुमराह करने का काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) आप इनकी बातों का क्यों जवाब देते हो क्योंकि इन्होंने तो झूठ बोलने की पी.एच.डी. कर रखी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारा घोषणा पत्र निकाल लीजिए जो सच्चाई है वह सामने आ जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता भुक्कल जी, आप एक मिनट में अपनी बात कम्पलीट कर लें क्योंकि आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो घोषणा पत्र दिया उसको निकाल कर देख लें। जुमले पत्र निकाल कर देख लें, 169 जुमले थे उनके बारे में तो बजट में कहा ही नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि लोगों ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आपको बहुमत दिया है आप अच्छे ढंग से सरकार चलाएं। मुझे खुशी होती है जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और 21 जिलों का समान विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगी कि झज्जर जिला जो एन.सी.आर. में आता है। एन.सी.आर. में बहुत तरक्की हुई चाहे गुडगांव की तरक्की हुई, चाहे सोनीपत की हुई या फरीदाबाद की तरक्की हुई लेकिन हमारा झज्जर क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी साथी सदस्या और कांग्रेस के विधायक साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या यह जुमला शब्द 24 अकबर रोड से इम्पोर्ट होकर आया है। (हंसी) किरण जी और दूसरे कांग्रेस के माननीय सदस्य जुमला शब्द बहुत यूज कर रहे हैं, हुड्डा साहब बोलते हैं तो जुमला शब्द बोलते हैं। (विघ्न) शर्मा जी के यह बात समझ नहीं आ सकती। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें तो जुमला शब्द की जानकारी नहीं थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है तब से जुमला शब्द का पता चला है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय लूंगी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैडम, प्लीज आप बैठें। आपका धन्यवाद मैंने स्वीकार कर लिया है। अब श्री असीम गोयल जी बोलेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : गीता भुक्कल जी मेरी परमिशन के बगैर जो कुछ बोल रही हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री असीम गोयल (अम्बाला सिटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय सदस्या से भी निवेदन करूंगा कि सदन में जो नये सदस्य चुनकर आये हैं उनके बोलते समय व्यवधान न डालें। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि-

खुदा करे कि सलामत रहे हमारी हिम्मत,

यह चिराग कई आंधियों पर भारी है।

अध्यक्ष महोदय, जो बेहतरीन बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने कल सदन में प्रस्तुत किया है उसके लिए इनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। यह बजट प्रदेश की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और प्रदेश के मूलभूत ढ़ांचे की रीढ़ को सुदृढ़ करने वाला बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं शब्दों के अंदर अपनी बात की अनुभूति को बता नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह पहला बजट प्रदेश में है जो कि अभूतपूर्व रूप से जनता से जुड़ा हुआ बजट है। मौजूदा बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विपक्ष के साथियों ने भी बजट में कोई कमी नहीं निकाली है बल्कि यह चिंता जाहिर की है कि यह बजट लागू कैसे किया जायेगा। बजट में विपक्ष के साथी कोई कमी नहीं निकाल पाये जो कि बजट की सार्थकता को प्रूव करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की जो वर्तमान चुनौतियां हैं उनसे इसी प्रकार की नीतियों से पार पाया जा सकता है जिस प्रकार की बातें बजट में की गई हैं। यह बजट सरकार की सच्ची और अच्छी नीयत का आईना है। इसके लिए मैं पुन : मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। पहले प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रीय असंतुलन, भाई भतीजावाद और राजनैतिक द्वेष की भावनाएं थी उनसे हटकर यह बजट वित्त मंत्री जी लेकर आये हैं। यह बजट प्रदेश के आम आदमी को खुशहाल करने वाला जन-जन का बजट है। अध्यक्ष महोदय, पिछली घोषणाओं वाली सरकार के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि-

इतना भी प्यार किस काम का,

भूलना भी पड़े तो नफरत की हद में जाना पड़े।

पूर्व की सरकार ने सोच लिया था कि उनका जनादेश परमानैंट हो चुका है। वे किस प्रकार की घोषणाएं करते रहे उसकी वायबिलिटी है या नहीं उसकी तरफ कोई ध्यान नही दिया। उस समय में असमान और असंतुलित विकास प्रदेश का किया गया। यही वजह रही कि जनता ने उनको आईना दिखा दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा विपक्ष के साथियों से अनुरोध है कि सच्ची बात को बहादुरी से स्वीकार करना वीरता की बात होती है इसलिए वे सच्ची बातों को धारण करने का माद्दा बनायें।

18.00 बजे इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता सेठ की भूमिका में है और इस प्रदेश की सरकारें मुनीम की भूमिका में हैं। पिछली सरकार ने अपनी मुनीम की भूमिका को निभाते हुए जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता के विश्वास को तोड़ा और जिस प्रकार से आम जन मानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया उसका खामियाज़ा तो पिछली सरकार भुगत चुकी है हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछली सरकार द्वारा पैदा की गई कमियों को दूर

[श्री असीम गोयल]

करने के लिए और पैदा की गई समस्याओं को जड़ से दूर करने के लिए एक बड़ा ही संतुलित बजट यहां पर प्रस्तुत किया है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से एक विशेष निवेदन है वे मेरी बात को ध्यान से सुन लें कि इन्होंने जो पूरे प्रदेश का श्वेत पत्र अभी जारी किया है वह तो ठीक है लेकिन मैं यह चाहता हूं कि ये हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक हल्के का एक श्वेत पत्र जारी करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने पूरे प्रदेश का श्वेत पत्र अभी जारी किया है उससे पिछली सरकार की पूरी तसल्ली नहीं हुई है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि हल्कावाईज़ श्वेत पत्र शीघ्रातिशीघ्र जारी किया जाये ताकि प्रदेश की जनता को बड़े विस्तार से पता चल सके कि पिछली सरकार ने पिछले 10 सालों के दौरान किस प्रकार के काम किस प्रकार से करने का काम किया है। (विघ्न) स्पीकर सर, हमें सबसे ज्यादा हैरानी तो उस समय होती है जब हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य उठकर कहते हैं कि हमारे हल्के की सड़कें टूटी हुई हैं। हमारे यहां स्कूल नहीं बना और हमारे यहां हॉस्पिटल नहीं बना। यहां कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया कि हमारे यहां घोषणायें तो हुई और पत्थर भी लगे लेकिन उससे आगे कोई काम न हो सका। ये बातें लगभग सभी कांग्रेसी सदस्यों ने यहां पर बोली हैं। कल श्री ललित नागर जी ने अपने हल्के की समस्याओं की एक लम्बी चौड़ी लिस्ट यहां पर पढ़कर सुनाई थी। इसलिए सबसे ज्यादा हैरानी का विषय तो यह है कि किस प्रकार से ये लोग अपने विकास की कहानी यहां पर ब्यान कर रहे हैं। इस बजट के अंदर बिजली, जनस्वास्थ्य, उद्योग और परिवहन के लिए जो 1750 हज़ार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि पूर्व के बजट से 8 प्रतिशत अधिक है। यहां पर परिवहन का विषय आया है इसलिए मैं अपने हल्के की बात करना चाहता हूं जैसा कि मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने वक्तव्य में भी जिक्र किया था कि अम्बाला शहर एक सुपर सी.एम. का हल्का होने के कारण उनके द्वारा कई सौ करोड़ रुपये की घोषणायें यहां पर करवाई गई लेकिन वास्तव में वे एक बस स्टैंड भी नहीं बनवा पाये। इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से और माननीय परिवहन मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे हमारी बस स्टैंड की वर्षों पुरानी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करें क्योंकि हमारी सरकार आने के बाद से ही अम्बालावासियों के मन में यह आस जगी हुई है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एक अदद बस स्टैंड मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्कूलों के बारे में बात करना चाहता हूं। अम्बाला शहर के सैक्टर 9 का एरिया सबसे पॉश एरिया माना जाता है। वहां पर 3-4 एकड़ के अंदर स्कूल बना हुआ है और लगभग 3-3 फुट तक उस स्कूल के अंदर पानी खड़ा है। उस स्कूल के कमरों में खिड़की, दरवाज़े और शीशे तक नहीं हैं। वहां पर सफाई के लिए केवल मात्र दो लोग हैं और जो पिछली सरकार ने चार साल पहले वहां पर एक बिल्डिंग बनाने की घोषणा की थी उसका सारे का सारा मैटीरियल अभी तक बाहर पड़ा है लेकिन अभी तक उसका कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे ही दुर्गा नगर का स्कूल है और ऐसे ही नसीमपुर का स्कूल है वहां पर मैंने स्वयं जाकर देखा कि पीने के पानी की टंकी के अंदर कबूतर मरे पड़े हैं और बच्चे उस पानी को पीने के लिए मज़बूर हैं। ये सारी की सारी बातें पिछली सरकार के विकास के दावे की पोल खोलती हैं। अम्बाला शहर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है इसलिए मेरे हल्के के अंदर एक गवर्नमैंट हॉस्पिटल है जो कि 200 बैड का हॉस्पिटल है। इस समय इसकी आक्यूपैंसी लगभग 160 प्रतिशत रहती है। इस प्रकार से वहां पर बैड कम हैं लेकिन वहां पर मरीज़ ज्यादा आते हैं। पिछली सरकारों ने वहां पर बैड की संख्या बढ़ाने के लिए कभी कुछ नहीं

किया और न ही वहां की समस्याओं पर ही कोई ध्यान दिया लेकिन मैं धन्यवादी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जिन्होंने इस हॉस्पिटल की क्षमता को 200 बैड से बढ़ाकर 300 बैड करने के प्रोसैस को शुरू किया है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि बौडमस्तपुर में एक सी.एच.सी. है जिसकी बिल्डिंग को पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2009 में कंडम घोषित कर दिया गया था। कल मैं वहां पर निरीक्षण करने के लिए चला गया तो मैंने पाया कि वहां पर केवल दो मरीज़ थे और केवल दो मरीज़ों को भी दाखिल करने के लिए उनके पास बिल्डिंग नहीं है इसलिए उनको कॉरीडोर के अंदर एडमिट कर रखा है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि जिस बिल्डिंग को वर्ष 2009 से सरकार द्वारा कंडम घोषित किया गया हो आज तक भी उसके ऊपर काम शुरू नहीं किया गया। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस सी.एच.सी. की बिल्डिंग का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाये ताकि मरीज़ों को ईलाज़ के दौरान पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हो सकें। इसलिए मैं पुन: यह कहना चाहता हूं कि श्वेत पत्र हरेक हल्के का होना चाहिए ताकि पिछली सरकार की कमियां पूरी तरह से जनता के सामने उजागर हो सकें। सरकार ने जो यह बजट पेश किया इसके पीछे इन्टैन्शन यही रही कि नई घोषणाएं न करके जो पुरानी घोषणाएं हैं या जो पुराने होने वाले काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा किया जाये। अध्यक्ष महोदय, पहली बार हरियाणा में शराब के ठेकों की नीलामी में ई-टैंडरिंग का प्रोसैस शुरू किया गया है। ई-टैंडरिंग के प्रोसैस से एक नीट एण्ड क्लीन पॉलिसी बनाई गई। आपस में झगड़े कम हुये। इससे पहले जो शराब के ठेकेदार थे वे आपस में मिल कर ग्रुप बना लिया करते थे और झगड़े होते थे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूँ कि वे नये-नये आये हैं और उनको पता नहीं है। हरियाणा में जो आबकारी नीति हमारी सरकार ने बनाई थी वह सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट थी और आपने भी उसी को आगे बढ़ाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी नीति में ई-टैंडरिंग की बात कर रहा हूँ जो कि पहली बार लागू की गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस कारटल को हमने ही तोड़ा था और हरियाणा में नई आबकारी नीति लागू की थी और जो एंड यूजर्स है जो सबसे छोटा आदमी है उस तक ठेके पहुंचाये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं ई-टैंडरिंग की बात कर रहा हूँ। हमारी सरकार ने जो नई आबकारी नीति बनाई है उससे प्रदेश का रिवैन्यू भी इन्क्रीज हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, इस बहस से एक बात तो अच्छी निकली है। हमारी जो नई आबकारी नीति है उसमें ई-टैंडरिंग तो शुरू हुई है। माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी ने आबकारी नीति के बारे में बताया है कि हमने उनके द्वारा बनाई गई आबकारी नीति को ही आगे बढ़ाया है। जिस समय हमने नई आबकारी नीति बनाई थी उस समय इन्होंने इस नीति की आलोचना भी की थी लेकिन मोटे तौर पर इन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि हमारी आबकारी नीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह जो आबकारी नीति हमने बनाई थी वह कारटलाईजेशन को तोड़ने के लिए बनाई थी। जो दूसरे स्टेट्स ने भी एमूलेट्स की थी और उसको बहुत मेहनत से बनाया गया था। आज हमारी उस नीति की प्रशंसा होनी चाहिए थी। जहाँ तक ई-टैंडरिंग की बात है तो मैं बताना चाहूँगी कि इसको ऑनलाईन करने के लिए 4 साल का समय लग गया था। यह जो जी.एस.टी. वगैरह को ऑनलाईन करने के लिए बहुत मेहनत की है।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की मेहनत को हम यहाँ पर रिवार्ड नहीं दे सकते। इनको जनता ने रिवार्ड दे दिया है। अपनी मेहनत जनता के आगे दिखाते। टैक्सेशन विभाग का पहली बार कम्प्यूटराईजेशन किया गया है और टैक्स क्लैक्शन को ऑनलाईन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये लोग कहते हैं कि घाटा कहाँ से पूरा होगा, और बाद में तो कोई टैक्स नहीं लगाओगे। मैं इस बात के लिए तो इनको आश्वासन नहीं दे सकता लेकिन जो ऑनलाईन टैक्स कलैक्शन है उससे बैटर टैक्स क्लैक्शन होगी और उससे हमारी सरकार को राजस्व घाटा कम करने में मदद मिलेगी। हमारी सरकार ने बायोफर्टिलाईजर पर वैट को माफ कर दिया है। हम जो आर्गेनिक खेती की बात करते हैं और आज के दिन आर्गेनिक सब्जियों का जो ट्रेंड बढ़ा है उसको बढ़ावा देने के लिये सरकार ने एक अच्छी शुरूआत की है। एल.ई.डी. पर और प्रि0 फेब स्टील स्ट्रकचर के ऊपर, पाईप की फिटिंग के ऊपर वैट कम कर दिया गया है। स्टील की पाईप के ऊपर तो पहले ही वैट नहीं था लेकिन जो पाईप की फिटिंग थी उसके ऊपर साढ़े 12 प्रतिशत वैट लगता था उसको कम किया है। इसी प्रकार से अगर मैं एन.सी.आर. की बात करूँ तो हमारी सरकार द्वारा मैट्रो को बहादुरगढ़ तक तथा एक नया स्टेशन द्वारका से गुड़गांव तथा बल्लभगढ़ से गुड़गांव के नये रूट्स स्वीकार किये गये हैं। इसी प्रकार से के.एम.पी. (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रैस हाईवे जो कि पिछले 10 वर्षों से पैंडिंग था जो कि दिल्ली के लिए लाईफ लाईन माना जाता है जिसके बनने से दिल्ली का ट्रैफिक का बोझ कम हो जायेगा। इन सब बीजों को सोचते हुए हमारे देश के महान नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी ने मैट्रो और के.एम.पी. ये दो प्रोजैक्ट लान्च किए थे लेकिन जैसे ही माननीय अटल जी की सरकार गई इस के.एम.पी. प्रोजैक्ट को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। हमारी सरकार ने पुन : इस प्रोजैक्ट का प्रावधान किया। अटल जी के समय में जो एक सर्व स्पर्शी सर्व जन की सरकार बनी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। हमारे देश के महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की केन्द्र की सरकार एक वोट से गिरी तो अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कई सदस्यों के ध्यान में भी हो, लेकिन मैं उस बात की पुनरावृत्ति करना चाहूंगा। उस वक्त जब माननीय अटल जी इस्तीफा देकर आ रहे थे तो उनसे प्रैस के बन्धुओं ने पूछा कि आपके पास तो केन्द्र की सरकार थी फिर भी आपकी सरकार केवल एक वोट से गिरी आप चाहते तो किसी एक विपक्षी सदस्य को केन्द्र का मंत्री बना लेते या उससे कोई और डील कर लेते तो आपकी सरकार बच जाती। उस समय अटल जी ने एक बात कही कि जिस समय रामायण का युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण को मूर्छा हुई सबने कहा कि अगर इसका कोई इलाज कर सकते हैं तो वह सुषैण वैद्य हैं। सुषैण वैद्य को हनुमान जी उठा लाए। सुषैण जी को जब सारा वृतांत पता चला तो सुषैण जी ने केवल एक बात भगवान श्री रामचन्द्र जी को कही कि-

"मैं वैद्य दशानन के घर का, किस तरह तुम्हारा कर्म करूं, सोच रहा हूं कि किस तरह ये अधर्म करूं।" तो भगवान श्री रामचन्द्र जी ने एक बात कही- "जिस धर्म की खातिर धर्म छूटा,

प्यारे पिता का मरण हुआ, घर बार से अपने बिछड़ गया, प्यारी सीता का हरण हुआ। उसी धर्म की वेदी पर लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, पर अधर्म नहीं होने पाए।"

जब भगवान रामचन्द्र जी ने कहा कि लक्ष्मण मरता है तो मर जाए लेकिन अधर्म न होने पाए। तो अटल जी ने कहा वहीं मिसाल आज मैं बनाना चाहता हूं क्योंकि आज जनता ने मुझे इस लोकतन्त्र के मन्दिर का पुजारी बनाकर भेजा है। इसलिए मैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहता जिससे हमारी लोकतन्त्र के इस मन्दिर की गरिमा को ठेस पहुंचे या उसका हनन मेरे द्वारा हो। मैं दोबारा जनता में जाऊंगा और जनादेश लेकर आऊंगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल अटल जी को पूरा जनादेश मिला। इस प्रकार के नेताओं की एक छाप इस सरकार पर है जो इस बजट के अन्दर वह छाप साफ नजर आती है। मैं पुन: इस बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्तमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि जनता की तरफ से उनको दो लाईने सुनाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जनता विपक्ष के माननीय सदस्यों से कह रही है -उन्हें लगता है कि मुझे उनकी चालाकियां समझ नहीं आती, मैं उसे बड़ी खामोशी से अपनी नजरों से गिरते हुए देखता हूं। जो जनता की नजरों से गिर चुके हैं वह किस प्रकार से इस हाऊस में बार-बार खड़े होकर चिल्लाते हैं। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री घनश्याम सर्राफ (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सत्र में बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। माननीय वित मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट यहां प्रस्तुत किया उसमें विकास और सबका सम्मान इस बजट के माध्यम से किया है। यह समदर्शी बजट है और जनहितकारी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बजट दूरदर्शी है जिसके परिणाम अच्छे निकलने वाले हैं। इससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा क्योंकि यह हरियाणा को प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाला बजट है। हमारी सरकार ने जो नारा दिया वह अच्छे दिनों की शुरूआत इस बजट के माध्यम से हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी , इस बजट में सबका ध्यान रखा गया और यह बहुत अच्छा बजट बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, यह एक सर्वांगीण बजट है जो हरियाणा प्रदेश के लिए प्रगति और खुशहाली की लहर लेकर आयेगा। इस बजट में 4 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक की बढोतरी अलग-अलग मदों में की गई है। इसके लिए मैं वित मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में किसी भी वस्तु पर नया टैक्स नहीं लगाया गया है बल्कि कुछ चीजों में वैट हटाने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में माननीय वित मंत्री महोदय ने किया है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से एक बात मेरे ध्यान में आती है कि जो हम सोचते थे कि "सर्व जन हिताय और सर्व जन सुखाय" होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने राज्यों के बजट को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत तक किया है। यह बहुत ही खुशी की बात है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कृषि, सिंचाई योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में खेतों में पानी देने का संकल्प लिया है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी ने पूरी लगन के साथ इस प्रणाली को लागू किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने भिवानी क्षेत्र को पानी 40 प्रतिशत कम दिया था। मेरे पास 5 साल की बाकायदा इसकी रिपोर्ट भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं रोहतक जिले के एक विधायक को पर्सनली मिला और

[श्री घनश्याम सर्राफ]

उनसे बात की कि हमारे इलाके में पानी नहीं आता है तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि जब तक रोहतक की सरकार है तब तक भिवानी जिले को पानी नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या किरण चौधरी जी को बताना चाहता हूं कि यह बात कही गई थी। अध्यक्ष महोदय, कहीं न कहीं माननीय सदस्या भी इस बात के लिए दुखी थी। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, घनश्याम जी ठीक कह रहे हैं।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा कि मेरे पास इसका रिकॉर्ड है मैं रिकॉर्ड के मुताबिक ही बात बता रहा हूं। इस बारे में माननीय सदस्या को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : घनश्याम जी, किरण चौधरी जी भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, महम हल्के में खरकड़ा हैड है उस हैड से भिवानी जिले में पालावास माईनर और बादली डिस्ट्रीब्यूट्री में पानी आता है। उससे पहले ही एक एमरजैंसी चैनल लगा हुआ है जो किसी आपातकाल के समय में या उसमें आदमी के डूब जाने से पानी छोड़ा जाता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय में 10 वर्षों के कार्यकाल में जब तक मैं विधायक रहा हूँ। रोहतक एरिया में ही पानी बराबर चलता रहा और हमारे इलाके का पानी काटते रहे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था उस सरकार में थी। अध्यक्ष महोदय, सड़कों को बनाने के लिए भी इसी तरह की भेदभावपूर्ण नीति हुड्डा सरकार ने अपनाई थी। अध्यक्ष महोदय, एक फोर लेनिंग सड़क रोहतक से भिवानी की ओर आती है, खेरड़ी मोड़ सड़क रोहतक जिले में ही समाप्त कर दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से महम में जो सड़क आती है जहाँ पर रोहतक जिला समाप्त होता है। गाँव सीसर कलानौर के पास स्थित है उसमें सड़क की वाईडनिंग और कारपैटिंग की थी और उस सड़क को वहीं समाप्त कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार भुंढाल के बाद भिवानी की ओर सड़क आती है। उसकी भी दुर्दशा पूरे 10 साल में ऐसी ही रही। यह सब रिकॉर्ड की बाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम गौ-माता का सम्मान करते हैं। इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्त्तव्य है। इसकी पालना करते हुए गौ-संरक्षण में गौ-संवर्धन शुरू किया गया है। एक बात और ऑन दी फ्लोर ऑफ दि हाउस कहना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मेरे से बड़ा कोई गऊ भक्त नहीं है जबकि 15 रुपये प्रति दिन गायों के लिये अनुदान देने की घोषणा मात्र बनकर रह गई थी। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार इसको कैंसिल करवाने तक के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय तक गये, यह बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं गौसंवर्धन और पशु पालन के बारे में कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि पशु पालन के क्षेत्र में हमारी सरकार ने 27.89 प्रतिशत की वृद्धि की है, जोकि पिछली सरकार से बहुत अधिक है। गौ सेवा आयोग की योजनाओं के लिये 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 9.20 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने किये हैं, इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक लेकर आई है और देश में सबसे पहले गौ निषेध के लिए कठोर से कठोर कानून बनाया, जिसकी जानकारी हमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से और माननीय मुख्यमंत्री जी के

माध्यम से प्राप्त हुई है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, गाय के अन्दर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, (इस समय मेजें थपथपाई गई) इसलिए हम गाय को माता का दर्जा देते हैं। सरकार वर्ष 2015-16 में पशु पालन विभाग में 36.30 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पशुपालन एवं डेयरी विभागों के लिए 191.30 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है लेकिन पहली सरकार ने जो बजट पेश किया था वह 130 करोड़ रुपये का था। अध्यक्ष महोदय, बजट में बहुत बड़ी वृद्धि इस बजट में की गई है। हमारी सरकार मत्स्य पालन के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार है और बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में करने जा रही है, पहले बजट में 31.29 करोड़ रुपये का प्रावधान था, वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 48.93 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। योजनागत स्कीमों के लिए 132.77 करोड़ रुपये की वृद्धि सराहनीय कदम है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कांट्रैक्ट बसों को परमिट देने का प्रावधान बजट के अन्दर किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने सभी वर्गों का साथ और सभी वर्गों का विकास का नारा दिया हुआ है। कांग्रेस सरकार ने केवल ए.सी. बसों को ही परमिट दिये थे लेकिन हमारी सरकार ने सभी बसों को परमिट देने की बात कही है, जो बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन में पिछली सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ कि "जो रहबर थे राहबर हो गये" (शोर एवं व्यवधान) वर्ष 2007 में स्कूलों के निर्माण के बारे में मैंने प्रश्न काल के दौरान ही सदन को अवगत करा दिया था। अध्यक्ष महोदय, भिवानी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पहले दौरे के दौरान ही 12वीं कक्षा तक राजकीय कन्या माध्यमिक स्कूल बनाने की घोषणा, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा और चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी को दूसरी बड़ी जगह पर ले जाने की घोषण कर दी। यह यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर स्थापित की गई थी। परंतु कम जगह होने की वजह से हम उसे ज्यादा जगह वाले स्थान पर लेकर जा रहे हैं। मैं यह बात माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी को बताना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी को बताना चाहता हूं कि इन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सौ एकड़ जगह की बात कही थी और मैंने कहा था कि आपके पास जगह नहीं है। यह मेरा क्वेश्चन था। हमारी एक बाईपास के लिए काफी लम्बे समय से डिमांड थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। मैं इस सदन के माध्यम से सिंचाई मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमारे क्षेत्र में दो रजवाहों की ढाल में फर्क है - एक है सांगा माइनर और दूसरी है बड़ेसरा माइनर। मेरी विनती है कि इन्हें यथाशीघ्र ठीक करवाया जाए और नहरों की मरम्मत करवाई जाए। मैंने बिजली और सड़कों की डिमांड मंत्री जी को सौंप दी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सेवाएं तीव्रता से आगे बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र की डिमांड्स मैंने स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री जी को दे दी हैं। मेरे क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। यहां पर उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है। वर्ष 2005 में डॉ. शिवशंकर भारद्वाज विधायक बने थे। उस समय इंडस्ट्रियल एरिया में 14 फ्लैट बचे हुए थे और उन्होंने वे सारे फ्लैट्स अपने रिश्तेदारों को दे दिये और खुद ले लिये थे। उन्होंने वहां की औद्योगिक इकाईयों को खत्म कर दिया था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का एक सुखमय बजट पेश करने के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। हमने पिछले 5 सालों में इस सदन का बड़ा खराब माहौल देखा है। जो माननीय सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष के आसन पर बैठते थे वे हमको बोलने का मौका नहीं देते थे। कभी वे हमको सदन से बाहर कर देते थे और

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY

[श्री धनश्याम सर्राफ]

कभी नेम कर देते थे। वे कभी हमको एक दिन के लिए सस्पैंड कर देते थे और कभी सारे विपक्ष को पूरे सैशन के लिए सदन से एक्सपैल कर देते थे। हमें सदन से बाहर बैठकर अपना आंदोलन शुरू करना पड़ता था और धरना देना पड़ता था। उस समय वे सब चीजें बड़ी चुभने वाली होती थी। आज आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। (विघ्न) अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जय हिंद !

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब यह सदन दिनांक 19 मार्च, 2015 प्रात: 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*18.29 बजे (तत्पश्चात् सदन वीरवार, 19 मार्च, 2015 प्रात: 10.00 बजे तक * स्थगित हुआ।)

53395–H.V.S.–H.G.P., Chd.